ISSN-0971-8397

योजना

विशेषांक

फरवरी 2019 विकास को समर्पित मासिक ₹ 30

बुनियादी ढांचा

सबको बिजली का सपना होता साकार
आर के सिंह

शहरों की कायापलट के लिए बहुआयामी पद्धति
दुर्गा शंकर मिश्र

सबके लिए आवास : सरकार की प्रमुख प्राथमिकता
रंजीत मेहता

विशेष आलेख
अंतर्देशीय जलमार्ग : समन्वित जल परिवहन नेटवर्क
प्रवीर पांडे

फोकस
उड़ान-हवाई संपर्क को नया आयाम
उषा पाढ़ी

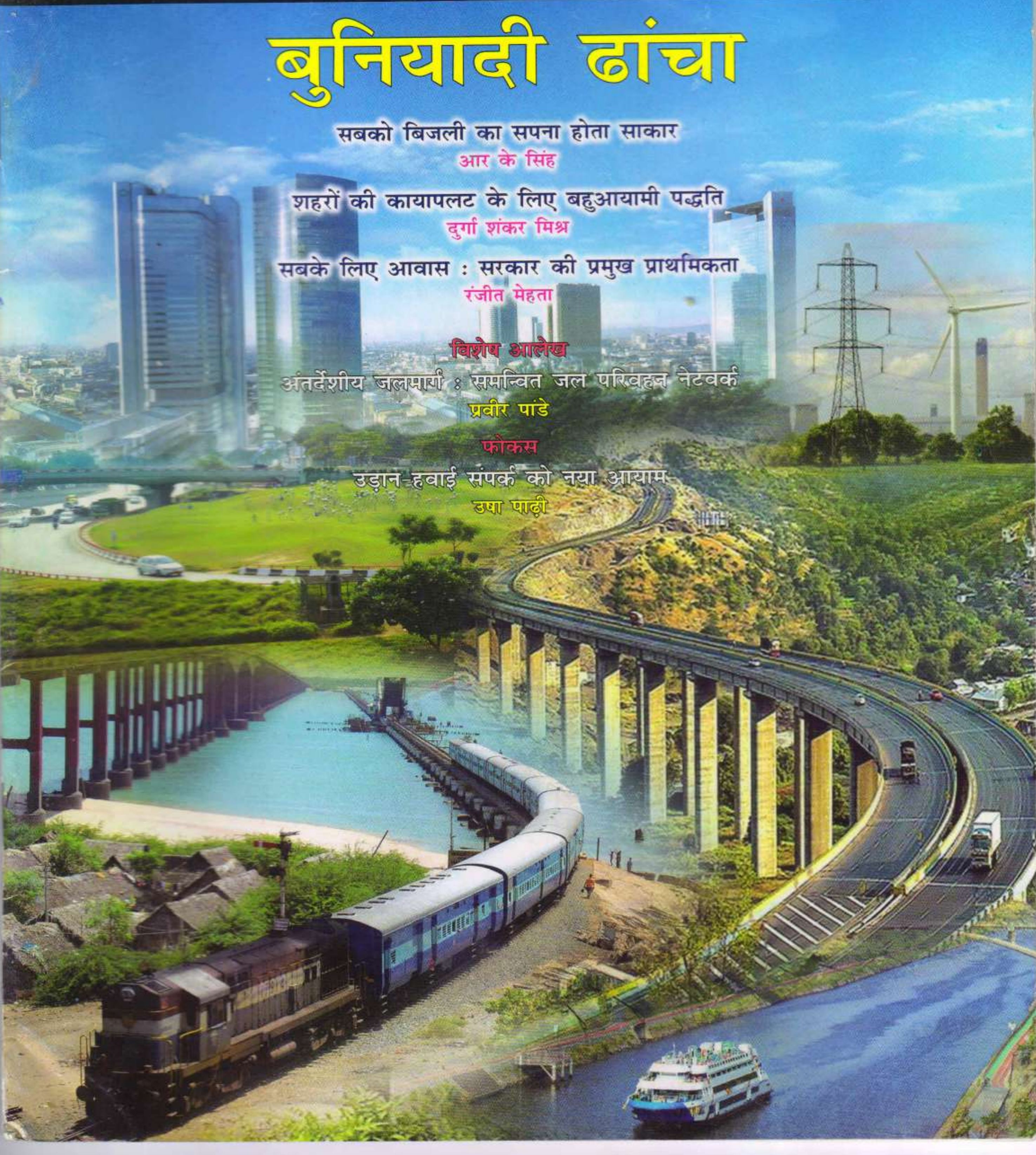

प्रधानमंत्री ने सोलापुर, महाराष्ट्र में कई परियोजनाओं की शुरुआत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जनवरी 2019 को महाराष्ट्र के सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद एनएच-52 राष्ट्र को समर्पित किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी. विद्यासागर राव, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस और अन्य जाने-माने व्यक्ति भी उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के सोलापुर में हाल में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। सड़क परिवहन संपर्क को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग-211 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-52) चार लेन की सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया। सोलापुर-उस्मानाबाद के बीच की इस सड़क को 4 लेन किए जाने से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के अहम क्षेत्रों से सोलापुर का संपर्क बेहतर होगा।

प्रधानमंत्री ने बेहतर संपर्क और जीवन की सहूलियत के लिए राजमार्ग के विस्तार की प्रमुखता पर जोर देते हुए कहा, ''पिछले 4 साल में तकरीबन 5.5 लाख करोड़ रुपये की लागत से 40,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कें बनी हैं और करीब 52,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमाग की सड़कें निर्माणाधीन हैं।'' उन्होंने 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत 30,000 घरों की भी आधारशिला रखी। इससे मुख्य तौर पर कचरा बीनने वाले, रिक्शाचालकों, बुनकरों, बीड़ी बनाने वाले मजदूरों आदि को फायदा पहुंचेगा। इस परियोजना की कुल लागत 1811.33 करोड़ रुपये है, जिनमें 750 करोड़ रुपये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मदद के तौर पर मुहैया कराए जाएंगे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, ''आज हमने गरीब और मजदूरों के परिवारों के लिए 30,000 घरों की परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना के लाभार्थियों में वैसे लोग हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, रिक्शा, ऑटो आदि चलाते हैं।'' उनका यह भी कहना था कि मध्य वर्ग के परिवारों को सस्ते घर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास हुए हैं। अब वे 20 साल में घर निर्माण से जुड़े कर्ज पर 6 लाख रुपये तक बचत कर सकते हैं। यह इस दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों के फायदों को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत के अपने विज़न के तहत सोलापुर में 'भूमिगत नाली प्रणाली' और तीन कचरा शोधन संयत्र राष्ट्र को समर्पित किये। इससे शहरों में नालियों के दायरे का विस्तार होगा और स्वच्छता में बढ़ोतरी होगी। यह मौजूदा प्रणाली की जगह लेगा और 'अमृत' मिशन के तहत बनाए गए बड़े सीवरों से भी जुड़ेगा।

उन्होंने जलापूर्ति और सीवर प्रणाली में सुधार के मकसद से संयुक्त परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसमें अमृत मिशन के तहत सोलापुर स्मार्ट सिटी में क्षेत्र आधारित विकास, उजनी बांध से सोलापुर शहर के लिए पेय जल की आपूर्ति में बढ़ोतरी और भूमिगत सीवर प्रणाली के विकास को लेकर काम करना है। इस परियोजना की स्वीकृत लागत 244 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से सेवाएं बेहतर तरीके से प्रदान करने और तकनीक की मदद से सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर होने की उम्मीद है।

उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से सोलापुर और आसपास के इलाकों में सड़क और परिवहन संपर्क, जलापूर्ति, स्वच्छता, रोजगार सृजन आदि के क्षेत्र में लोगों को काफी लाभ होगा। ❑

विशेषांक

योजना

वर्ष : 63
अंक : 02

फरवरी 2019
माघ-फाल्गुन, शक संवत् 1940

मूल्य : ₹ 30
पृष्ठ : 80

वेबसाइट www.yojana.gov.in

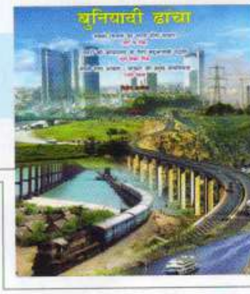

प्रधान संपादक : शमीमा सिद्दीकी
वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ. ममता रानी

संपादकीय कार्यालय
648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा
आवरण: गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना **मंगवाने की दरें**
एक वर्ष: ₹ 230, दो वर्ष: ₹ 430, तीन वर्ष: ₹ 610

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए pdjucir@gmail.com पर ईमेल करें, योजना की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ईमेल पर लिखें या संपर्क करें- दूरभाष: 011-24367453
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली-110003

www.publicationsdivision.nic.in
@DPD_India

इस अंक में

सबको बिजली का सपना होता साकार
आर के सिंह.......... 7

प्रधानमंत्री द्वारा अनेक ढांचागत परियोजनाओं की शुरुआत.......... 12

शहरों की कायापलट के लिए बहुआयामी पद्धति
दुर्गा शंकर मिश्र.......... 14

विशेष आलेख

अंतर्देशीय जलमार्ग : समन्वित जल परिवहन नेटवर्क
प्रवीर पांडे.......... 27

क्या आप जानते हैं?

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन.......... 33

राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और समृद्धि योजना (हृदय).......... 34

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत).......... 35

जल संसाधन और गंगा नवीनीकरण-हाल की बड़ी उपलब्धियां.......... 36

फोकस

उड़ान-हवाई संपर्क को नया आयाम
उषा पाढ़ी.......... 39

भारतमाला परियोजना: राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र की सबसे बड़ी क्रांति
डी दास.......... 42

भारतीय रेलवे : आमूल चूल परिवर्तन की ओर
दीपक राज़दान.......... 47

तेजी से विकास के रास्ते पर उत्तर-पूर्व
नमिता तिवारी.......... 54

सबके लिए आवास : सरकार की प्रमुख प्राथमिकता
रंजीत मेहता.......... 58

खेल ढांचागत सुविधाओं में आगे बढ़ता भारत
राजेश राय.......... 62

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का सृजन
संजीव कुमार.......... 66

ग्रामीण विकास के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा
नितिन प्रधान.......... 72

स्वच्छ भारत मिशन : खुले में शौच से मुक्त भारत के लक्ष्य प्राप्ति की ओर.......... 75

शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार की नई पहलें.......... 76

पुस्तक समीक्षा :
2500 ईयर्स ऑफ बुद्धिज़्म.......... 78

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	द्वितीय तल, अलखनंदा हॉल, भद्रा, मदर टेरेसा रोड	380052	079-26588669

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

आपकी राय

yojanahindi@gmail.com

डिजिटल इंडिया से न्यू इंडिया

योजना का दिसंबर, 2018 अंक पढ़ने को मिला। इसे देखते ही तबियत खुश हो गई। इस अंक में हर लेख में मुख्य केंद्र बिन्दु दूरसंचार क्षेत्र में डिजिटिल क्रांति ही है। मौजूदा सरकार ने डिजिटल इंडिया को हर तरह से कामयाब और सुरक्षित बनाने का अभियान चला रखा है। संभवत: यही कारण है कि डिजिटल इंडिया के कई सकारात्मक प्रभाव देखने-सुनने में आ रहे हैं। भारत सरकार में कानून व न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने लेख में इस बात पर जोर दिया है कि यही वह सुरक्षित माध्यम है जिससे समावेशी और सशक्त राष्ट्र का निर्माण तेजी से संभव है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल इंडिया से हम सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना को सच कर सकते हैं।

श्री आर चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया को देश के लिए एक अनिवार्यता बतलाया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के विकास का भावी मार्ग तय करने में यह अत्यंत महत्वपूर्ण निर्धारक रहा है।

आर एस शर्मा ने दूरसंचार क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का नियमन विषय पर फोकस किया है। वह इसे विकास के प्रमुख कारक के तौर पर देखते हैं। वे दूरसंचार क्षेत्र को डिजिटल इंडिया को बढ़ाने वाला प्रमुख इंजन मानते हैं।

इसी तरह अन्य लेखों में भी कमोवेश इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है।

भारत में लाइब्रेरी के बदलते स्वरूप को भी रेखांकित किया गया है। आज चारों ओर डिजिटल लाइब्रेरी पर जोर दिया जा रहा है फलत: परम्परागत लाइब्रेरी के अस्तित्व पर खतरा मंडराना स्वाभाविक ही है। साइबर संसार में हिंदी का बोलबाला भी लोगों के लिए आश्चर्यचकित तथ्य बनकर सामने आया है। 2022 तक उत्तर पूर्वी भागों में डिजिटल क्रांति का जोर बढ़ने की प्रबल संभावनाओं पर दृष्टि पत्र जारी किया जाना भी सार्थक सोच की ओर इंगित करता है। योजना की पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई!

– डॉ. राकेश कुमार
बिहारशरीफ, नालंदा, बिहार

डिजिटल इंडिया से सुशासन

'डिजिटल इंडिया' पर आधारित योजना का दिसंबर अंक पढ़ा। अंक से तकनीक के विभिन्न आयामों की जानकारी मिली। तकनीक किसी भी देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। तकनीकी विकास से विकास प्रक्रिया को तीव्रता प्राप्त होती है। यह शासन-व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर सुशासन को स्थापित करने पर बल देता है। इसके तहत नागरिकों को स्थानीय स्तर पर बिना किसी परेशानी के विभिन्न प्रकार की अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध करायी जाएगी। डाकघरों एवं पंचायतों को बहुआयामी बनाया जा रहा है जिससे लोगों को किसी भी प्रमाणपत्र के लिए विभिन्न कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। सरकार ने 'जनधन-आधार-मोबाइल' की त्रिकोणीय शक्ति से भ्रष्टाचार पर आक्रमण किया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। वर्तमान में, नि:संदेह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के द्वारा शासन-प्रशासन में निखार आ रहा है और इससे सुशासन की स्थापना को बल मिलेगा।

– अमित कुमार 'विश्वास'
रामपुर नौसहन, हाजीपुर
वैशाली, बिहार

नवाचार पर बेहतरीन अंक

नवाचार पर बेहतरीन अंक निकालने के लिए बधाई। अगर बात की जाए नवाचारों की तो आज के इस आधुनिकीकरण के युग में यह हर क्षेत्र में बेहद जरूरी हो गया है चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, विज्ञान, अनुसंधान, कृषि एवं सार्वजनिक क्षेत्र हो सभी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

पुराने पड़े हुए विचारों में आज नवाचार लाकर उसमें नित नये नये रंग भरे जा रहे हैं जिसके माध्यम से भारत निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है साथ ही इन नवाचारों की बदौलत ही भारत अपनी पैठ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने में सफल साबित हो रहा है।

– पल्लवी आर्य
जिला-संभल, उत्तर प्रदेश
ईमेल : pallaviarya477@gmail.com

नवाचार: 'जय विज्ञान' की सार्थकता

नवाचार केंद्रित अंक संग्रहणीय है। सभी लेख नई-नई जानकारियों से भरे हैं। नई प्रतिभाओं को उनके मस्तिष्क में उपजी अनोखी और जटिल सोच को मूर्त रूप देने के लिए अटल नवाचार मिशन तथा इम्प्रिन्ट जैसे प्लेटफॉर्म का होना देश में युवा वैज्ञानिक तैयार करने की दिशा में सफल प्रयोग है। डिजिटल क्रांति के युग में स्वयं को ई लर्निंग के साथ जोड़े रखना अच्छा है, जिससे ग्रामीण छात्र भी उच्च संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा अपने ही परिवेश में पा सकते हैं। नैनो तकनीक से आज हम बहुत बड़े डेटा को भी छोटे से चिप में सहेज सकते हैं। बेहतर उदाहरण मेट्रो रेल है जो समय की बचत और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ अपनी गुणवत्ता कायम रखे हुए हैं।

नवाचार के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर प्रचार प्रसार के साथ जागरूकता की आवश्यकता ज्यादा है। ताकि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण प्रतिभाएं भी विश्व पटल पर अपनी पहचान बना सकें तथा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकें। इसमें हम सब की भागीदारी होनी चाहिए।

– प्रशान्त कुमार पाठक
पूर्णिया, बिहार
ईमेल : percypriya@gmail.com

संपादकीय

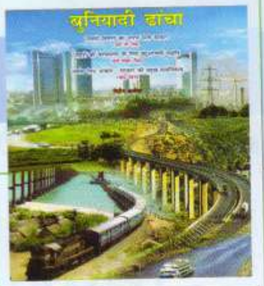

बदलता भारत

एक व्यक्ति जब किसी शहर या कस्बे में बसना चाहता है, तो वह पता करता है कि क्या उसे वहन कर सकने की कीमत पर मकान मिल जाएगा? शहर में बिजली सप्लाई, साफ-सफाई, रोजाना आवाजाही के लिए सड़कें और शहर से बाहर आने-जाने के लिए राजमार्ग, रेल तथा हवाई संपर्क कैसा है? साथ ही आस-पास स्कूल तथा चिकित्सा की आपात स्थिति के लिए अस्पताल इत्यादि हैं या नहीं।

इसीलिए, बुनियादी ढांचे के विकास को आम आदमी के जीवन की कुंजी माना जा सकता है। यह राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि बुनियादी ढांचे का विकास सरकार की प्राथमिकता रहा है और उसने बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में कई पहले की हैं।

आवास के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास, सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। सिर पर छत हर व्यक्ति का सपना होता है और इसे साकार करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 'सभी के लिए आवास' है।

दूरदराज के गांवों में बिजली पहुंचाना सरकार का एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - **सौभाग्य** योजनाओं से ग्रामीण भारत में लोगों का जीवन बदल रहा है।

स्मार्ट सिटी का निर्माण, सरकार की एक और महत्वपूर्ण परियोजना है। स्मार्ट सिटी परियोजना की मूल अवधारणा, न केवल बेहतर नागरिक सुविधाओं या बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ शहरों का निर्माण करना है, बल्कि शहरों को समावेशी और सहयोगपूर्ण बनाने में भी मदद करना है, जिसका उद्देश्य वहां के निवासियों के जीवन में बदलाव लाना है।

सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया है।

सड़कें किसी भी देश की जीवन रेखा होती हैं और आम आदमी के लिए सड़क संपर्क बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छी सड़कें और राजमार्ग तेजी से गंतव्य तक पहुंचने में मदद करते हैं, इसलिए सरकार का लक्ष्य भारतमाला योजना के तहत बेहतर सड़क और राजमार्ग बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इसी तरह, सरकार ने रेल ढांचागत की आधारभूत संरचना में परिवर्तन के साथ-साथ अंतर्देशीय जलमार्ग मार्गों के विकास को भी बढ़ावा दिया है। **उड़ान** योजना के माध्यम से, सरकार छोटे शहरों में आम आदमी के लिए हवाई यात्रा सस्ती करना चाहती है।

इस प्रकार, बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से आम आदमी के लिए सुविधाएं सुलभ बनाना सरकार की प्राथमिकता रही है। विभिन्न सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम निश्चित रूप से नागरिकों के जीवन को बदलने और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में दीर्घकालिक उपाय साबित होंगे। ❑

सबको बिजली का सपना होता साकार

आर के सिंह

पिछले साढ़े चार साल में विद्युत क्षेत्र के तमाम उपक्षेत्रों में, चाहे यह बिजली उत्पादन हो, ट्रांसमिशन हो या वितरण हो, बुनियादी ढांचे के निर्माण में अभूतपूर्व तेजी देखी गयी है। विनियामक ढांचे में सुधार किया जा रहा है जिसके तहत नयी शुल्क नीति बनायी गयी है और विद्युत अधिनियम में संशोधन किये गये हैं। कुल मिलाकर भारत के बिजली क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुआ है।

बिजली आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चाहे कारखाने चलाने हों, बिजली के पंपसेट चलाने हों या मोबाइल फोन चार्ज करने हों, तमाम कार्य बिजली से ही होते हैं। बिजली की भरोसेमंद और किफायती आपूर्ति से जीवन जीना आसान हो जाता है और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। इससे देश के विकास को भी बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भी बिजली पहली शर्त है क्योंकि इससे अब तक बाहरी दुनिया से अलग-थलग रहे लोगों के लिए संपर्क के नये दरवाजे खुल जाते हैं।

पिछले साढ़े चार साल में सरकार ने विद्युत क्षेत्र में लगभग आमूल परिवर्तन ला दिया है। चाहे विद्युत उत्पादन हो या ट्रांसमिशन और वितरण, इन वर्षों में बुनियादी ढांचे से संबंधित हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तेजी से निर्माण कार्य हुआ है। नई शुल्क नीति से विनियामक ढांचे में सुधार किया जा रहा है और विद्युत अधिनियम में भी संशोधन किये गये हैं। कुल मिलाकर भारतीय विद्युत क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है।

सबसे पहली और बुनियादी जरूरत बिजली की उपलब्धता की थी। आजादी के समय से ही देश अभावों में रहने का

पिछले साढ़े चार साल में सरकार ने विद्युत क्षेत्र में लगभग आमूल परिवर्तन ला दिया है। चाहे विद्युत उत्पादन हो या ट्रांसमिशन और वितरण, इन वर्षों में बुनियादी ढांचे से संबंधित हर क्षेत्र में अभूतपूर्व तेजी से निर्माण कार्य हुआ है। नई शुल्क नीति से विनियामक ढांचे में सुधार किया जा रहा है और विद्युत अधिनियम में भी संशोधन किये गये हैं। कुल मिलाकर भारतीय विद्युत क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आया है

लेखक केन्द्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं। ईमेल: pibpower@gmail.com

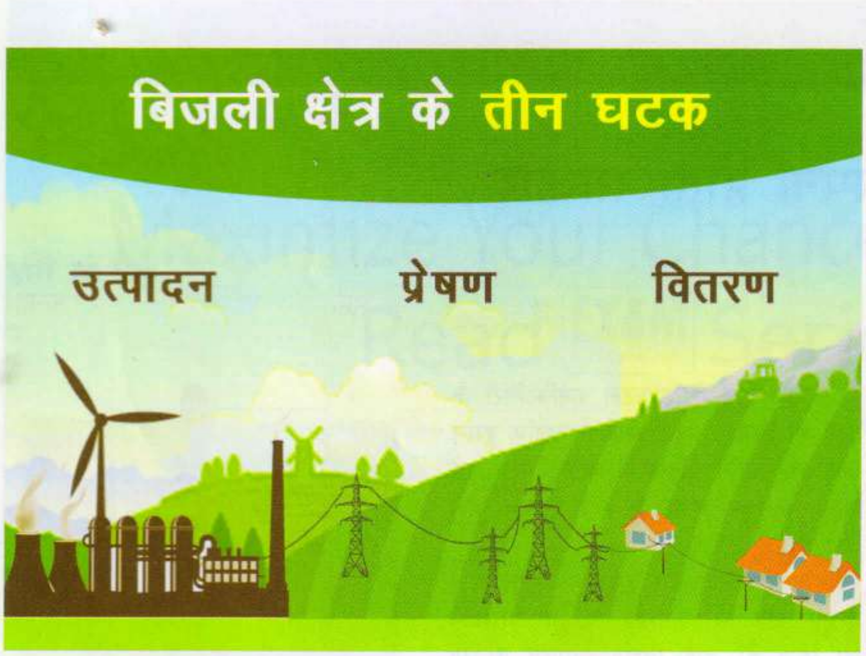

आदी हो गया था। लेकिन पिछले साढ़े चार साल में हमने एक लाख मेगावाट से अधिक नई उत्पादन क्षमता का सृजन किया है और बिजली की कमी 4.2 प्रतिशत से घटाकर लगभग शून्य के स्तर पर आ गयी है। इतना ही नहीं, आज भारत बिजली का निर्यातक है और नेपाल तथा बंगलादेश को बिजली दे रहा है।

पिछले चार वर्षों में हमने एक राज्य से दूसरे राज्य को बिजली के ट्रांसमिशन की क्षमता में एक लाख सर्किट किलोमीटर की बढ़ोतरी की है और समूचे देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया है। आज पहली बार हमारे यहां 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड' की स्थिति है और पूरा नेटवर्क एक ही फ्रीक्वेंसी (आवृत्ति) पर कार्य कर रहा है। आज देश के एक कोने से दूसरे कोने को निर्बाध रूप से बिजली प्रेषित की जा सकती है। यानी, हिमाचल प्रदेश में उत्पादित बिजली तमिलनाडु को और असम से महाराष्ट्र को भेजी जा सकती है या इसके विपरीत भी बिजली का ट्रांसमिशन किया जा सकता है।

हमारी सरकार ने ऐसे हरएक गांव तक बिजली पहुंचाने का फैसला किया है जहां अबतक इसकी सुविधा नहीं है। 15 अगस्त, 2015 को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि जिस किसी गांव में बिजली उपलब्ध नहीं होगी वहां एक हजार दिन के भीतर बिजली पहुंचा दी जाएगी। राज्यों की ओर से बताया गया कि देश की आजादी के सात दशक बाद भी 18,452 गांव बिजली से वंचित हैं। हमने अपने वादे के अनुसार 1,000 से कम दिनों में इन गांवों में बिजली पहुंचा दी। सबको बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तब हासिल हुई जब 28 अप्रैल, 2018 को देश ने ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त कर लिया।

इस कार्य को पूरा करने में बड़ी भारी चुनौतियां थीं और इन्हीं की वजह से इतने लंबे समय तक इन गांवों में बिजली नहीं पहुंच पायी थी। ऐसे ज्यादातर गांव दूर-दराज के दुर्गम इलाकों, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, वामपंथी आतंकवाद से ग्रस्त इलाकों में थे। कठोर संकल्प और धैर्य के बिना वहां तक सामग्री/उपकरण पहुंचाना और काम पूरा करने के लिए श्रमशक्ति जुटाना संभव नहीं था। जैसे-जैसे काम आगे बढ़ता गया, कठिनता के स्तर में भी बढ़ोतरी होती चली गयी। अंत में अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और मणिपुर के दूर-दराज और दुर्गम इलाकों में करीब साढ़े तीन सौ ऐसे गांव थे जहां तक सिर पर सामान लादकर ले जाना पड़ा। कुछ स्थानों तक पहुंचने के लिए 10 दिन पैदल चलकर जाना पड़ा। जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांवों में तो सामान पहुंचाने में हैलीकॉप्टरों की मदद ली गयी। 2,762 गांवों तक ग्रिड के नेटवर्क का विस्तार करना व्यावहारिक नहीं था क्योंकि ये गांव बहुत ही दूर और दुर्गम थे। इसलिए इनमें सौर ऊर्जा पर आधारित एकल प्रणालियों के जरिए बिजली की व्यवस्था की गयी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के वामपंथी अतिवाद के असर वाले 7,614 गांवों के विद्युतीकरण में भी जबरदस्त चुनौतियों से दो-चार होना पड़ा।

इस भगीरथ प्रयास को पूरा करने के लिए दीन दायाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विस्तृत बुनियादी ढांचा खड़ा किया

देश में सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने सितंबर 2017 में 'प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना'-सौभाग्य की शुरुआत की। इस लक्ष्य को निर्धारित तिथि (31 मार्च, 2019) तक प्राप्त करना ऐसी चुनौती थी जिसका बीड़ा हमने उठाया। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 'सहज' यानी आसान/सरल/अनायास और 'हर घर' पर जोर दिया गया है।

तीव्र गति से व्यापक परिवर्तन

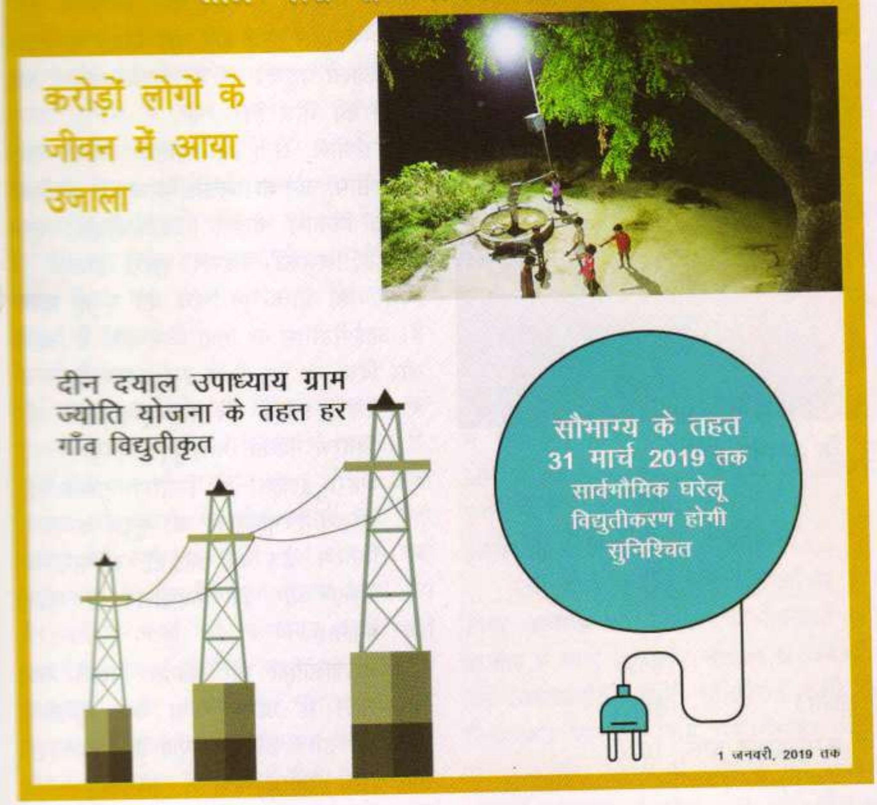

जब इस कार्यक्रम पर पूरे जोर से अमल हो रहा था तो रोजाना औसतन एक लाख घरों को बिजली दी जा रही थी। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत की विद्युतीकरण की मुहीम को वर्ष 2018 की सफलता की महानतम गाथाओं में से एक करार दिया। गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा होने के बाद अब मुश्किल से 4 लाख ऐसे परिवार होंगे जिनमें बिजली नहीं होगी, लेकिन इन्हें भी अगले कुछ सप्ताहों में विद्युतीकृत कर दिया जाएगा और इस तरह देश में हर घर बिजली से जगमग हो जाएगा। दुनिया के किसी भी देश ने इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर कुछ होते नहीं देखा। अपने घर में बिजली पहुंचने पर जो खुशी होती है वह देखने की चीज है।

गया (देखिए टेबल-1)। गांवों में घरों और कृषि के लिए अलग-अलग फीडर लाइनें खींचने पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसके अलावा फीडर लाइनों से घरों और खेतों तक सब-ट्रांसमिशन तथा वितरण करने वाले ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की मात्रा का मीटर से हिसाब रखने की व्यवस्था की गयी। कई हजार किलोमीटर लंबी नयी बिजली लाइनें खींची गयीं और वितरण के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये। इन बकाया गांवों के विद्युतीकरण से इनके सामाजिक-आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस कार्यक्रम ने सहकारी संघवाद की सफलता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, वितरण कंपनियों और प्रशासन ने साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर पूरे तालमेल से कार्य किया।

टेबल-1 : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति (इसमें सौभाग्य कार्यक्रम और उसमें सम्मिलित किय गये ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के लिए अतिरिक्त बुनियादी को भी शामिल कर लिया गया है)

क्रम सं.	ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति	मई 2014 से दिसंबर 2018 तक	मई 2009 से मई 2014 तक
1.	कुल स्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	54,672	33,091
2.	राज्यों को जारी अनुदान सहायता (करोड़ रु. में)	35,437	16,058
3.	गांवों का सघन विद्युतीकरण (संख्या)	3,05,229	2,27,487
4.	डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मरों की संख्या	3,60,840	2,23,563
5.	हाई टेंशन लाइनें (फीडर सेग्रेगेशन और 11 के.वी. समेत) (कि.मी. में)	2,92,023	1,11,677
6.	नये सब-स्टेशनों की संख्या	1,001	553
7.	मौजूदा सब-स्टेशनों में बढ़ोतरी (संख्या)	2109	368

इसके बाद अगला चरण था हर घर को बिजली के प्रकाश से रोशन करना। देश में सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री ने सितंबर 2017 में 'प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना'-सौभाग्य की शुरुआत की। इस लक्ष्य को निर्धारित तिथि (31 मार्च, 2019) तक प्राप्त करना ऐसी चुनौती थी जिसका बीड़ा हमने उठाया। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 'सहज' यानी आसान/सरल/अनायास और 'हर घर' पर जोर दिया गया है। यानी इसमें प्रत्येक घर के विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है। दुनिया में लक्ष्य तय करके इतने बड़े पैमाने पर कोई कार्यक्रम कभी पूरा नहीं किया गया था। इसको पूरा करने की रफ्तार भी गति और नवसृजन की दृष्टि से अनुकरणीय है।

'सौभाग्य' कार्यक्रम के अंतर्गत 2.50 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। यह संख्या दक्षिण अफ्रीका जैसे दो देशों की आबादी के बराबर है और भारत ने यह कार्य 15 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा कर

टेबल-2: आई.पी.डी.एस. के अंतर्गत प्रगति

क्रम सं.	मानदंड	पिछले साढ़े चार साल में प्रगति
1.	कुल परिव्यय	32,612 करोड़
2.	अनुदान पाने वाले राज्य	7,149 करोड़
3.	आई.टी. सक्षम कस्बे	869
4.	प्रगति कर रहे कस्बों की संख्या (आईटी सक्षम)	1958
5.	सकल वितरण और वाणिज्यिक हानियों में कमी दर्शाने वाले कस्बों की संख्या	1070
6.	नये सब-स्टेशन (सं.)	1028
7.	मौजूदा सब-स्टेशनों में बढ़ोतरी (सं.)	441
8.	एचटी लाइनें (कि.मी.)	35,061
9.	एलटी लाइनें (कि.मी.)	18,125
10.	वितरण मीटरों की संख्या	55,679
11.	बिजली मीटरों की संख्या	86,13,063

टेबल -3 : एक राष्ट्र एक ग्रिड

क्रम स.	मानदंड	पिछले साढ़े चार साल में प्रगति
1.	ट्रांसमिशन लाइनों में इजाफा (220 के.वी. और अधिक)	1,14,607 कि.मी.
2.	ट्रांसमिशन क्षमता में इजाफा (220 के.वी. और अधिक)	3,44,367 एमवीए
3.	अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन क्षमता में इजाफा	56,900 मेगावाट
4.	ग्रिड निर्माण की रफ्तार कि.मी./वर्षा	22,921 कि.मी. वार्षिक

दिखाया। बदलाव की यह रफ्तार और पैमाना इतना बड़ा है जो दुनिया में कहीं और ऐसा नहीं देखा गया। जब इस कार्यक्रम पर पूरे जोर से अमल हो रहा था तो रोजाना औसतन एक लाख घरों को बिजली दी जा रही थी। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत की विद्युतीकरण की मुहीम को वर्ष 2018 की सफलता की महानतम गाथाओं में से एक करार दिया।

गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा होने के बाद अब मुश्किल से 4 लाख ऐसे परिवार होंगे जिनमें बिजली नहीं होगी, लेकिन इन्हें भी अगले कुछ सप्ताहों में विद्युतीकृत कर दिया जाएगा और इस तरह देश में हर घर बिजली से जगमग हो जाएगा। दुनिया के किसी भी देश ने इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर कुछ होते नहीं देखा। अपने घर में बिजली पहुंचने पर जो खुशी होती है वह देखने की चीज है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने के अलावा सरकार ने समन्वित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) शुरू की है जिसका मकसद शहरी इलाकों में विद्युत के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना है। आईपीडीएस के तहत जिन क्षेत्रों में विशेष जोर दिया जा रहा है वे इस प्रकार हैं:

- शहरी इलाकों में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना
- शहरी इलाकों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं को सुदृढ़ करना
- वितरण क्षेत्र को आई.टी. से समन्वित करना और इसे स्वचालन में सक्षम बनाना।

आईपीडीएस के अंतर्गत पिछले साढ़े चार साल में खड़ा किया गया बुनियादी ढांचा भी उतना ही महत्वपूर्ण है (टेबल-2) और इससे पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीयता बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

रोजाना एक लाख परिवारों की दर से उपभोक्ता आधार में भारी बढ़ोतरी और उसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के विकास का मतलब है कि बिजली की हमारी मांग में पिछले महीनों में दस प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ोतरी हुई है।

नवीकरणीय ऊर्जा

भारत को विकास करने की आवश्यकता है और यह कार्य जिम्मेदार तरीके से करना जरूरी है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि अपनी आने वाली पीढ़ियों स्वच्छ और हरी-भरी धरती को विरासत दें। यही वजह है कि भारत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली बिजली की मात्रा में फेर-बदल कर रहा है। विद्युत उत्पादन को स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा के मानदंडों पर खरा बनाए रखने के लिए हमने 2022 तक 175 गीगावाट क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से प्राप्त करने की योजना बनायी है। इसमें से 100 गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से और 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से प्राप्त होगी। नवीकरणीय ऊर्जा की समग्र संस्थापित क्षमता पिछले साढ़े चार साल में 34,000 मेगावाट से बढ़ाकर 72,000

मेगावाट कर दी गयी है। इसी तरह पिछले चार साल में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने क्षमता में आठ गुना बढ़ोतरी हुई है। आज सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता की दृष्टि से भारत दुनिया में चौथे स्थान पर, संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता की दृष्टि से पांचवें स्थान पर और कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की संस्थापित क्षमता की दृष्टि से भी पांचवे स्थान पर है। इस तरह हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ किये गये अपने वादे को निभाने की दिशा में अग्रसर हैं।

ऊर्जा दक्षता

जहां एक ओर हम विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता बढ़ाने की दिशा में अग्रसर हैं, वहीं हम यह भी महसूस करते हैं कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के तौर-तरीकों का पता लगाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में कई अभिनव और दूरदर्शितापूर्ण उपाय किये गये हैं। घरों में ऊर्जा की किफायत करने वाले एल.ई.डी. बल्ब वितरित करने का कार्यक्रम 'उजाला' और परम्परागत स्ट्रीटलाइटों के स्थान पर बिजली की किफायत करने वाली स्मार्ट स्ट्रीटलाइट लगाने के लिए स्ट्रीटलाइट नेशनल प्रोजेक्ट (एस.एल.एन.पी.) से अरबों यूनिट बिजली की सालाना बचत हो रही है (टेबल-4).

टेबल-4 : उजाला और एस.एल.एन.पी. योजनाओं से हासिल ऊर्जा दक्षता

क्र.	मानदंड	उजाला	एस.एल.एन.पी.
1.	वितरित एल.ई.डी.की संख्या/ स्थापित स्ट्रीट लाइट	31.80 करोड़ एलईडी बल्ब	77.33 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट
2.	बिजली की अनुमानित बचत	41.30 अरब इकाइयां	5.19 अरब इकाइयां
3.	टाली गयी अधिकतम मांग/क्षमता	8,269 मेगावाट	866 मेगावाट
4.	ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सालाना कमी	3.34 करोड़ टन कार्बन डाई आक्साइड	35.7 लाख टन कार्बन डाई आक्साइड

इनके अलावा विद्युत उपकरणों की ऊर्जा दक्षता प्रदर्शित करने के लिए उनपर 'स्टार लेबल' लगाने का कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (पी.ए.टी.) कार्यक्रम के तहत ऊर्जा के उपयोग में दक्षता के उपाय भी बिजली की किफायत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। उद्योगों के लिए पी.ए.टी. के पहले चक्र में 86 लाख टन से अधिक तेल और समतुल्य पदार्थों की बचत हुई है जो भारत में प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का करीब 1.23 प्रतिशत है। दूसरे चक्र में इससे भी अधिक बचत होने का अनुमान है।

आगे की योजनाएं

एक नयी शुल्क नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें उपभोक्ताओं को सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं। इस नीति में 1 अप्रैल, 2019 से बिजली की निर्बाध आपूर्ति (सप्ताह में सातों दिन और चौबीसों घंटे) करना अनिवार्य बना दिया गया है। अगर किसी वैध कारण के बिना (जैसे पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रखरखाव के लिए या प्राकृतिक आपदा की वजह से) बिजली की आपूर्ति बाधित होती है तो संबंधित विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे डिस्कॉम द्वारा बेवजह बिजली काटे जाने पर कारगर तरीके से रोक लगेगी।

हम भविष्य के लिए एक अन्य क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं और वह है स्मार्ट बिजली मीटर का। हमने तीन साल के भीतर देश में तमाम पुराने तरह के बिजली मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला किया है। इस संबंध में एक शुरुआत नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में पहले ही की जा चुकी है। इससे विद्युत क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इससे सकल ट्रांसमिशन और वाणिज्यिक नुकसान कम होगा, डिस्कॉम की हालत में सुधार होगा, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा और बिजली बिलों के भुगतान में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं इससे युवाओं के लिए कौशल युक्त रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण उभरता हुआ क्षेत्र विद्युत वाहनों का है जिसपर हम ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। सरकार ने बिजली से चलने वाले वाहनों (ई.वी.) को जोरदार तरीके से बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस तरह के वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले इन्हें चार्ज कराने के लिए बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करना पहली पूर्वशर्त है। विद्युत मंत्रालय इन वाहनों की बैटरियों को चार्ज करने और स्टोरेज अवसंरचना के तेजी से विस्तार के लिए अनुकूल विनियामक ढांचा तैयार कर रहा है।

हमारा देश 2018 में विश्व बैंक की बिजली प्राप्त करने की सुविधा संबंधी सूची में 24वें स्थान पर आ गया जबकि 2014 में वह 111 वें स्थान पर था। निश्चय ही यह बड़ी ऊंची छलांग है और इससे सरकार के परिणाम मूलक दृष्टिकोण का पता चलता है। बहरहाल, हमें अभी बहुत कुछ करना है और हमारी परिकल्पना एकदम स्पष्ट है...और हमारा निश्चय दृढ़ है। हम ऊर्जा संपन्न और खुशहाल भारत के निर्माण के प्रति वचनबद्ध हैं। ❑

प्रधानमंत्री द्वारा अनेक ढांचागत परियोजनाओं की शुरुआत

प्रधानमंत्री ने आगरा में गंगाजल परियोजना की शुरुआत की

आगरा में पर्यटन संबंधी आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी 2019 को आगरा शहर और आसपास के इलाकों के लिए कुल 2,900 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने गंगाजल परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना का मकसद तकरीबन 2880 करोड़ रुपये की लागत से आगरा को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। गंगाजल परियोजना का लक्ष्य आगरा में गंगा का 140 क्यूसेक पानी लाना है। इससे शहर की पीने के पानी की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने आगरा स्मार्ट सिटी के लिए एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना में सुरक्षा और निगरानी के मकसद से पूरे आगरा शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इससे आगरा को आधुनिक और विश्वस्तरीय स्मार्ट सिटी बनाने में मदद मिलेगी, जिससे प्रीमियम पर्यटन ठिकाने के तौर पर इस शहर को विकसित करने में मदद मिलेगी। इस पर कुल 285 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री ने आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के उन्नतिकरण (अपग्रेडेशन) के लिए आधारशिला रखी। इसके तहत महिलाओं के अस्पताल में 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 100 बेड वाला मातृत्व विभाग तैयार किया जाएगा। इससे समाज के कमजोर तबके के लिए स्वास्थ्य और मातृत्व संबंधी देखभाल की सुविधाओं में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री ने अमृत योजना के तहत आगरा के पश्चिमी हिस्से में सीवर नेटवर्क परियोजना के लिए भी आधारशिला रखी। इस परियोजना के कारण 50,000 से भी ज्यादा घरों में स्वच्छता सुविधाएं बेहतर हो सकेंगी।

प्रधानमंत्री ने ओडिशा में आधारभूत संरचना संबंधी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री ने 14 जनवरी 2019 को ओडिशा के बालनगीर में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपये की कुछ विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने झारसुगुड़ा का मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) राष्ट्र को समर्पित किया। रेल परियोजनाओं को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने तकरीबन 115 करोड़ की लागत से बने बालनगीर-बिच्छापाली रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने नागवली नदी पर बने नए पुल, बारपाली-डुंगरीपाली और बालनगीर-देवगांव के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण और झारसुगुड़ा-विजिनागरम और संबलपुर-अंगुल रेल लाइन के विद्युतीकरण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सोनेपुर में तकरीबन 15.81 करोड़ की लागत से बनने वाले केंद्रीय विद्यालय की भी आधारशिला रखी। झारसुगुड़ा में बना मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क 100 करोड़ की लागत से बना है और यह आयात-निर्यात और घरेलू कागी के लिए सुविधाएं पेश करेगा। स्टील, सीमेंट, पेपर आदि जैसे महत्वपूर्ण उद्योग इस पार्क के आसपास हैं और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क झारसुगुड़ा को ओडिशा में लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा और राज्य में कारोबार करने में सहूलियत को बढ़ाएगा।

15 किलोमीटर लंबा बालनगीर-बिचुपाली नई रेल लाइन तटीय ओडिशा को पश्चिमी ओडिशा से जोड़ेगी और इस तरह से पूरे राज्य में विकास के लिए नेटवर्क बन सकेगा। इससे भुवनेश्वर या पुरी से नई दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहर पहुंचने में लगने वाला समय भी कम हो सकेगा। इस लाइन से ओडिशा में कई एमएसएमई और कुटीर उद्योगों को फायदा होगा और राज्य में खनन क्षेत्र के लिए अवसर खुल सकेंगे।

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर संपर्क और शिक्षा की अहमियत को प्रमुखता से रेखांकित किया। उन्होंने कहा, 'शिक्षा के कारण मानव संसाधन विकास होगा। हालांकि, आवागमन और संपर्क की बेहतर सुविधा इस तरह के संसाधनों को अवसर में बदल देती है। 6 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन संपर्क और आवागमन की सहूलियत को बढ़ाने की दिशा में हमारी तरफ से एक प्रयास है। यह लोगों की आवाजाही को आसान बनाएगा, उद्योग जगत के लिए खनिज संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाएगा और किसानों को अपना उत्पाद दूर-दराज के बाजारों में ले जाने में मदद करेगा, जिससे ओडिशा के लोगों को जीवन और सुगम हो सकेगा।'

पीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-66 का कोल्लम बायपास राष्ट्र को समर्पित किया

प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय राजमार्ग-66 पर मौजूद 13 किलोमीटर लंबा कोल्लम बायपास राष्ट्र को समर्पित किया। यह दो लेन की सड़क है। इस मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है और कोल्लम बायपास इसका एक उदाहरण है। कोल्लम बायपास अलाप्पुझा और तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा का वक्त कम करेगा और कोल्लम शहर में ट्रैफिक को कम करने में मददगार होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 'प्रगति' के जरिये 12 लाख करोड़ की 250 से भी ज्यादा परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। सड़क संपर्क के मामले में हुए विकास का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि सरकार ग्रामीण संपर्क के मोर्चे पर जल्द ही 100 फीसदी लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेगी। क्षेत्रीय हवाई संपर्क और रेलवे लाइनों के विस्तार के कारण हालात काफी बेहतर हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर भी तैयार हुए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया, 'जब हम सड़क और पुल बनाते हैं तो हम सिर्फ शहरों और गांवों को नहीं जोड़ते हैं। हम आकांक्षाओं को उपलब्धियों, आशावाद के साथ और खुशी को उम्मीद के साथ जोड़ते हैं।' ❑

शहरों की कायापलट के लिए बहुआयामी पद्धति

दुर्गा शंकर मिश्र

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या देश की कुल आबादी का 31 प्रतिशत थी और 2030 तक इससे बढ़कर 40 प्रतिशत और 2050 तक 50 प्रतिशत यानी 80 करोड़ को पार कर जाने का अनुमान है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शहरी भारत देश के सकल घरेलू उत्पाद में 63 प्रतिशत का योगदान करता है और 2030 में इसके 75 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। घनी आबादी और भौतिक संपत्तियों की वजह से जलवायु परिवर्तन, आपदाओं और संघर्षों के प्रति शहरों की संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर शहरों का ठीक से नियोजन और प्रबंधन किया जाए तो शहर प्रगति और चिरस्थायी विकास का माध्यम बन जाते हैं।

शहरों में बुनियादी बदलाव के बारे में भारत का बहुआयामी दृष्टिकोण

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहरीकरण की चुनौतियों को देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के एक अवसर के रूप में देखा-उन्हें लगा कि बुनियादी ढांचे में निवेश से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जीवन यापन करने में सुविधा होगी और राष्ट्र की सेवा में नागरिकों की क्षमताओं का बेहतरीन उपयोग किया जा सकेगा।

क) पहले स्तर पर गरीबी उन्मूलन, किफायती आवास और स्वच्छता तीन सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.यू.एल.एम.), प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पी.एम.ए.वाई.-यू.) और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एस.बी.एम.-यू) को सभी शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जा रहा है।

ख) दूसरे स्तर पर बुनियादी ढांचे, जैसे

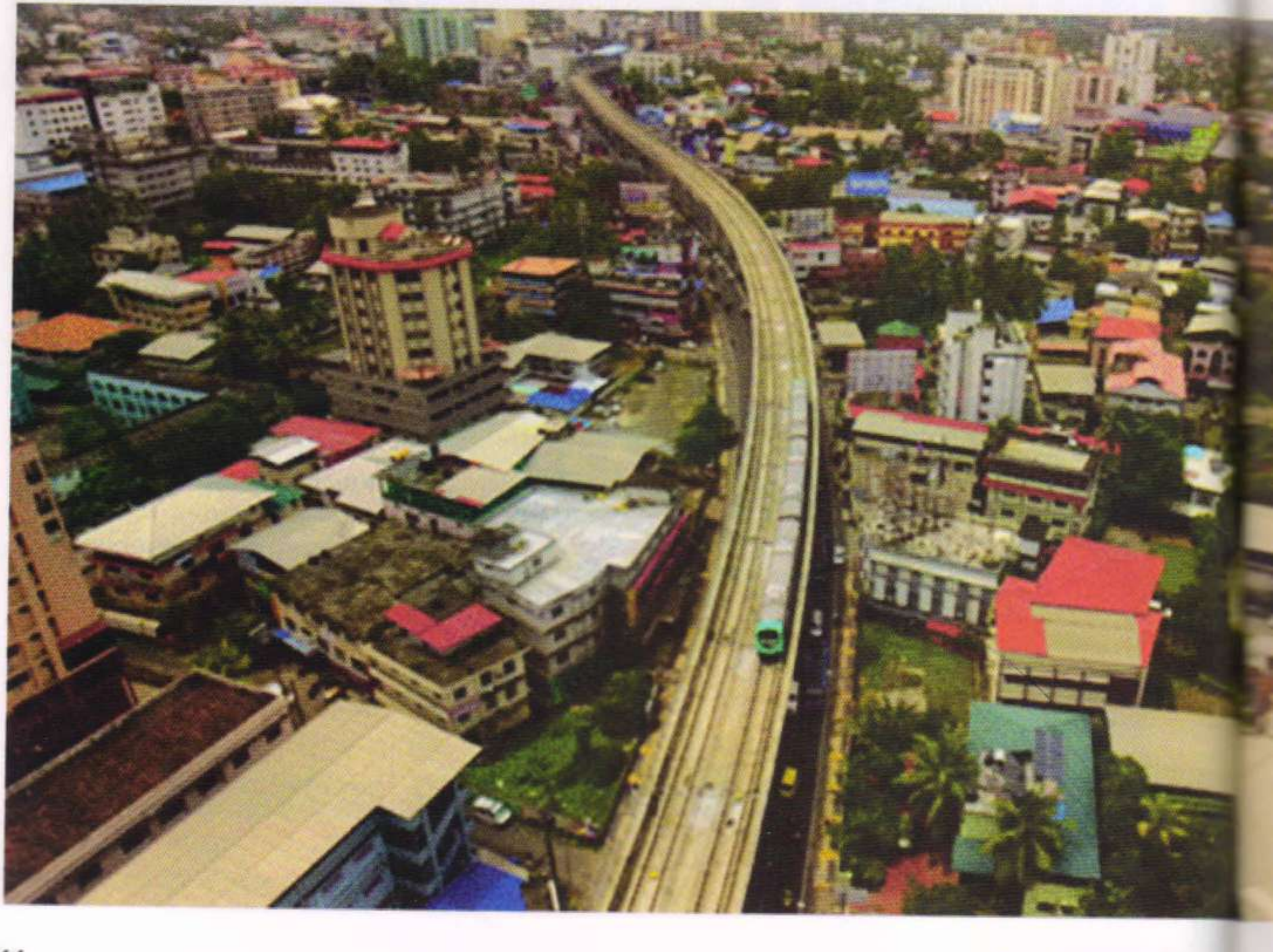

100 स्मार्ट शहरों का विकास प्रकाश इस तरह से किया जाएगा कि वे जीवन यापन की सुविधा की दृष्टि से अन्य शहरों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य करें। इनमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा और संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा ताकि वे मार्गदर्शन का कार्य करें।

जल आपूर्ति और सीवरेज/कचरे के निपटान के कार्य को बड़े पैमाने पर करने में किफायत का फायदा मिलता है इसलिए एक लाख से अधिक आबादी वाले 500 अमृत शहरों में इसे लागू किया जाएगा।

सभी शहरी स्थानीय निकायों में गरीबी उन्मूलन, किफायती आवास और स्वच्छता से संबंधित मसलों के समाधान के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (शाहरी) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का सहयोग लिया जाएगा।

रेखाचित्र 1 : विकास के सोपान

जल आपूर्ति, जलमल/कचरे के निपटान की परियोजनाओं और हरे-भरे पार्कों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इन क्षेत्रों में अधिक संख्या की वजह से होने वाली किफायत का

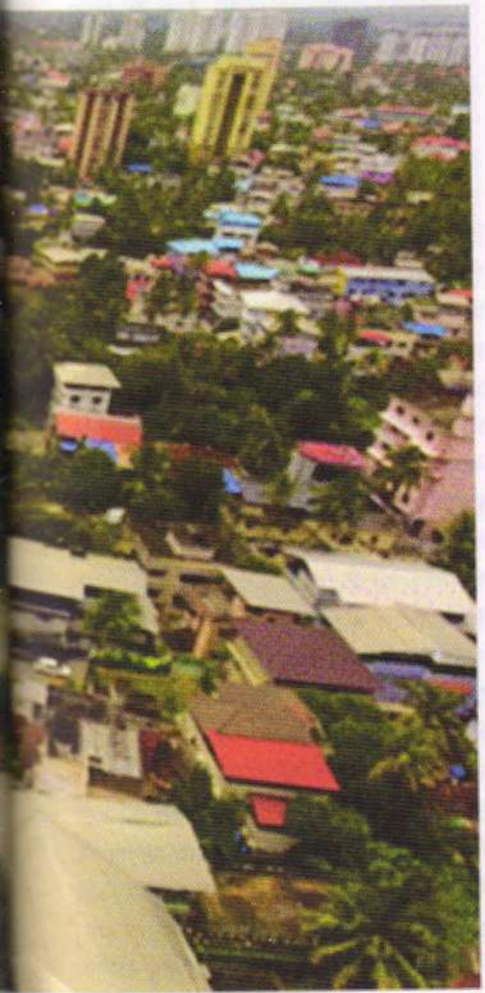

फायदा मिलता है और इसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के माध्यम से एक लाख और इससे अधिक आबादी वाले 500 शहरों में लागू किया जा रहा है। इससे देश की 60 प्रतिशत शहरी आबादी इसके दायरे में आ जाती है।

ग) अंतत: तीसरे स्तर पर 100 शहरों को स्मार्ट सिटीज मिशन (एस.सी.एम.) के तहत विकसित किया जा रहा है और जीवनयापन की सुविधा के मुद्दे पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत जन समुदाय को केन्द्र में रखकर शहरी शासन व्यवस्था के नये आयामों का विकास किया जा रहा है और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाकर शहरी बुनियादी ढांचे, सेवाओं और संसाधनों के उपयोग में सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।

स्मार्ट सिटीज से क्या अभिप्राय है

स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून, 2015 को भारत के प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। बोलचाल की सामान्य भाषा में स्मार्ट सिटीज ऐसे शहर हैं जो अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। बहरहाल, स्मार्ट सिटी की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं है। हमारे स्मार्ट सिटी निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैं:

1) इनका केन्द्र नागरिक होते हैं: नागरिक और जन-समुदाय विकास का केन्द्र बिन्दु होते हैं। 2. कम संसाधनों से अधिक परिणाम : संसाधनों की कमी के प्रति जागरूक होने के कारण इन्हें सीमित संसाधनों-जैसे कम ऊर्जा, कम वित्तीय और अन्य संसाधनों का उपयोग करके ज्यादा असर/परिणाम प्राप्त करने होते हैं, 3. सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद : इन शहरों का चयन दो चरण वाली प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाता है जो राज्य स्तर पर और केन्द्र के स्तर पर होती है, 4. समन्वय, नवाचार और स्थायित्व : स्मार्ट शहर का मतलब केवल टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं है, बल्कि समन्वित रूप से बुनियादी ढांचे और सेवाओं के सृजन से है, 5. टेक्नोलॉजी साधन है

बॉक्स 1

ऐसा पहली बार हो रहा है कि शहरों के कुछ खास इलाकों का व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से विस्तृत विकास किया जाएगा।

ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर नागरिकों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकारी योजना में धन का आबंटन मंत्री या अधिकारियों के निर्णय की बजाय प्रतियोगिता के आधार पर किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री
30 जनवरी 2016 को इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस मीट में

लेखक आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव हैं। ईमेल: secyurban@nic.in

स्मार्ट सिटीज मिशन 25 जून, 2015 को भारत के प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। बोलचाल की सामान्य भाषा में स्मार्ट सिटीज ऐसे शहर हैं जो अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं।

साध्य नहीं : किसी खास शहर के लिए ऐसी उपयुक्त टेक्नोलॉजी का सावधानी से चयन जो समुदायों की खास जरूरतों के अनुसार बनायी गयी हो बहुत जरूरी है तभी इनमें समस्याओं के समाधान निकाले जा सकते हैं और 6. समावेशी निर्देशक सिद्धांत : शहर लोगों के लिए होते हैं इसलिए उन्हें समावेशन सभी लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। मोटे तौर पर स्मार्ट सिटी तीन मूल मुद्दों पर ध्यान देते हैं: रहने के लिहाज से सुविधाजनक, आर्थिक सक्षमता और टिकाऊपन।

स्मार्ट सिटी के बारे में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए नागरिकों की भागीदारी पर आधारित बुनियाद। शहरी इलाकों में सामने आने वाले प्रमुख मुद्दे जिनका सामना अधिकतर नागरिकों को करना पड़ा है इस प्रकार हैं: शहरी आवागमन व्यवस्था, किफायती आवास, जल और जलमल प्रबंधन, स्वच्छता, संरक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा। ये ऐसे पहलू हैं जो इस बात से जुड़े हैं कि नागरिक शहरों में जीवन की गुणवत्ता का मूल्यांकन किस तरह से करते हैं।

रेखाचित्र 2 : विकास मॉडल

आर्थिक विकास को निर्देशित करने की शहरों की शक्ति के बारे में अच्छा अनुसंधान हुआ है और इसे स्वीकार भी किया गया है। निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाना, उपलब्ध प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सक्षम होना और अधिक निवेश तथा प्रतिभाओं को आकृष्ट करना, नवाचार को जन्म देना, बेरोजगारी के स्तर में कमी लाना आदि हमारे स्मार्ट सिटीज की प्रमुख आकांक्षाएं हैं।

अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन उपलब्ध करने और चिरस्थायी विकास के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे, उत्पादों और सेवाओं में निवेश करते समय शहरों को चिरस्थायित्व के बारे में सतर्क रहना चाहिए। इस तरह का विकास समन्वय की स्थिर अवस्था में बना नहीं रहता, बल्कि इसमें ऐसा गतिशील संतुलन बनाने की जरूरत पड़ती है जिसमें टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे, प्रक्रियाओं और निवेश के बारे में रोजमर्रा के फैसले समाज के वर्तमान और भावी सरोकारों के बीच संतुलन कायम करते हुए किये जाएं। स्मार्ट शहर विभिन्न प्रकार की पहल के जरिए चिरस्थायी विकास को प्रोत्साहन देते हैं।

बॉक्स 2

.....इस मिशन का उद्देश्य निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके जीवन को आसान बनाना है.

श्री नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री
28 जुलाई, 2018 को लखनऊ में

	प्रतियोगिता के चार दौर				
	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण	कुल
चयनित शहरों की संख्या	20	40	30	10	100
चयन अवधि	जनवरी 2016	मई से सितंबर 2016	जून 2017	जनवरी 2018	
कुल परियोजनाएं	829	1,959	1,691	472	5,151
निवेश (करोड़ रु.)	48,064	83,698	57,393	15,863	2,05,018
एससीपी का औसत आकार (करोड़ रु.)	2,403	2,092	1,913	1,586	2,050

* शिलांग को जून 2018 में 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया

रेखाचित्र 3 : स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता के चार दौर

स्मार्ट सिटी की मिशन रणनीति

मोटे तौर पर मिशन दो प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है जिनके बारे में दो द्विआयामी रणनीति के अंतर्गत पहले ही विशेष रूप से चर्चा की जा चुकी है। 1. क्षेत्र आधरित विकास जिसमें शहरों के अंदर विश्वस्तरीय स्थलों को अनुकरणीय मॉडल के रूप में रखकर फिर से विकास, सुधार और हराभरा किया जाता है, 2. समग्र नगर विकास, जिसमें शहर डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग

बच्चों की आकांक्षाओं के अनुसार स्मार्ट सिटी योजनाएं

करके अपने कार्य के कुछ प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करते हैं ताकि नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने वाले बुनियादी ढांचे और सेवाओं का सृजन हो सके। इस द्विआयामी प्रक्रिया को रेखाचित्र-2 में प्रदर्शित किया गया है।

स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत

भारत में विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में स्मार्ट सिटी के रूप में विकास के लिए 100 शहरों का चयन किया गया है। चयन प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की गयी जैसा कि रेखचित्र-3 में दिया गया है।

इन स्मार्ट सिटीज ने अपने-अपने चयन की तारीख से पांच साल के भीतर 2,05,018 करोड़ रुपये लागत की 5,151 परियोजनाओं पर अमल का प्रस्ताव किया है। उनकी पूंजी निवेश योजनाओं में वित्तीय नवाचार को समन्वित किया गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशियों का विवरण इस प्रकार है: केन्द्र और राज्य सरकार 93,553 करोड़ रुपये (45 प्रतिशत)(मिशनों, केन्द्र/राज्य के कार्यक्रमों और/या शहरी स्थानीय निकायों से कन्वर्जेंस फंडिंग : 42,088 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत)(सार्वजनिक-निजी भागीदारी कोष से :41,022 करोड़ रुपये (21 प्रतिशत)(ऋण/उधार : 9,843 करोड़ रुपये (4 प्रतिशत) (अपने ही स्रोतों से : 2,644 करोड़ रुपये (1 प्रतिशत)(अन्य स्रोतों से : 15,930 करोड़ रुपये (8 प्रतिशत)। मिशन में शामिल परियोजनाएं विविध क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं। कुछ प्रमुख क्षेत्र और समग्र परियोजना के अंतर्गत उनका अनुपात रेखाचित्र-4 में दिया गया है।

टेक्नोलॉजी साध्य नहीं, बल्कि साधन

जैसा कि पहले कहा गया है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है और स्मार्ट सिटीज मिशन के अनुभव से यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। मिशन के अंतर्गत प्रत्येक स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी सेंटर (जिसे समन्वित कमान और नियंत्रण केन्द्र कहा जाएगा) होगा। यह शहर के मस्तिष्क और तंत्रिका प्रणाली की तरह होगा जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को सामाजिक, भौतिक और पर्यावरण संबंधी पहलुओं से जोड़कर केन्द्रीकृत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी और निर्णय लिए जाएंगे। अत्यंत अल्प अवधि में ही जो नतीजे प्राप्त हुए है वे बड़े उत्साहवर्धक हैं। राजकोट में जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्रों को जारी करने में बढ़ोतरी दर्ज की गयी और निगरानी की व्यवस्था होने से अपराध की दर कम हो गयी। अहमदाबाद में ट्रैफिक चालानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। पुणे में शहर के प्रमुख स्थानों में फ्लड सेंसर लगाए गये हैं जहां से स्मार्ट सिटी सेंटर को आंकड़े भेजे जाते हैं जिनसे समय पर चेतावनी और बचाव प्रणाली को सक्रिय करने में मदद मिली है। विशाखापत्तनम में स्मार्ट सिटी सेंटर से सीसीटीवी और जीपीएस की मदद से सार्वजनिक परिवहन की बसों पर निगाह रखी जा रही है। भोपाल में संपत्ति कर की वसूली बढ़ी है और परिवहन प्रणाली की बसों पर ऑनलाइन निगाह रखी जाने लगी है।

जीवन की गुणवत्ता और अर्थव्यस्था पर असर

स्मार्ट सिटी परियोजनाएं न केवल चिरस्थायी विकास को बढ़ावा दे रही हैं बल्कि शहरों को जीवंत, समवेशिता, आरोग्यमय और सहयोगपूर्ण बनाने में भी मदद कर रही हैं। इनमें से कुछ उदाहरण रेखाचित्र-5 में दिए

रेखाचित्र 4 : स्मार्ट सिटी योजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित निवेश

स्थल निर्माण परियोजना	पुणे ने उपेक्षित शहरी स्थलों को सामाजिक गतिविधियों का केन्द्र बना दिया है जिससे आस-पड़ोस में जीवंतता बढ़ी है।
साइकिल साझा करने की परियोजना	कोयम्बटूर, भोपाल और पुणे टिकाऊ परिवहन एजेंडा में मदद दे रहे हैं और शहरों को हराभरा और आरोग्यमय बना रहे हैं।
इंटेलीजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली	अहमदाबाद, सूरत और विशाखापत्तनम ने आईटीएमएस प्रणाली है जिससे शहर के भीतर निर्बाध और सुविधाजनक तरीके से यात्रा की जा सकती है।
स्मार्ट जल प्रबंधन	अहमदाबाद में एससीएडीए (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) को लागू कर दुर्लभ संसाधनों के उपयोग में दक्षता बढ़ाई गयी है जिससे करदाताओं के पैसे की बचत हुई है।
दीपगृह परियोजना	पुणे में शहर के गरीब युवाओं को आवश्यक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे अपनी रोजी-रोटी कमाने के साथ-साथ समाज के लिए भी योगदान कर सकें।
स्मार्ट कक्षा परियोजना	नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद, काकिनाडा और जबलपुर ने सामान्य कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में बदल दिया गया है। बेहतर शिक्षण प्रबंधन और शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण से परीक्षा परिणामों में सुधार हुआ है।
कूड़े से ऊर्जा संयंत्र	जबलपुर ने कूड़े से ऊर्जा प्राप्त करने का अपनी तरह का पहला संयंत्र स्थापित किया है जिसमें कूड़ा जलाकर उससे जो बिजली बनायी जा रही है उसे सैकड़ों घरों को सप्लाई किया जा रहा है।
स्मार्ट कैम्पस परियोजना	विशाखापत्तनम ने शिक्षण के पारम्परिक तौर-तरीकों में आमूल परिवर्तन किया है और कागज विहीन कक्षाएं बनायी है जिससे शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा मिला है।
बी-नेस्ट इनक्यूबेशन सेंटर	भोपाल शहर में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले इनक्यूबेशन सेंटरों के जरिए अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास कर रहा है जिनसे नवसृजन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कई और शहरों ने भी इसी तरह की परिकल्पना बनायी है ताकि नवाचार का इंजन चालू हो और मिलकर नयी चीजें बनाने की संस्कृति विकसित हो।
राजस्थानी चित्रकला शैली का संरक्षण	जयपुर ने प्रमुख धरोहर भवनों के जीर्णोद्धार और उन्हें फिर से काम में लाने योग्य बनाने का एक सफल मॉडल दिया है।
धरोहर संरक्षण परियोजनाएं	सूरत, इंदौर और भुवनेश्वर सहित कई शहर अपनी पहचान फिर से कायम करने में शानदार कार्य कर रहे हैं और नागरिकों को अपनी पुरानी विरासत से जोड़कर उनके मन में अपने इतिहास के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न कर रहे हैं।

रेखाचित्र 5 : स्मार्ट सिटी मिशन के असर के उदाहरण

पुणे का एक स्कूल

गए हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन क्षेत्र आधारित विकास के तहत जमीन के मिश्रित उपयोग को बढ़ावा देता है क्योंकि निकटता और सघनता से बुनियादी ढांचे और सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव की प्रति व्यक्ति लागत कम हो जाती है। इससे जानकारी और विशेषज्ञता में भी इजाफा होता है जिससे शहरी उत्पादकता में भारी बढ़ोतरी होती है। स्मार्ट सिटी आज आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं। स्थानीय आर्थिक विकास से संबंधित पहल का मुख्य जोर वाणिज्यिक और फुटकर व्यापारिक गतिविधियों पर है जिसके तहत बाजार पुनर्विकास परियोजनाओं पर खासा जोर दिया जा रहा है। मिश्रित उपयोग वाले विकास की अवधारणा के तहत नये कार्यालयों, घरों और सम्मेलन केन्द्र जैसी विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल कुछ अन्य पहलों में कौशल विकास केन्द्रों, इनक्यूबेशन सेंटरों और बिक्री केंद्रों का भी शामिल है।

बॉक्स 3

स्मार्ट सिटी मिशन का मकसद शहरों में सिर्फ बुनियादी ढांचे का विकास करना नहीं है। यह एक ऐसा मिशन है जो राष्ट्र को नयी पहचान देता है। यह 'यंग इंडिया' का 'न्यू इंडिया' का प्रतीक है।

श्री नरेन्द्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री
14 जुलाई, 2018 को वाराणसी में

मुख्य प्रेरक के रूप में नवसृजन

स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य सही भागीदारी और नेटवर्क कायम करना, संपर्क के लिए अनुकूल माहौल बनाना और ऐसे माहौल का निर्माण करना है जिसमें नवसृजन को बढ़ावा मिले। इस कार्य में स्टार्ट अप्स की भूमिका को ध्यान में रखते हुए मिशन इन शहरों में 'स्पिरिट' यानी स्मार्ट सिटीज प्रोमोटिंग इनोवेशन, रिसर्च एंड इन्क्यूबेशन इन टेक्नोलॉजी (स्मार्ट सिटीज द्वारा नवाचार, अनुसंधान और टेक्नोलॉजी में मदद) के माध्यम से एक नया माहौल तैयार करेगा। यह अटल नवसृजन मिशन और स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम के सहयोग से की जाने वाली पहल है जिसमें तीन पहलों की ताकत का फायदा उठाया जाता है। इससे स्मार्ट सिटीज में नवसृजन के

माहौल को बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय क्षेत्रों का विकास होगा, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जा सकेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। आमूल परिवर्तन का एक अन्य क्षेत्र है डिजिटल भुगतान।

चिरस्थायित्व पर प्रभाव

स्मार्ट सिटीज ने ऐसे निवेशों का प्रस्ताव किया है जिनसे बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी और उनकी आवश्यकता की 10 प्रतिशत बिजली सौर ऊर्जा से मिलेगी। केन्द्र शासित प्रदेश दीव देश का पहला शहर बन गया है जहां दिन के समय सौर ऊर्जा से प्राप्त होने वाली बिजली का उपयोग होता है।

इस कार्य में स्टार्ट अप्स की भूमिका को ध्यान में रखते हुए मिशन इन शहरों में 'स्पिरिट' यानी स्मार्ट सिटीज प्रोमोटिंग इनोवेशन, रिसर्च एंड इन्क्यूबेशन इन टेक्नोलॉजी (स्मार्ट सिटीज द्वारा नवाचार, अनुसंधान और टेक्नोलॉजी में मदद) के माध्यम से एक नया माहौल तैयार करेगा। यह अटल नवसृजन मिशन और स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम के सहयोग से की जाने वाली पहल है जिसमें तीन पहलों की ताकत का फायदा उठाया जाता है

कई अन्य शहरों ने भी सौर और पवन ऊर्जा समेत नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाएं शुरू की हैं। स्मार्ट सिटीज ने स्मार्ट बिजली मीटर प्रणाली के जरिए अपनी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में भी पहल की है। ऊर्जा की किफायत करने वाली स्मार्ट इमारतों और 'ग्रीन ट्रांसपोर्ट' के विकल्पों को बढ़ावा देकर और बिजली की जरूरत में कमी लाना स्मार्ट सिटीज द्वारा की गयी कुछ अन्य पहल हैं।

महत्वपूर्ण मददगार

स्मार्ट सिटीज के कार्यनिष्पादन में स्मार्ट अभिशासन, उन्नत शहरी वित्त व्यवस्था, क्षमता निर्माण और टेक्नोलॉजी निर्देशित नवाचार

पुणे की स्मार्ट सड़कें

रेखाचित्र 6 : टेंडर की जा चुकी परियोजनाओं की प्रगति

वडोदरा स्थित समन्वित कमान और नियंत्रण केंद्र

महत्वपूर्ण मददगार है। इनका जिक्र निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है।

स्मार्ट अभिशासन

स्मार्ट सिटी सूचना और संचार टेक्नोलॉजी तथा जिडिटाइजेशन का फायदा अभिशासन को नागरिक केन्द्रित तथा किफायती बनाने, जवाबदेही व पारदर्शिता लाने, नगर निगम के कार्यालय में जाए बगैर सेवाएं उपलब्ध कराने, जनता की आवाज को सुनने के लिए ई-ग्रुपों के निर्माण और फीडबैक प्राप्त करने में करते

रेखाचित्र 7 : रुकी पड़ी परियोजनाओं की प्रगति

रेखाचित्र 8 : पूरी हो चुकी परियोजनाआं की प्रगति

विशाखापट्टणम स्मार्ट सिटी का नगर परिचालन केंद्र

हैं। वे ऑनलाइन उपकरणों के जरिए कार्यक्रमों और गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी भी करते हैं। अब तक 13 स्मार्ट सिटीज ने आई.सी.सी.सीज को चालू किया है और अन्य 49 में इस दिशा में कार्य जारी है।

स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य 'डेटा स्मार्ट सिटीज' के माध्यम से डेटा संचालित अभिशासन में बाधाओं को दूर करना है। डेटा स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरों के लिए एक विकासमान नीतिगत ढांचा है जिसका उद्देश्य लोगों, प्रक्रियाओं और टेक्नोलॉजी वाले समूचे माहौल के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करना है। पुणे और सूरत जैसे शहरों ने सिटी डेटा पोर्टलों http://opendata.pmc.gov.in and

स्मार्ट सिटी मिशन का लक्ष्य सही भागीदारी और नेटवर्क कायम करना, संपर्क के लिए अनुकूल माहौल बनाना और ऐसे माहौल का निर्माण करना है जिसमें नवसृजन को बढ़ावा मिले। इस कार्य में स्टार्ट अप्स की भूमिका को ध्यान में रखते हुए मिशन इन शहरों में 'स्पिरिट' यानी स्मार्ट सिटीज प्रोमोटिंग इनोवेशन, रिसर्च एंड इन्क्यूबेशन इन टेक्नोलॉजी (स्मार्ट सिटीज द्वारा नवाचार, अनुसंधान और टेक्नोलॉजी में मदद) के माध्यम से एक नया माहौल तैयार करेगा

https://surat.data.gov.in/ के जरिए डेटा सेट का प्रकाशन भी शुरू कर दिया है। स्मार्ट सिटीज मिशन का इरादा सभी 100 स्मार्ट शहरों के लिए नागरिक डेटा को नियंत्रण मुक्त करना है।

शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से आत्म-निर्भर बनाना विकास को चिरस्थायी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। मंत्रालय ने शहरों की क्रेडिट रेटिंग शुरू की है जो 465 शहरों के लिए पूरी हो चुकी है। मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों को उनके द्वारा जारी

प्रत्येक 100 करोड़ रुपये के निगम बांडों के लिए 13 करोड़ रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि देने की शुरुआत की है जो 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता के समतुल्य है। अब तक स्मार्ट शहर पुणे (200 करोड़ रुपये), इंदौर (140 करोड़ रुपये), भोपाल (175 करोड़ रुपये), अमरावती (2,000 करोड़ रुपये), हैदराबाद (395 करोड़ रुपये) और विशाखापट्टणम (80 करोड़ रुपये) ने निगम बांडों के जरिए काफी धनराशि जुटा ली है। शहर आवास, कूड़े से ऊर्जा, छत पर सौर प्रणाली, सार्वजनिक रूप से साइकिल साझेदारी, पार्किंग स्थल प्रबंधन, स्मार्ट कार्ड और परिवहन केन्द की परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में संचालित कर रहे हैं।

क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रबंधन

मंत्रालय ने फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक (एएफडी) के सहयोग से सिटीज इनवेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सीआईटीआईआईएस) नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। एएफडी चुने हुए शहरों को टिकाऊ परिवहन, खुले सार्वजनिक स्थानों, शहरी अभिशासन और आई.सी.टी. तथा निम्न आयवर्ग की बस्तियों के बारे में सामाजिक व संगठनात्मक नवसृजन के लिए 10 करोड़ यूरो की निवेश सहायता उपलब्ध करायी है। मिशन सीआईटीआईआईएस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कम से कम 15 परियोजनाओं का चयन करेगा।

इंडिया स्मार्ट सिटीज फैलोशिप और इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है ताकि प्रतिभाशाली युवाओं को मिशन से जोड़ा जा सके। इससे मिशन के भीतर ज्ञान के प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा और पेशेवर नौजवानों को शहरी नियोजन और अभिशासन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

स्मार्ट नेट देश भर में शहरों के विकास और सीखने, साझा करने और ऐसा संसाधन संपन्न माहौल बनाने की एक पहल है जिसमें शहरों के प्रबंधक और प्राथमिक लाभार्थी भारत के शहरी रूपांतरण के बारे में जानकारी को सीख सकें, साझा कर सकें और इसका प्रचार-प्रसार कर सकें।

राष्ट्रीय शहरी नवाचार केन्द्र

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शहरी नवसृजन केन्द्र (एनयूआईएच) नाम के नये संगठन का प्रस्ताव किया जा रहा है जो मौजूदा संसाधनों

भोपाल में समर्पित साइकिल ट्रैक

इंदौर स्थित रजवाड़ा

भोपाल समन्वित क्षेत्र आधारित विकास परियोजना

शहरी वाटरफ्रंट्स से स्थानीय आर्थिक विकास में मदद मिलने के साथ-साथ सामाजिक संपर्क बढ़ते हैं

विशाखापत्तनम में नगर निगम के पार्किंग स्थल की छत पर सोलर प्रणाली

दीव स्मार्ट सिटी में सोलर फोटोवोल्टैक प्रणाली

को समेकित करेगा और शहरी क्षेत्र के लिए नवाचार विकास तथा क्षमता निर्माण गतिविधियों में बढ़ोतरी करेगा। एनयूआईएच लगातार और व्यापक नवसृजन के माध्यम से शहरी क्षेत्र में आमूल परिवर्तन के लिए अनुकूल माहौल बनाने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करेगा। एनयूआईएच राष्ट्रीय स्मार्ट सिटीज क्षमता निर्माण कार्यक्रम का भी संचालन करेगा ताकि मिशन पर अमल के लिए अधिकार संपन्न कार्यकर्ता और सुदृढ़ संस्थाएं उपलब्ध हों।

एनयूआईएच को नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक (एनयूआईएस) से सशक्त किया जाएगा।

मंत्रालय ने फ्रेंच डिवेलपमेंट बैंक (एएफडी) के सहयोग से सिटीज इनवेंस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सीआईटीआईआईएस) नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। एएफडी चुने हुए शहरों को टिकाऊ परिवहन, खुले सार्वजनिक स्थानों, शहरी अभिशासन और आई.सी.टी. तथा निम्न आयवर्ग की बस्तियों के बारे में सामाजिक व संगठनात्मक नवसृजन के लिए 10 करोड़ यूरो की निवेश सहायता उपलब्ध करायी है

एनयूआईएस द्वारा विभिन्न शहरी कार्यक्रमों के लिए जरूरी बुनियादी घटक उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान किया गया है। एनयूआईएस राष्ट्रीय स्तर पर साझा किया जाने वाला डिजिटल बुनियादी ढांचा है जिसका उपयोग केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा भी किया जाएगा।

मिशन की प्रगति की स्थिति

25 जून 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के दिशानिर्देश जारी किये जाने के बाद के तीन वर्षों में सभी 100 शहरों का चयन प्रतियोगिता के आधार पर किया गया है। सभी शहरों ने इसके लिए स्पेशल परपज व्हीकल यानी विशेष कंपनियां गठित की हैं

ताकि मिशन के क्रियान्वयन में मदद मिले। सभी ने स्मार्ट सड़क, जल आपूर्ति, धरोहर और स्थानों के विकास, स्मार्ट आई.टी. तथा संचार, मोबाइल ऐप आधारित नागरिक सेवा प्रदान करने की प्रणाली आदि के लिए परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और उनपर अमल के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की सेवाएं ली हैं।

31 दिसंबर, 2018 को 1,02,027 करोड़ रुपये की कुल 2,563 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी थीं जिनमें से करीब 59,336 करोड़ रुपये की 1,842 परियोजनाओं पर अमल हो रहा है। इनमें से ज्यादातर को अगले 18 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। 10,817 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 587 परियोजनाओं को पूरा भी किया जा चुका है। अक्तूबर 2017 में 21,760 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी थीं जिनसे 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी का पता चलता है। अक्तूबर 2017 में 11,460 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर भी दिये जा चुके थे जिससे करीब 400 प्रतिशत वृद्धि का संकेत मिलता है। जैसे-जैसे नयी परियोजनाओं पर अमल हो रहा है नागरिकों के जीवन पर इनका और अधिक प्रभाव दिखने लगेगा।

आगे का रास्ता - चुनौतियां और अवसर

स्मार्ट सिटी मिशन के प्रारंभ होते समय सबसे बड़ी चुनौती शहरों के स्तर पर एक संस्थागत ढांचा खड़ा करने की थी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत में नगरों के समग्र विकास के लिए शहर के स्तर पर स्पेशल परपज़ व्हीकल (विशेष कंपनियां) गठित की गयी हैं। अब इन शहरों को अपने स्तर पर क्षमताओं का सृजन करना होगा ताकि समस्याओं के टेक्नोलॉजी संबंधी अभिनव समाधान अपनाए जा सकें।

एक बड़ी चुनौती यह है कि शहरी वित्त क्षमताएं कैसे सृजित की जाएं ताकि शहर सरकारों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे अनुदान का भी फायदा उठा सकें। नगर निगम बांड जारी करना, निजी-सार्वजनिक भागीदारी में परियोजना चलाना और भूमि के बढ़े हुए मूल्य से लागत निकालने जैसे नये वित्तपोषण उपायों को लेकर नीतियां बनाने की आवश्यकता है। शहरों ने अपने स्मार्ट सिटी प्रस्तावों में सरकारी

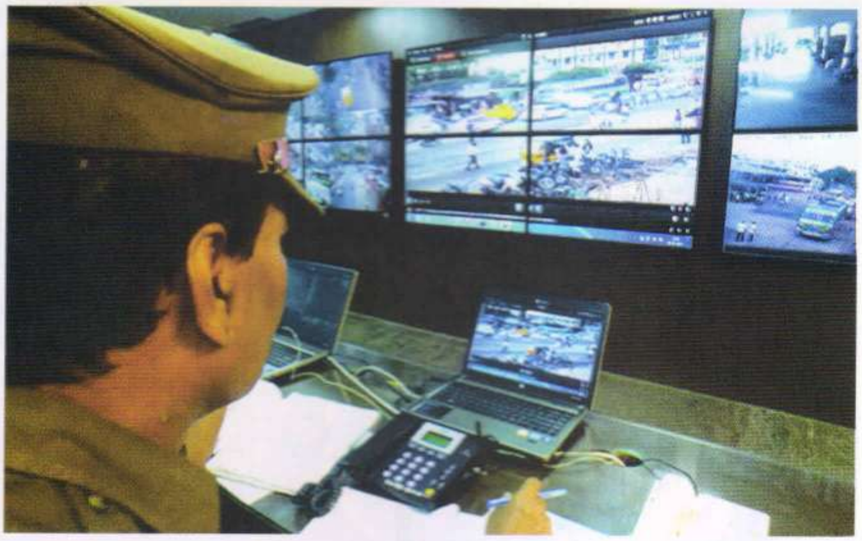

समन्वित कमान और नियंत्रण केन्द्र का लाभ उठाकर नगर की निगरानी

जबलपुर में पीपीपी मोड में चलने वाला कूड़े से ऊर्जा बनाने का संयंत्र

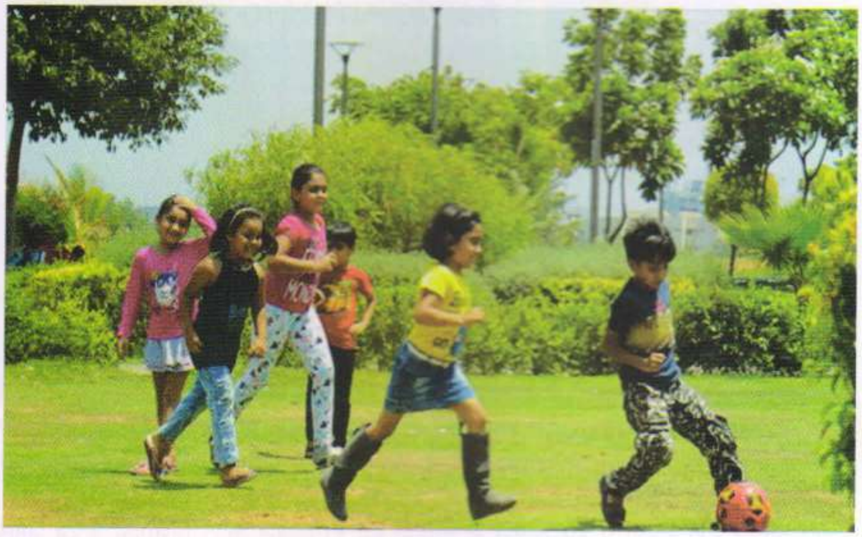

सभी उम्र के लोगों के लिए खुले हुए सार्वजनिक स्थान पर खेलते बच्चे

अनुदान के दो से ढाई गुना (औसतन) के बराबर फायदा उठाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है।

स्मार्ट सिटीज के विकास के संदर्भ में मानकीकरण के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मानक न होने से आपसी तालमेल गड़बड़ाने की समस्या पैदा हो सकती है। हम आई.सी.टी. के स्मार्ट ढांचे के मानदंडों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (आई.बी.एस.) के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य कर रहे हैं और हमें आशा है कि 2019 के मध्य तक इन मानकों के पहले संस्करण को जारी कर दिया जाएगा।

स्मार्ट शहर उस नये शहरी भारत के इनक्यूबेटर की तरह हैं जो हमारे देश के 1.25 अरब से अधिक भारतीयों की आकांक्षा है। यही वह स्थान हैं जहां भारत के 'शहरी नवजागरण' की परिकल्पना की जाएगी और उसपर अमल किया जाएगा। यह भी परिकल्पना की गयी है कि 2022 तक, जब भारत स्वतंत्रता की 75वीं जयंती मनाएगा, भारत के शहरों को वैज्ञानिक तरीके से नियोजित होना चाहिए और उनमें रिहायशी इलाके और सार्वजनिक स्थान सुरुचिपूर्ण तरीके से अकल्पित होने चाहिए ताकि नगरवासियों को रहने, काम करने, खेलने और मनोरंजन के लिए खुला हुआ, साफ-सुथरा और सुरक्षित माहौल मिले। नये शहरी भारत में हर देशवासी को लाभप्रद व्यवसाय, आजीविका और संतोष मिलना जरूरी है। यही शहरीकरण का वह चिरस्थायी मॉडल होगा जो भारत विश्व के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ❑

न्यू इंडिया के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

स्मार्ट सिटीज के माध्यम से शहरी क्षेत्र में बदलाव

गुणवत्तापूर्ण जीवन, स्थायी शहरी योजना और विकास सुनिश्चित करने के लिए **स्मार्ट सिटी के तौर पर करीब 100 शहरी केंद्रों का चयन** किया गया है

इन शहरों में विभिन्न विकास परियोजनाओं की लागत **₹2,05,018 करोड़** तक होगी और इससे करीब **10 करोड़** भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

1 जनवरी, 2019 तक

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 6 करोड़ का आंकड़ा पार किया

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 6 करोड़ का आंकड़ा पार किया। उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने दिल्ली में श्रीमती जस्मिना खातून को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 6 करोड़वां एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया। कई अन्य लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत कनेक्शन प्रदान किए गए।

मौजूदा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2019 तक महिलाओं को पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की थी। जिसे अपने लक्ष्य से काफी पहले ही पूरा कर लिया गया था। पीएमयूवाई के लागू होने से सामान्य रूप से, विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण गरीब परिवार बड़ी संख्या में इस योजना में शामिल हुए है। योजना के 48 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के हैं।

1 दिसंबर 2018 के अनुसार देश में औद्योगिक स्तर पर 22,639 एलपीजी वितरक मौजूद हैं। एलपीजी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तेल वितरण कंपनियों ने देश में मार्च 2019 तक 835 और वितरक शामिल करने की योजना बनाई है।

गरीब परिवारों के लिए एलपीजी सुगम बनाने के लिए उज्ज्वला लाभार्थियों को पांच किलो के रिफिल भी शुरू किए हैं। इसके तहत इस योजना के लाभार्थी 14.2 किलो सिलेंडर को पांच किलो रिफिल में तथा पांच किलो रिफिल वाले को 14.2 किलो सिलेंडर में बदल सकते हैं। पीएमयूवाई को लागू करने की विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने प्रशंसा करते हुए इसे देश की महिलाओं के सामने आ रहे घरेलू स्वास्थ्य प्रदूषण को रोकने वाला निर्णायक कदम बताया है। ❑

(स्रोत : प्रेस सूचना ब्यूरो)

अंतर्देशीय जलमार्ग : समन्वित जल परिवहन नेटवर्क

प्रवीर पांडे

भारत सरकार एकीकृत परिवहन नेटवर्क रणनीति के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास से जुड़े काम को बेहद सक्रियता से आगे बढ़ा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2018 को वाराणसी में गंगा नदी पर तैयार भारत का पहला मल्टीमॉडल टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया। इसी दिन उन्होंने देश के पहले मालवाहक जहाज (कंटेनर कार्गो) की भी आगवानी की, जिसने गंगा नदी पर (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) यात्रा करते हुए कोलकाता से वाराणसी तक की यात्रा की।

दोनों घटनाएं न सर्फ भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) के विकास में ऐतिहासिक क्षण का गवाह है, बल्कि इस तरह के घटनाक्रमों ने राष्ट्रीय जलमार्ग पर बिजनेस गतिविधियों में बढ़ोतरी के लिए जमीन तैयार की। (एनडब्ल्यू-1) के जरिये कई कार्गो मालिक मसलन पेप्सिको इमामी एग्रोटेक, इफको फर्टिलाइजर्स, डाबर इंडिया अंतर्देशीय जलमार्ग से जुड़े हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग कानून, 2016 के तहत 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों का ऐलान किया गया था। 5 मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू), एक नए जलमार्ग को जोड़े जाने से देश में इसकी कुल संख्या 111 हो जाती है। हाल में जिन जलमार्गों का ऐलान किया है, उनमें से 8 को तैयार करने का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2014-15 के लिए 10 जुलाई, 2014 को दिए गए अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर

एक विकसित अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन न सिर्फ देश की पूरी परिवहन क्षमता में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि इससे परिवहन मॉडल को भी दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर मालों की ढुलाई संबंधी बड़ी लागत का बोझ रहता है

लेखक भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वाइस चैयरमैन। ईमेल: vc.iwai@nic.in

न्यू इंडिया के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

संपर्क को बढ़ावा देने हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों का सुदृढ़ीकरण

गंगा नदी पर देश के पहले अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन

राष्ट्रीय जलमार्गों पर निर्मित चार बहु–मॉडल टर्मिनलों में पहला टर्मिनल

जल मार्ग विकास परियोजना के तहत 5369 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड समय में पूरा

1500–2,000 डीडब्ल्यूटी की क्षमता वाले जहाजों को वाणिज्यिक नेविगेशन की क्षमता उपलब्ध होगी

*डेडवेट टनेज

1 जनवरी 2019 तक

जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) का ऐलान किया था, ताकि गंगी नदी के वाराणसी–हल्दिया मार्ग पर व्यावसायिक नौसंचालन को मुमकिन बनाया जा सके। उसके तुरंत बाद जेएमवीपी के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर क्षमता में बढ़ोतरी का काम शुरू हो गया। जेएमवीपी के तहत तकनीकी समर्थन और 5,369 करोड़ की अनुमानित लागत पर विश्व बैंक की तरफ से निवेश संबंधी सहयोग प्रदान किए जाने की भी बात है। चार साल में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जमीनी स्तर पर तकरीबन 2,000 करोड़ रुपये का काम पहले ही हो चुका है।

जेएमवीपी के तहत गंगा नदी पर 2 मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। वाराणसी का टर्मिनल पहले ही चालू हो चुका है और दूसरा साहिबगंज (झारखंड) का टर्मिनल 2019 के मध्य तक तैयार हो जाएगा।

जल मार्ग विकास परियोजना (राष्ट्रीय जलमार्ग-1, गंगा नदी)

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर हल्दिया-वाराणसी के बीच 1,390 किलोमीटर की दूरी पर जल मार्ग विकास परियोजना के तहत क्षमता में बढ़ोतरी का काम किया जा रहा है। इसमें विश्व बैंक की तरफ से तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के साथ प्रस्तावित पूर्वी समर्पित माल गलियारा और एनच 2 भारतीय पूर्वी परिवहन गलियारा का हिस्सा है। यह गलियारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) को पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है और यह कोलकाता बंदरगाह और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिये बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और अन्य पूर्वी और दक्षिणपूर्वी एशियाई देशों के लिए संपर्क के माध्यम की तरह काम करेगा।

दरअसल, यह 1 अक्टूबर 2018 को जलमार्ग के जरिये एक महीना लंबी यात्रा पूरी कर 1,233 टन राख गुवाहाटी के पांडु पहुंचा और इस तरह से इसने देश में अंतर्देशीय जल क्षेत्र (आईडब्ल्यूटी) में काफी लंबी ढुलाई का नमूना पेश किया। बोरियों में बंद 1,233 टन फ्लाई ऐश (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) कहलगांव विद्युत संयंत्र, बिहार) को असम के पांडु पहुंचने के लिए 2,085 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी थी।

यह तीन जलमार्गों (राष्ट्रीय जलमार्ग-1, गंगा नदी), भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) रूट और (राष्ट्रीय जलमार्ग-2, ब्रह्मपुत्र नदी) के जरिये एकीकृत संचार का मामला था।

इस गतिविधि ने अंतर्देशीय जलमार्ग उद्योग में भरोसा और दिलचस्पी पैदा किया है और राष्ट्रीय जलमार्गों के विभिन्न रास्तों पर 15 से भी ज्यादा पायलट गतिविधियां सफलतापूर्वक पूरी हुई हैं।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जुलाई में कार्गो मालिकों और जहाज चलाने वालों को जहाजों की उपलब्धता के बारे में रियल टाइम आंकड़े से जोड़ने के लिए पोर्टल- 'फोकल' की शुरुआत की।

एक विकसित अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन न सिर्फ देश की पूरी परिवहन क्षमता में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि इससे परिवहन मॉडल को भी दुरुस्त करन में मदद मिलेगी, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर मालों की ढुलाई संबंधी बड़ी लागत का बोझ रहता

अंतर्देशीय जलमार्ग के मुद्रीकरण के फायदे

विचार किए गए पहलू	विचार किए गए रेट रुपये/टन किमी)			स्रोत
	जलमार्ग	सड़क	रेल	
वायु प्रदूषण	0.03	0.202	0.0366	योजना आयोग : टीटीएस अध्ययन
ध्वनि प्रदूषण	नहीं के बराबर	0.0032	0.0012	पीआईएएनसी
मिट्टी और पानी संबंधी प्रदूषण	नहीं के बराबर	0.005	बिल्कुल नहीं	पीआईएएनसी
जीएचजी का उत्सर्जन	0.0006	0.0031	0.0006	12वीं पंचवर्षीय योजना

है। भारत में माल की ढुलाई और आवाजाही की लागत जीडीपी का 15 फीसदी है, जो अमेरिका के मुकाबले दोगुनी है। अमेरिका में माल ढुलाई में जलमार्ग की हिस्सेदारी 8.3 फीसदी है, यूरोप में 7 फीसदी और चीन में 8.7 फीसदी है, जबकि भारत में यह सिर्फ 1.5 फीसदी है। भारत के पास जहाजों के चलने लायक अंतर्देशीय जलमार्ग 14,500 किलोमीटर है।

जहाजरानी मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के पास राष्ट्रीय जलमार्ग को व्यावसायिक रूप से चलने लायक बनाने की जिम्मेदारी है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मकसद देश में राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के जरिये माल ढुलाई का काम 5.5 करोड़ टन से बढ़ाकर 2023 तक 15 करोड़ टन करना है।

विश्व बैंक के आर्थिक विश्लेषण के मुताबिक जल मार्ग विकास परियोजना के तहत संबंधित गतिविधियों से तकरीबन 5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार तैयार होंगे।

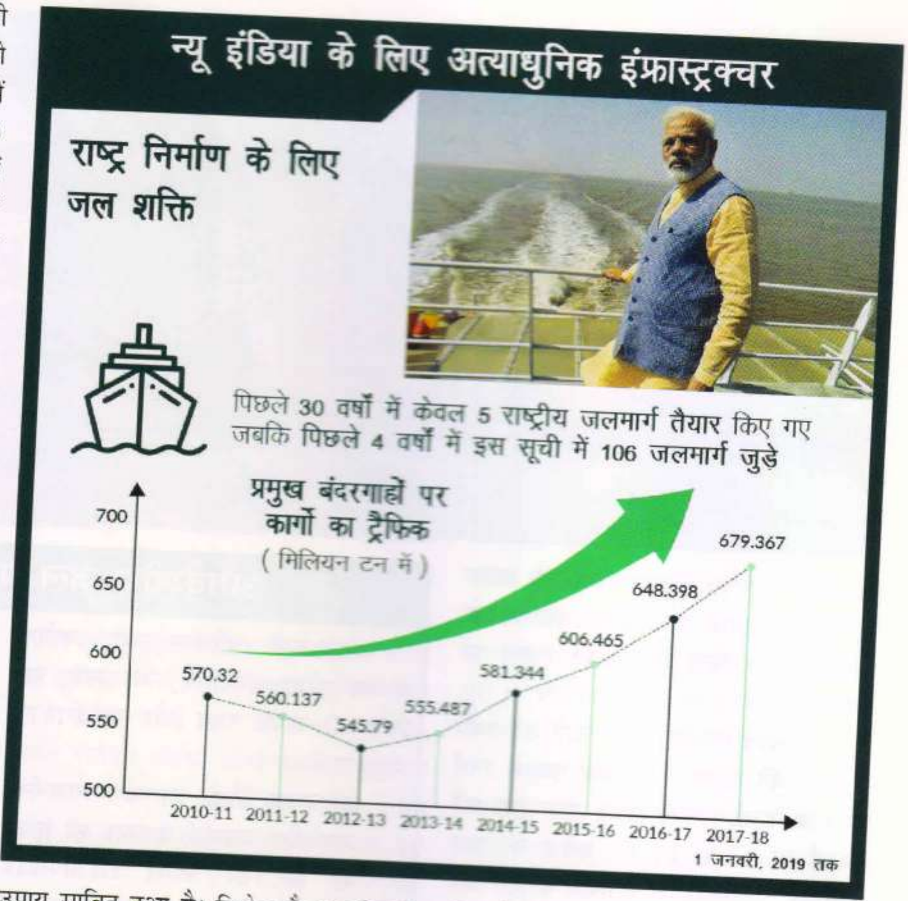

जेएमवीपी गंगा नदी पर पूरी तरह से समावेशी, आर्थिक और पर्यावरण के अनूकूल विकल्प हैं। इससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ नदी को फिर से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह परियोजना न सिर्फ परिवहन का एक वैकल्पिक और सस्ता साधन तैयार करती है, बल्कि इससे 'नदी के लिए गुंजाइश' भी बन सकेगी और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ का खतरा कम करने और नदी के संरक्षण का कारगर उपाय साबित हुआ है। विशेष तौर पर निचले जलस्तर वाले नीदरलैंड में ऐसा देखने को मिला है।

जहाज का प्रारूप

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अगस्त 2018 में जहाज की 13 अत्याधुनिक प्रारूपों को सार्वजनिक रूप से पेश किया, जो गंगा नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) पर बड़े स्तर पर ढुलाई के लिए उपयुक्त है।

यह देश के अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर जैसा है, जिससे गंगा नदी की नौवहन चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। यह अंतर्देशीय जहाजों से जुड़े घरेलू जहाज निर्माण उद्योग के लिए अनुकुल विकल्प की तरह काम करेगा और इससे राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर माल ढुलाई और यात्रियों की गतिविधियों के लिए बड़ी संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।

विशेष डिजाइन के तहत तैयार जहाज उच्च वहन क्षमता के साथ जलमार्गों पर चलेंगे और ये पर्यावरण के अनुकूल भी होंगे। जहां तक जहाज निर्माण उद्योग का सवाल है तो नई डिजाइन के कारण जहाज के निर्माण में 30-35 लाख रुपये की बचत होगी। ये डिजाइन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध हैं और इससे वैसे जहाजों की श्रेणी और किस्म को लेकर भी संशय खत्म हो सकेगा, जो पूरी दक्षता के साथ गंगा नदी में चल सकते हैं। इससे जहाज निर्माण इकाइयों को उच्चस्तरीय क्षमता का जहाज बनाने में मदद मिलेगी और अंतर्देशीय जहाजों के लिए 'बिक्री और खरीद' का बाजार विकसित करने के अलावा इसे काफी जगहों पर उपलब्ध

टर्मिनल तैयार किए हैं, जो किलाघाट, सरस्वती घाट, नैनी पुल और सुजावन घाट पर हैं। मेला प्राधिकरण द्वारा इन टर्मिनल के आसपास टेंट में रहने की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। श्रद्धालुओं को ले जाने और पहुंचाने के लिए आईडब्ल्यूएआई के दो जहाज- सीएल कस्तूरबा और एसएल कमला भी तैनात किए गए हैं।

प्रयागराज और वाराणसी के बीच 1 मीटर की न्यूनतम उपलब्ध गहराई के साथ कुछ दूरी पर नौसंचालन संबंधी मदद की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए पांच अस्थायी

कराया जा सकेगा। बेहतर डिजाइन के कारण ईंधन की लागत कम होगी और इसके परिणामस्वरूप माल ढुलाई की लागत भी घटेगी।

ये जहाज तकरीबन 350 कारों को लेकर 2 मीटर की गहराई में भी चल सकेंगे। इनमें से कुछ डिजाइन वाले जहाज तीन मीटर की गहराई पर 2,500 टन की क्षमता के साथ माल की आवाजाही को मुमकिन बनाएंगे और इस तरह से सिर्फ एक जहाज से सड़कों से तकरीबन 150 लोड ट्रक या पूरे एक रेल रेक का बोझ कम हो सकेगा।

थोक में सूखा और तरल सामानों के वाहक, आरओ-आरओ जहाज, कार वाहक, कंटेनर वाहक, एलएनजी वाहक, जैसी विभिन्न श्रेणियों के लिए मेसर्स डीएसटी, जर्मनी ने नया डिजाइन तैयार किया है। इस ईकाई की उच्च वहन क्षमता में विशेषज्ञता है। इस डिजाइन की जांच डुइसबर्ग जनवरी में की गई थी। नई डिजाइनें अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए भारतीय जहाज निर्माणकर्ताओं की निर्भरता को खत्म करेंगे और सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए कारगर साबित होंगे।

कुंभ और अन्य सामाजिक आयोजनों में आईडब्ल्यूएआई

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) कुंभ मेला, 2019 में यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

कुंभ मेले का आयोजन संगम, प्रयागराज में 15 जनवरी से 15 मार्च 2019 तक किया गया है। आईडब्ल्यूएआई ने चार अस्थायी

अंतर्देशीय जल परिवहन के फायदे

आईडब्लूटी परिवहन का अतरिक्त माध्यम मुहैया कराता है, जो सस्ता, कम ईंधन की खपत वाला और पर्यावरण के अनुकूल है।

1. हानिकारक गैसों का कम उत्सर्जन- अंतर्देशीय जलमार्ग से माल की ढुलाई पर प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन 15 ग्राम है, जबकि रेल और सड़क परिवहन से माल ढुलाई के संबंध में यह आंकड़ा क्रमश: 28 ग्राम और 64 ग्राम प्रति टन है।
2. ऊर्जा की कम खपत- 1 एचपी पानी में 4,000 किलोमीटर भार वहन कर सकता है, रेल और सड़क का यही आंकड़ा क्रमश: 500 किलोग्राम और 150 किलोग्राम है।
3. ईंधन की लागत में भी कमी- 1 लीटर ईंधन से जलमार्ग में 105 टन-किलोमीटर की दर से सामान आगे बढ़ेगा, जबकि रेल में यह आंकड़ा 85 टन-किलोमीटर और सड़क में 24 टन-किलोमीटर है।

- अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन नदी परिवहन को तमाम साधनों के साथ जोड़ते हुए अधिकतम बेहतर सुविधा मुहैया करा सकता है और यह ढुलाई के कुल खर्च को कम करने में मददगार है।
- यह सड़क और रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ की समस्या को कम करता है।
- अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए सड़क और रेल मार्ग की तुलना में काफी कम जमीन अधिग्रहण की जरूरत पड़ती है।
- यह अपेक्षाकृत अविकसित दूर-दराज के इलाके की जरूरतों को पूरा करता है।

कारोबार के अवसर

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विकास कार्य जलमार्ग से जुड़े इन खिलाड़ियों को इन क्षेत्रों में कारोबारी अवसर उपलब्ध कराते हैं:

- माल ढुलाई संबंधी गतिविधियां
- तलकर्षण संबधी कार्य
- टर्मिनल का निर्माण, संचालन और रखरखाव
- बराज निर्माण और रखरखाव
- नौसंचालन सहायता
- जलमाप चित्रण संबंधी सर्वे
- जहाज और टर्मिनल के लिए मानव संसाधन की आपूर्ति। जहाज के चालक दल को प्रशिक्षण।
- जहाजीकुली और अग्रेषण
- पोतविहार संचालन
- तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के लिए सलाहकार सेवाएं, पर्यावरण व सामाजिक प्रभाव और बाजार विश्लेषण अध्ययन, डीपीआर के लिए तैयारी।
- परियोजना प्रबंधन सलाह
- निर्माण संबंधी देखरेख
- डिजाइन की प्रूफ जांच
- मॉडल अध्ययन।

घाट-चतंग, सिरसा, सीतामढ़ी, विंध्याचल और चुनार बनाए गए हैं। आईडब्ल्यूएआई के पास अंतर्देशीय नौसंचालन के जरिये परिवहन का सुरक्षित और दक्ष साधन मुहैया कराने की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (प्रयागराज से हल्दिया) के विकास के तहत आईडब्ल्यूएआई गंगा नदी के प्रयागराज-वाराणसी खंड को नौसंचालन के योग्य बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पहल कर रहा है। इससे जहाजों की सुरक्षित और बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी।

इससे पहले पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेला और पटना के प्रकाश पर्व में आईडब्ल्यूएआई श्रद्धालुओं को पहुंचाने और अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का काम कर चुका है।

नदी परिवहन को बढ़ावा

अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन 'कोंडे नेस्ट ट्रैवलर' ने गंगा पोतविहार (क्रूज) को 2017 में नदियों से संबंधित 6 सबसे बेहतरीन पोतविहार में शामिल किया। इसने लग्जरी क्रूज जहाज वोयेजर II को इस सूची में रखा है, जिसका परिचालन कोलकाता से वाराणसी के बीच होता है। इसे चीन में मेकॉन्ग और यांगट्ज, दक्षिण अमेरिका में अमेजन, रूस में वोल्गा और म्यांमार में इरावाड्डी से जुड़े पोतविहार (क्रूज) की श्रेणी में रखा गया। क्रूज ठिकाने के तौर पर इस प्रकाशन द्वारा गंगा को मान्यता दिया जाना भारत में नदी पर्यटन के लिए एक बेहतर अवसर की तरह है।

आईडब्ल्यूएआई राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी) पर निजी क्रूज संचालकों के साथ मिलकर कोलकाता से वाराणसी के बीच क्रूज सेवा उपलब्ध कराता है। आईडब्ल्यूएआई की तरफ से उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में रात्रि नौवहन सुविधा, तय ठिकानों पर चढ़ने और उतरने की सुविधा, समेत नौवहन संबंधी अन्य सहायता शामिल हैं। भारत में माल ढुलाई का प्रमुख रास्ता बनने के अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के इस खंड में नदी क्रूज पर्यटन की भी अच्छी संभावनाएं हैं।

अन्य राष्ट्रीय जलमार्ग:

राष्ट्रीय जलमार्ग-2

बांग्लादेश सीमा से सदिया तक (891 किलोमीटर) ब्रह्मपुत्र नदी को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग-2 घोषित किया गया था। इस जलमार्ग को जहाज के जरिये माल ढुलाई के लिए टर्मिनल और अन्य सुविधाओं के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट :

भारत और बांग्लादेश के तय बंदरगाहों में प्रवेश के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा हर रोज प्रोटोकॉल संबंधी इजाजत दी जाती है। यह एक तरह से पारस्परिक लाभ के लिए समझौता है, जिसका इस्तेमाल जलमार्ग के जरिये दोनों देशों के बीच व्यापार और सामानों की आवाजाही के लिए किया जाता है। इस समझौते पर सबसे पहले 1972 में हस्ताक्षर हुए थे और फिलहाल यह 5 जून 2020 तक वैध है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-3 को पूरी तरह से व्यावसायिक नौसंचालन के लिए विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-4 और राष्ट्रीय जलमार्ग-5 को अंतर्देशीय जलमार्ग की आधारभूत संरचना

न्यू इंडिया के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

बंदरगाह के विकास में जबर्दस्त बढ़ोतरी

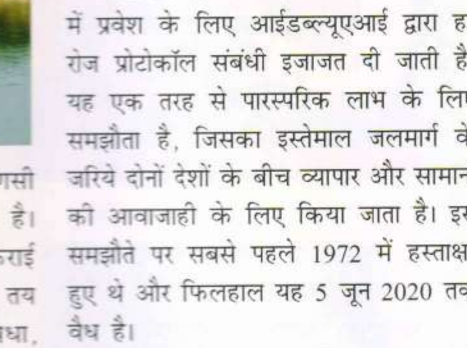

पिछले 4 वर्षों में प्रमुख बंदरगाहों पर जहाज पर माल लादने और उतारने के समय में आई कमी

94 घंटे में 2013-14 से 64 घंटे में 2017-18

के साथ विकसित किया जा रहा है।

2017-18 के दौरान 8 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का कार्य शुरू हुआ:

1. बिहार और उत्तर प्रदेश में गंडक नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-37)
   - गंडक नदी की 277 किलोमीटर लंबाई को राष्ट्रीय जलमार्ग-37 घोषित किया गया है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी घाट के पास भाईसासलोतल से हाजीपुर तक मौजूद है।
2. रूपनारायण नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग 86)
   - रूपनारायण नदी की 72 किलोमीटर लंबाई को राष्ट्रीय जलमार्ग-86 घोषित किया गया है। यह पश्चिम बंगाल में प्रतापपुर से गेओंखली तक स्थित है।
3. आल्लपुझा कोट्टयम अथिरम्पुझा नहर (राष्ट्रीय जलमार्ग 9)
   - आल्लपुझा कोट्टयम अथिरम्पुझा नहर की 38 किलोमीटर लंबाई को राष्ट्रीय जलमार्ग 9 घोषित किया गया है। यह केरल में नाव जेट्टी, आल्लपुझा से अथिरम्पुझा बाजार तक मौजूद है।
4. सुंदरबन जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग 97)
   - पश्चिम बंगाल में मौजूद 201 किलोमीटर की लंबाई वाले सुंदरबन जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग-97 घोषित किया गया है।
5. बराक नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग 16)
   - परियोजना की लागत 76.01 करोड़ रुपये है।
   - राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर माल ढुलाई वाली प्रमुख चीजें निर्माण सामग्री, चावल, कोयला, कागज और सामान है।
6. 7, और 8- गोवा जलमार्ग - कंबरजुआ नहर (राष्ट्रीय जलमार्ग-27), मंडोवी नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-68) और जुआरी नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-111)
   - कंबरजुआ नहर (राष्ट्रीय जलमार्ग 27) - 17 किलोमीटर: कोर्टालिम टर्मिनल के पास कंबरजुआ और जुआरी नदियों के संगम से लेकर साव कंबरजुआ और मंडोवी सो मार्टिअस विधानपरिषद के पास कंबरजुआ और मंडोवी नदियों के संगम तक।
   - मंडोवी नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग 68)-41 किलोमीटर: उसगांव पर पुल से मंडोवी नदी में रीस मैगोस के पास अरब सागर तक।
   - जुआरी नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग 111)-50 किलोमीटर: सनवर्दम पुल से मोर्मोगाओ बंदरगाह तक। ❑

प्रमुख बंदरगाहों की उपलब्धियां

सरकार नियमित रूप से प्रमुख बंदरगाहों के विकास/विस्तार से जुड़ी परियोजनाओं की निगरानी रख रही है। इस सिलसिले में हाल में कुछ अहम नीतिगत और प्रक्रिया संबंधी कदम इस तरह हैं:

(I) प्रमुख बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के स्तर पर लाना, प्रमुख बंदरगाहों की दक्षता और उत्पादकता को लेकर एक अध्ययन किया गया गया। इस अध्ययन में 116 बंदरगाहों के हिसाब से बिंदुओं/पहल की पहचान की गई है, जिनमें से 91 बिंदुओं को पहले ही पूरी किया जा चुका है।

(II) भारतीय बंदरगाह रेल निगम लिमिटेड नाम से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में एक नया स्पेशल पर्पज व्हीकल तैयार किया गया है। इसका मकसद प्रमुख बंदरगाहों से जुड़ी रेल संपर्क परियोजनाओं पर काम करना है, ताकि उनकी हैंडलिंग क्षमता और दक्षता को बेहतर बनाया जा सके।

(III) 2016-17 में औसत टर्न-राउंड समय 82.28 घंटा था, जो घटकर 64.43 घंटा हो गया।

(IV) 2017-18 के दौरान प्रति जहाज बर्थ औसत उत्पादन बेहतरी के साथ 15,333 टन हो गया।

(V) 207-18 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों ने 67.93 करोड़ टन के कार्गो का लेनदेन किया।

(VI) 2017-8 में प्रमुख बंदरगाहों में 92 एमटीपीए क्षमता की बढ़ोतरी हुई। प्रमुख बंदरगाहों की कुल क्षमता 1,451.19 एमटीपीए के स्तर पर पहुंच गई।

(VII) 2017-18 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों का परिचालन आधिक्य (सरप्लस) बढ़कर 916.22 करोड़ रुपये हो गया। ❑

क्या आप जानते हैं?

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)

प्रधानमंत्री ने 22 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) की शुरुआत की। उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के कुराभात से इसका उद्घाटन किया।

इस मिशन का मकसद देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विकास के समूह तैयार करना था, ताकि इस क्षेत्र में संपूर्ण विकास की राह बनाई जा सके। इन समूहों (क्लस्टर) को आर्थिक गतिविधियां मुहैया कराना, कौशल विकास और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना और आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएं मुहैया कराना है।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राम कृपाल यादव की तरफ से 13 दिसंबर 2018 को लोकसभा में दी गई सूचना के मुताबिक, एसपीएमआरएम पूरे देश में लागू होने की प्रक्रिया में है।

इस दिशा में तय लक्ष्य यानी 300 समूहों में 295 की पहचान की जा चुकी है और इन्हें कुल 29 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में मंजूरी मिल चुकी है। 5,142.08 करोड़ रुपये के प्रस्तावित खर्च के साथ इस अनोखे कार्यक्रम का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर उत्प्रेरक संबंधी पहल करना है।

हर रर्बन समूह के लिए अनुमानित निवेश का 30 फीसदी तक फंडिंग समर्थन गैप फंडिंग के रूप में है, जबकि इससे जुड़ा 70 फीसदी फंड राज्य और केंद्र सरकारों के कार्यक्रमों और प्राइवेट और संस्थागत फंडिंग के जरिये दिए जाने की बात है।

इस मिशन के फिर से केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना की तरह वर्गीकृत किए जाने के कारण सीजीएफ (क्रिटिकल गैप फंडिंग) को मैदानी इलाके वाले राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 अनुपात और हिमालयी और उत्तर-पूर्व राज्यों में 90:10 में बांटा जाएगा। इसके अलावा, राज्यों के साथ सलाह-मशवरा और सहयोग कर 232 एकीकृत समूह कार्य योजना (आईसीएपी) तैयार किए गए हैं, जो हर समूह के लिए निवेश का खाका की तरह है।

पिछले 4 वित्त वर्षों में 29 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सीजीएफ में अपनी हिस्सेदारी के तहत केंद्र की तरफ से 1314 करोड़ रुपये, राज्य के हिस्से के तौर पर 627.91 करोड़ और प्रशासनिक फंडिंग के तौर पर 103.25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वित्त वर्ष 2015-16 में 32.05 करोड़ रुपये का प्रशासनिक फंड जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2016-17 में इस मद में कुल 600 करोड़ रुपये जारी किए गए।

वित्त वर्ष 2017-18 में इस संबंध में संशोधित अनुमान 600 करोड़ रुपये का था, जबकि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 553.26 करोड़ रुपये जारी किए गए।

मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 में 551.01 करोड़ के संशोधित अनुमान के मुकाबले 236.90 करोड़ रुपये जारी किए गए। समूहों में विकास के काम के प्रमुख हिस्सों की पहचान बुनियादी और आर्थिक सुविधाओं के प्रावधान पर की जाती है।

किसी समूह (क्लस्टर) में बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान में निम्न चीजें होती हैं; सभी घरों को 24/7 पानी की आपूर्ति, घरों और समूह के स्तर पर ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की सुविधा। समूह के भीतर गांव के अंदर और बाहर सड़कों का प्रावधान, हरित तकनीक के उपयोग से गली के लिए पर्याप्त रोशनी और सार्वजनिक परिवहन। समूह (क्लस्टर) में आर्थिक सुविधाओं के प्रावधान के तहत छोटे और मंझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृषि सेवाएं और प्रसंस्करण, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ❑

राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और समृद्धि योजना (हृदय)

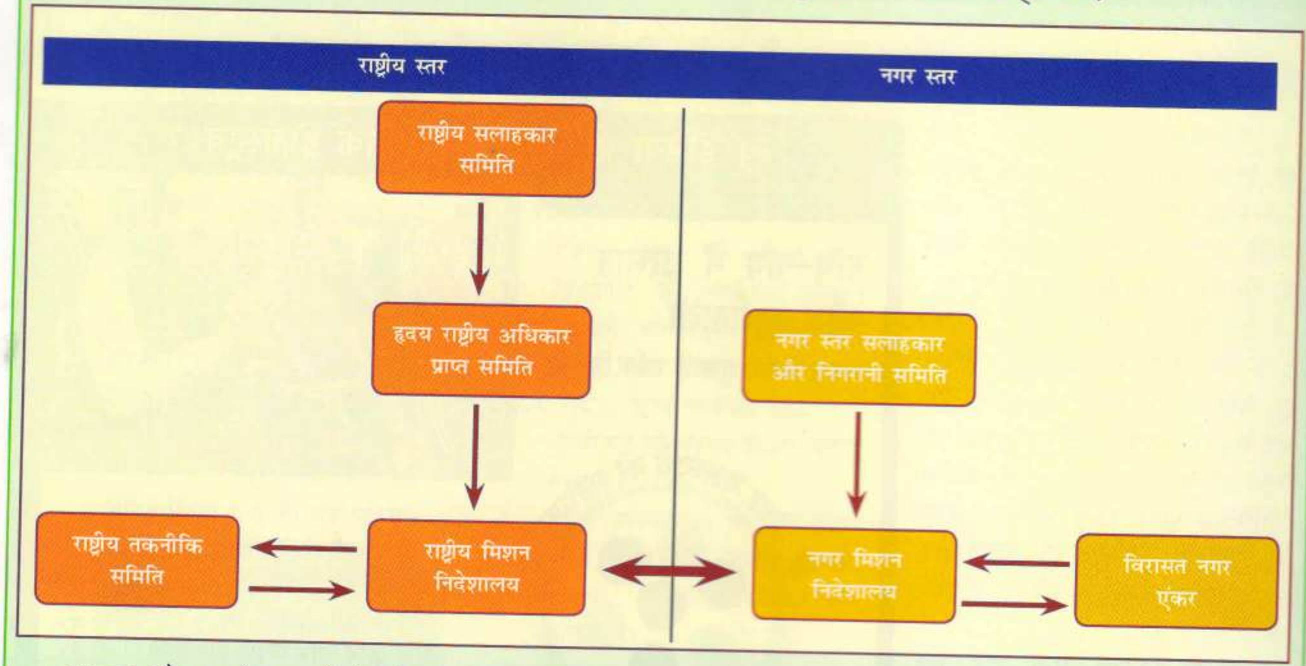

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और समृद्धि योजना की शुरुआत की थी और इसका फोकस विरासत वाले शहरों का संपूर्ण विकास था। हृदय का मुख्य मकसद इस तरह के शहरों के मूल चरित्र व आत्मा को सुरक्षित रखना और निजी क्षेत्र समेत विभिन्न ठिकानों की तलाश कर विरासत से जुड़े शहरी विकास की राह आसान करना है। इसके मुख्य मकसद इस तरह हैं:

- विरासत से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं की योजना बनाना, उसे विकसित करना और उसका कार्यान्वयन करना।
- ऐतिहासिक शहर से जुड़े मुख्य क्षेत्रों में सेवा मुहैया कराना और आधारभूत संरचना का प्रावधान करना।
- विरासत का संरक्षण कर उसे फिर से मजबूत करना, ताकि पर्यटक शहर के अनोखे चरित्र से सीधे जुड़ सकें।
- शहरों की विरासत संबंधी संपत्ति की सूची बनाकर इसका दस्तावेज तैयार करना- शहरी योजना, विकास और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक, सांस्कृतिक आदि विरासत तैयार करना।
- जन सुविधाएं, शौचालय, पानी, मुहल्लों में बिजली और पर्यटन सुविधाएं बेहतर करने में हालिया तकनीकों के उपयोग जैसे सफाई संबंधी सेवाओं पर फोकस के साथ बुनियादी सेवा मुहैया कराने पर अमल।
- विरासत आधारित उद्योग के लिए स्थानीय क्षमता में बढ़ोतरी।
- पर्यटन और सांस्कृतिक सुविधाओं के बीच असरदार संयोजन तैयार करना। साथ ही, प्राकृतिक और निर्मित विरासत का संरक्षण।
- ऐतिहासिक इमारतों में फेरबदल के लिए उपयुक्त तकनीक के उपयोग समेत शहरी विरासत के अनुकूल पुनर्वास और रखरखाव।
- अनुकूल शहरी पुनर्वास के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी बनाना और उसका प्रबंधन करना।
- संबंधित पक्षों के बीच आजीविका के संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख ठोस आर्थिक गतिविधियों का विकास और बढ़ावा। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों को सुगम बनाने और सांस्कृतिक ठिकाने विकसित करने समेत उनके बीच जरूरी कौशल विकास का मामला भी शामिल है।
- आधुनिक आईसीटी उपकरणों के इस्तेमाल के साथ शहरों को सूचनाप्रद बनाना और सीसीटीवी आदि जैसे आधुनिक जांच और सुरक्षा उपकरणों के साथ शहरों को सुरक्षित बनाना।
- सुगमता (शारीरिक लिहाज से) और बौद्धिक उपलब्धता (डिजिटल विरासत और ऐतिहासिक ठिकानों/पर्यटन नक्शा और रूट की जीआईएस मैपिंग) को बढ़ाना।

यह योजना इस मकसद के लिए पहचान किए गए 12 शहरों में लागू की गई है। इनमें अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलान्कन्नी और वारंगल शामिल हैं। ❑

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

अमृत

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

भारत सरकार ने अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरुआत की है, जिसका मकसद पानी की आपूर्ति, नालियां, शहरी परिवहन पार्क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है, ताकि सभी लोगों खास तौर पर गरीब और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। मिशन का प्रमुख ध्यान आधारभूत संरचना के निर्माण पर है, जिसका सीधा संबंध नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं के प्रावधान से है।

'अमृत' का मकसद (i) यह सुनिश्चित करना है कि हर घर में पाइप के पानी और नाली का कनेक्शन हो (ii) हरियाली और बेहतर रखरखाव वाली खुली जगह विकसित कर शहरों के सुविधाजनक पहलुओं को बढ़ाना (iii) सार्वजनिक परिवहन की तरफ बढ़ते हुए या बिना मोटर वाले परिवहन यानी पैदल और साइकल की सवारी के लिए सुविधाओं का निर्माण कर प्रदूषण को कम करना।

मिशन का मकसद 500 शहरों को अपने दायरे में शामिल हैं। इस मिशन के तहत वैसे शहरों को शामिल किया गया है, जो अधिसूचित नगर निकाय हैं और जिनकी आबादी 1 लाख से भी ज्यादा है। अमृत के लिए पांच साल में (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20) 50,000 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है और इस मिशन का संचालन केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत किया जा रहा है।

परियोजना के फंड को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच बराबर-बराबर बंटवारे के फॉर्मूले के तहत बांटा गया है। इसके तहत हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित शहरों को 50:50 की भारिता दी जाती है।

मिशन के घटक

अमृत के घटकों में क्षमता निर्माण, सुधार को लागू करना, पानी की आपूर्ति, नालियों और मल का प्रबंधन, पानी निकासी, शहरी परिवहन और हरीभरी जगहों और पार्क का विकास। नियोजन की प्रक्रिया के दौरान स्थानीय शहरी इकाइयां (यूएलबी) भौतिक आधारभूत संरचना के अवयवों में कुछ अच्छे पहलुओं को शामिल करने के लिए हरमुमकिन प्रयास करते हैं। मिशन के अवयवों के बारे में नीचे बताया गया है:

पानी की आपूर्ति: जलापूर्ति प्रणाली में पानी की मौजूदा आपूर्ति को बढ़ाना, पानी के शुद्धीकरण वाले संयंत्र (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) और इसकी मीटर प्रणाली में सुधार करना।

ii. पानी के शुद्धीकरण वाले संयत्रों समेत पानी की आपूर्ति की पुरानी प्रणाली का पुनर्विकास। iii. जल निकायों का नवीनीकरण, खास तौर पर पीने के पानी की आपूर्ति और भूजल पुनर्भरण iv. दिक्कत वाले इलाकों, पहाड़, तटीय शहरों और वैसे जगहों पर पानी की आपूर्ति का विशेष इंतजाम करना जहां पानी की गुणवत्ता (मसलन आर्सेनिक, फ्लोराइड) की समस्या है।

नाली, पानी की निकासी: नाली, पानी निकासी की मौजूदा प्रणाली और कचरा परिशोधन संयंत्र में बढ़ोतरी समेत विकेंद्रीकृत, नेटवर्क वाला भूमिगत जल निकासी प्रणाली। ii. पुरानी जल निकासी और परिशोधन संयंत्र का पुनर्वास। iii. बेहतर मकसद से पानी की राइसाइक्लिंग और बेकार हो चुकी पानी का फिर से इस्तेमाल।

मल: i. मल कीचड़ प्रबंधन- किफायती तरीके से सफाई, परिवहन और शोधन।

ii. नाली और सेप्टिक टैंक की यांत्रिक और जैविक सफाई और संचालन संबंधी लागत की पूरी रिकवरी।

बाढ़ वाले पानी की निकासी : i. बाढ़ को कम करने या खत्म करने के लिए नालों का निर्माण और सुधार।

शहरी परिवहन : i. अंतर्देशीय जलमार्गों के लिए जहाजों की आवाजाही (बंदरगाह/खाड़ी आधारभूत संरचना को छोड़कर) और बस ii. फुटपाथ/पैदल पथ, पगडंडी, फुट ओवर-ब्रिज और गैर-मोटरीकृत परिवहन के लिए सुविधाएं (साइकिल)। ❑

स्रोत: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186363, https://www.hridayindia.in/, http://mohua. gov.in/cms/amrut.php

जल संसाधन और गंगा नवीनीकरण- हाल की बड़ी उपलब्धियां

राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन (एनएमसीजी):

गंगा सफाई :- नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 24,672 करोड़ की कुल 254 परियोजनाएं नाली, कचरा संबंधी आधारभूत संरचना, घाट और शवदाह गृह के विकास, नदी के किनारे के विकास, नदी के तल की सफाई, संस्थागत विकास, जैवविविधता का संरक्षण, वन-रोपण, ग्रामीण स्वच्छता और सार्वजनिक भागीदारी।

नदी के तट के विकास के लिए 145 घाटों और 53 शवदाह गृहों पर काम चल रहा है और इसके मार्च 2019 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

अगर हम ग्रामीण सफाई मोर्चे पर बात करें तो गंगा नदी के तट पर सभी 4,465 गांव को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाया जा चुका है और केंद्रीय पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 10,83,688 घरों में निजी शौचालय बनाए गए हैं। राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन ने इसके लिए केंद्रीय पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय को 829.0 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जैवविविधता संरक्षण और डॉलफिन, घड़ियाल, ऊदबिलाव, जल पक्षियों और मछली पालन समेत गंगा नदी की जलीय जैवविविधता के लिए कुल 6 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 2 पूरी हो चुकी हैं। गंगा के मैदान और घाटी में वणरोपन कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2018-19 के लिए गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्य वन विभागों को 190.3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 (30.11.2018 तक) के दौरान राष्ट्रीय गंगा सफाई मिशन ने इस मद में खर्च समेत कार्यक्रम के अमल के लिए राज्यों, केंद्रीय सार्वजनिक इकाइयों को 1,532.59 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

बांध परियोजनाएं:-

शाहपुर कंडी परियोजना: पंजाब में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध परियोजना पर फिर से काम शुरू करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के तत्वावधान में पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्यों के बीच 8 सितंबर 2018 को समझौता हुआ। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। इस परियोजना को लागू करने के लिए 485.38 करोड़ (सिंचाई भाग के लिए) की केंद्रीय सहायता के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने 6 दिसंबर, 2018 को मंजूरी दी थी। यह परियोजना जून 2022 तक पूरी हो जाएगी।

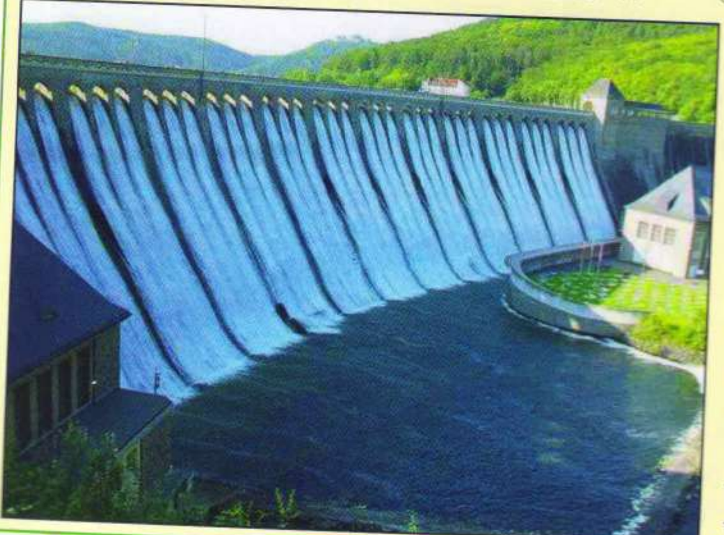

इस परियोजना से पंजाब राज्य में अतिरिक्त 5,000 हेक्टेयर, जम्मू-कश्मीर राज्य में 32,173 हेक्टेयर और पंजाब में यूबीडीसी प्रणाली के तहत 1.18 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए संभावना तैयार करने में मदद मिलेगी। नतीजतन, यह परियोजना रावी नदी के कुछ पानी को कम करने में मदद करेगी, जो फिलहाल माधोपुर जल शीर्ष तंत्र प्रवाह के जरिये बर्बाद किया जा रहा है।

लखवर परियोजना: यमुना की ऊपरी घाटी में 3966.51 करोड़ की बहुद्देशीय लखवर परियोजना के निर्माण के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, जहाजरानी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच 28 अगस्त 2018 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

लखवर परियोजना के तहत उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहरी गांव में यमुना नदी के पास 330.66 एमसीएम भंडारण क्षमता का 204 मीटर ऊंचा बांध बनाने का प्रस्ताव है। इस भंडारण से 33,780 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा और नदी से जुड़े 6 राज्यों में घरेलू, पीने और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए 78.83 एमसीएम जमीन की उपलब्धता मिल सकेगी।

परियोजना 300 मेगावॉट की बिजली भी पैदा करेगी। परियोजना का कार्यान्वयन मेसर्स उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएल) द्वारा किया जाएगा।

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के बचे काम को पूरा किया जाना, बिहार और झारखंड:

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना, बिहार और झारखंड के बाकी काम को पूरा करने का जिम्मा उठाया है, जो 1993

में रुक गया था। केंद्रीय कैबिनेट ने इस परियोजना की शुरुआत से तीन वित्त वर्षों के लिए अगस्त 2017 में 1622.27 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

परियोजना का मकसद बिहार में सूखे की मार झेलने वाले इलाकों मसलन औरंगाबाद और गया जिले, झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों की 39,801 हेक्टेयर जमीन के लिए अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था मुहैया कराना है।

बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (ड्रिप): 2018-19 में जलप्लावित ठिकानों की तैयारी के लिए 38 बांधों पर विश्लेषण किया गया। वेब आधारित बांध स्टॉक प्रबंधन सॉफ्टवेयर- धर्म को बनाया गया है।

नदियों को जोड़ना:

राष्ट्रीय परिदृश्य योजना (एनपीपी) प्रस्ताव:

नदियों को जोड़ने से जुड़ी तीन प्राथमिक परियोजनाओं के संबंध में तीन डीपीआर पूरी हो चुकी है- केन-बेतवा को जोड़ने की परियोजना (चरण-1 और 2), दमनगंगा-पिंजल संयोजन परियोजना और प्रतापी-नर्मदा संयोजन परियोजना। साथ ही, परियोजना रिपोर्ट कार्यान्वयन के लिए तैयार है।

राज्य के भीतर संयोजन के प्रस्ताव:

बिहार राज्य के बूढ़ी गंडक-नून बाया-गंगा और कोसी-मेची को जोड़ने के प्रस्ताव, तमिलनाडु के पोन्नियार-पलार और महाराष्ट्र के वैनगंगा (जोशीखुर्द)-नालगंगा (पुराना-तापी) संयोजन का प्रस्ताव संबंधी डीपीआर पूरा हो चुका है और इसे संबंधित राज्यों को भेजा जा चुका है। महाराष्ट्र के दमनगंगा-गोदावरी और दमनगंगा-वैतर्णा-गोदावरी नदियों को जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के डीपीआर की तैयारी चल रही है।

कावेरी घाटी तक गोदावरी के पानी के मार्ग में बदलाव के लिए प्रस्ताव:

राष्ट्रीय परिदृश्य योजना (एनपीपी) के प्रायद्वीपीय हिस्से की योजना के तहत 9 संयोजन प्रणाली (i) महानदी-गोदावरी (ii) इन्चामपल्ली - नागार्जुनसागर संयोजन (iii) इन्चामपल्ली - पुलिचिंताला संयोजन महानदी और गोदावरी नदियों (iv) पोलावरम - विजयवाड़ा लिंक (आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से कार्यान्वित किया गया) (v) अलमाट्टी - पेन्नार संयोजन (vi) श्रीशैलम - पेन्नार संयोजन (vii) नागार्जुन - सोमसिलाल संयोजन (viii) सोमसिला - एनीकट संयोजन और (ix) कावेरी-वैगी - गुंडार का कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगी और गुंडार घाटी से संयोजन के जरिये 20,796 एमसीएम पानी महानदी और गोदावरी नदी को स्थानांतरित किया जाना है। ❑

न्यू इंडिया के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

निर्मल गंगा सुनिश्चित करने की दिशा में पहल

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 254 परियोजनाओं के लिए 24,672 ₹ करोड़ स्वीकृत

3076 एमएलडी* की क्षमता के नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट(एसटीपी) हेतु 131 परियोजनाओं को स्वीकृति

887 एमएलडी की क्षमता वाले एसटीपी और 4942 कि.मी. सीवर के नेटवर्क का पुनरूद्धार

10,83,688 घरों में शौचालय का निर्माण और 4465 गांवों को ओडीएफ बनाया गया

*मिलियन्स ऑफ लीटर पर डे

1 जनवरी 2019 तक

उड़ान-हवाई संपर्क को नया आयाम

उषा पाढ़ी

'उड़ान' की शुरुआत करीब दो वर्ष पहले हुई थी। केंद्रीय सरकार की फ्लैगशिप क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' अब भारत के छोटे शहरों में लोगों के लिये कम लागत पर विमान सेवाएं प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन चुकी है। योजना के तहत, इन दो वर्षों में पहली बार 35 टियर-2 और टियर-3 शहरों के लोगों को (दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार) विमान सेवाओं से जोड़ा जा चुका है। जैसा कि, पर्यटक स्थलों और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थानों को जोड़ने के लिये योजना की नई परिकल्पना की शुरुआत हो चुकी है, अतः अब योजना से जुड़ी उन मूल्यवान बातों पर ध्यान दिये जाने का समय है जो नागर विमानन संचालकों के लिये उभरकर सामने आई हैं।

पिछले 10 वर्षों से भारत में विमान यातायात में तीन गुणा वृद्धि हुई है और यह घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान सेवाओं की दृष्टि से दुनिया के तीन सर्वोच्च देशों में जगह बनाने की क्षमता रखता है। भारतीय विमानन क्षेत्र की प्रगति को महत्वपूर्ण ढंग से प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र की प्रकृति का अर्थव्यवस्था पर कई गुणा असर होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के एक अध्ययन के अनुसार, निर्गत गुणांक और रोज़गार गुणांक क्रमशः 3.25 और 6.10 हैं। 2016 में भारत सरकार ने विभिन्न विमानन उप क्षेत्रों जैसे कि एअरलाइन्स, विमानपत्तन, कार्गो आदि के अनुकूल विकास के लिये परिस्थितियां उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (एनसीएपी) की शुरुआत की थी। बड़े पैमाने पर आम जनता के लिये किफायती विमान सेवाएं प्रदान करने और 2022 तक 30 करोड़ तथा 2027 तक 50 करोड़ घरेलू टिकटिंग में समर्थता के लिये परिस्थितियों के निर्माण के लिये नीतियां बनाई गई।

सुविधाजनक हवाई यात्रा

एनसीएपी के अधीन छोटे शहरों में आम आदमी के लिये विमान यात्रा सुविधाजनक और किफायती बनाने के लिये **उड़ान** (उड़े देश का आम नागरिक) आधार स्तम्भ है और इसके जरिए क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में देश में 70 प्रतिशत विमान यातायात केवल मेट्रो शहरों की आवश्यकताएं पूरी करता है। आज़ादी के बाद से भारत में हाल के दिनों तक केवल 67 हवाई अड्डों पर निर्धारित व्यावसायिक प्रचालन होता था। उड़ान से हवाई अड्डों के उन्नयन और एअरलाइन्स को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करके प्रचालन लागत में कमी से बुनियादी ढांचे तथा किफायत से जुड़े मुद्दों की चुनौतियां का समाधान किया गया है और इस तरह विमान टिकटें किफ़ायती हो गई हैं। अतः यह स्कीम इस दिशा में महत्वपूर्ण है कि भारतीय विमानन क्षेत्र की सफलता की कहानी हर किसी से जुड़ी है और टियर-II तथा टियर-II शहर भी विमानन क्रांति में शामिल हो गये हैं। 2017 में उड़ान की शुरुआत से लेकर अब तक 61 नये सेक्टर जोड़े जा चुके हैं जिससे विमानन नेटवर्क की ताक़त बढ़ गई है। इन मार्गों पर दस लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं और पहली बार उड़ान भरने वालों को जोड़ने के साथ ही विमानन बाज़ार से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। छोटे कस्बों को मेट्रो शहरों से जोड़ते हुए नये नगरीय जोड़े स्थापित किये गये हैं, जिससे क्षेत्रीय बाज़ार में काफी उछाल आया है।

उड़ान एक अभिनव मॉडल पर काम करती है जो कि एक हवाई अड्डे को प्रचालन के लिये तैयार करने के लिये व्यापक संसाधनों की तैनाती और निर्माण-पूर्व तैयारी अवधि की ज़रूरत से गुजरना होता है। योजना में ऐसे छोटे शहरों में मौजूदा हवाई पट्टियों की बहाली और उन्नयन की व्यवस्था है जहां पर उड़ान के तहत विमान सेवाएं आरंभ की जायेंगी। प्रचालन संबंधी लागतों में कमी लाने के लिये एयरलाइन्स के लिये केंद्र, राज्यों और विमानपत्तन संचालकों से रियायतें प्रदान

श्रीमती उषा पाढ़ी नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव हैं। ईमेल: usha.padhee@nic.in

2017 में उड़ान की शुरुआत से लेकर अब तक 61 नये सेक्टर जोड़े जा चुके हैं जिससे विमानन नेटवर्क की ताक़त बढ़ गई है। इन मार्गों पर दस लाख से अधिक यात्री यात्रा कर चुके हैं और पहली बार उड़ान भरने वालों को जोड़ने के साथ ही विमानन बाज़ार से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। छोटे कस्बों को मेट्रो शहरों से जोड़ते हुए नये नगरीय जोड़े स्थापित किये गये हैं, जिससे क्षेत्रीय बाज़ार में काफी उछाल आया है।

न्यू इंडिया के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

विमान क्षेत्र की ऊंची उड़ान

की जाती हैं। इस नये दृष्टिकोण से न केवल छोटे कस्बों में सीमित जनसंख्या आधार के लिये विमान सेवाएं उपलब्ध हुई हैं, इससे उनके लिये सेवाएं किफ़ायती भी हुई हैं।

क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान की प्रमुख विशेषताएं

- क्षेत्रीय संपर्क योजना- उड़ान का उद्देश्य विमान सेवाओं से अब तक अछूते मार्गों में विमान सेवाएं शुरू करने के लिये क्षेत्रीय इलाकों को जोड़ना, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और आम लोगों के लिये विमान सेवाएं किफायती बनाना है।
- क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान में, जो कि 10 वर्षों की अवधि के लिये प्रचालन में रहेगी, मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों की बहाली के जरिये संपर्क बढ़ाने की व्यवस्था है।
- प्रचालन रहित/कम प्रचालन वाले हवाई अड्डों से प्रचालन अड्डा शुरू करने के लिये केंद्रीय, राज्य सरकारों और विमानपत्तन प्रचालकों से रियायतों तथा चुनिंदा एअरलाइन्स को व्यवहार्य अंतर वित्तपोषण के तौर पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, ताकि यात्री किरायों को किफायती बनाये रखा जा सके।
- क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान एक मांग संचालित योजना है जहां इच्छुक एअरलाइन्स और हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाता है।
- क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के चयनित एअरलाइन ऑपरेटर को फिक्स्ड विंग एअरक्राफट के जरिए प्रचालन हेतु क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान में न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 आरसीएस सीटें उपलब्ध करानी होंगी। हेलीकॉप्टरों के लिये 13 यात्री तक सभी सीटें आरसीएस सीटें मानी जायेंगी।

उड़ान - सभी हितधारकों के लिये लाभप्रद

नागरिक	एअरलाइन्स
• कनेक्टिविटी • किफायती • रोज़गार	• अवलंबी : नये फीडर मार्गों का सृजन नये यात्रियों को विमान सेवाओं से जोड़ना। • स्टार्ट-अप्स : क्षेत्रीय एअरलाइन्स के तौर पर उत्कृष्ट बिज़नेस मॉडल सृजित करने के नये अवसर
राष्ट्रीय सरकार	**एअरपोर्ट ऑपरेटर**
• क्षेत्रीय विमानन बाज़ार में जबर्दस्त शुरुआत। • मेटकॉफ लॉ : नये क्षेत्र जुड़ने से नेटवर्क की ताक़त बढ़ी।	• विस्तार के अवसर। • मौजूदा हवाई अड्डे के लिये अधिक यात्रीगण।
क्षेत्र	**मूल उपस्कर विनिर्माता**
• अधिक व्यापार और वाणिज्य। • पर्यटन सर्किट्स। • दूरदराज के क्षेत्रों का विकास।	• भारत में एक दशक में विमानों की संख्या 450 से बढ़कर 1,200 पहुंचने की आशा है। • घरेलू विनिर्माताओं की वृद्धि, भारत एक निर्यात हब के तौर पर है।

- विभिन्न चरण लंबाई/उड़ान अवधि के मार्गों के लिये, एक फिक्स्ड विंग एअरक्राफट पर लगभग 500 कि.मी. की एक घंटे की यात्रा के लिये अथवा हेलीकॉप्टर की 30 मिनट की यात्रा के लिये, समानुपातिक मूल्य के साथ, लगभग 2500 रुपये किराया होगा।
- आरसीएस मार्ग पर, प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, प्रति सप्ताह न्यूनतम अंतराल में तीन और अधिकतम सात उड़ानें चलाई जाएंगी।

यद्यपि इस योजना में कार्यान्वयन से जुड़ी व्यापक चुनौतियां हैं। योजना का शुरुआती फ़ोकस एक बोली प्रक्रिया के जरिए एअरलाइन ऑपरेटरों का चयन करना था जो कि पारदर्शी और निष्पक्ष हो। यह एअरलाइन्स के मध्य विश्वास पैदा करने की कुंजी थी। उड़ान के पहले दो दौर में, 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीकाप्टरों को भारत के विमानन मानचित्र में शामिल किया गया है। योजना का तीसरा दौर पर्यटन और वाणिज्य को बढ़ावा देने में योगदान के लिये महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और प्राथमिकता वाले स्थानों को जोड़ने वाले मार्गों का आबंटन करने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। बहुत से स्वीकृत मार्ग उत्तर-पूर्वी राज्यों के साथ-साथ वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को जोड़ेंगे। भले ही ये गुवाहाटी से पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश) हो अथवा देहरादून से पिथौरागढ़ (उत्तराखंड), यात्रा समय में इतनी जबर्दस्त कमी आयेगी कि इससे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियां बदल जायेंगी।

किफ़ायती विमान किराये से न केवल व्यापार के लिये बल्कि पर्यटन और चिकित्सा सुविधाओं के लिये यात्राएं सुविधाजनक हो जायेंगी। लेकिन, योजना के अधीन मार्गों का आबंटन यात्रा की केवल शुरुआत है। हवाई अड्डों को तैयार करना, एअरलाइन्स की तैयारी तथा राज्य सरकारों की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत से कर्ताधर्ता हैं जिन्हें अपनी व्यापक तौर पर ज़िम्मेदारी पूरी करनी होंगी।

कार्यान्वयन तंत्र

यद्यपि ज़्यादातर राज्य सरकारें इस दिशा में आगे आई हैं और भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं, उनकी सीमित क्षमताओं के लिये पेशेवर संगठनों के समर्थन की जरूरत है। नागर विमानन सेक्टर इसकी संवेदनशील प्रकृति के कारण बहुत अधिक विनियमित क्षेत्र है। हवाई अड्डों की लाइसेंसिंग एक कठिन प्रक्रिया है। संरक्षा और सुरक्षा सर्वोच्च होती है और प्रचालन में अपेक्षित विनियमों का पालन करना होगा। इन चुनौतियों को दूर करने के लिये, कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) हवाई अड्डों का विकास करने, लाइसेंसिंग के लिये प्रलेखन, सुरक्षा और आग बुझाने के उपकरणों आदि की खरीद में राज्य सरकारों को ज़रूरी सहयोग प्रदान कर रही हैं। कुछेक रक्षा हवाई अड्डों में, रक्षा मंत्रालय के परामर्श से मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपीज) तैयार की गई हैं। यद्यपि इसमें काफी समय लग गया है, लेकिन उड़ान निजी ऑपरेटर्स को उड़ान स्कीम से जुड़ी विमान सेवाओं में भागीदार बनने और इससे संबंधित विमान सेवाओं को लाभ पहुंचाने के लिये प्रेरित करने में सफल रही है। आज महाराष्ट्र के नांदेड़ और कर्नाटक में विद्यानगर उड़ान के अधीन शानदार उदाहरण बन गये हैं। पर्यटन स्थलों के लिये क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) लागू करने और राज्य सरकारों के अनुरोध के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिये इसका विस्तार करने की योजना की पहले ही शुरुआत की जा चुकी है। इस पहल से और अधिक चुनौतियों के साथ-साथ नये अवसर खुलेंगे जिन पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार करना अपेक्षित है।

योजना के अधीन कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों में न केवल हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के लिये निगरानी और सहायता करना शामिल है बल्कि चयनित एअरलाइन्स और हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों के लिये विमान संचालन परमिट प्राप्त करने के काम में सहायता करना भी शामिल है। कुछ छोटे एअरलाइन ऑपरेटर, जिन्होंने उड़ान के अधीन बोली लगाई थी, अपनी सीमित क्षमताओं के कारण जबर्दस्त कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उड़ान के लिये छोटी एअरलाइन्स के साथ काम करना बहुत आवश्यक है जिनमें दूरदराज के क्षेत्रों में क्षेत्रीय योजना को ले जाने की क्षमता है। एअरलाइन्स के लिये अर्हता प्राप्त क्रू की उपलब्धता भी एक प्रमुख चुनौती है और कुशल पेशेवरों के सृजन के लिये महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता है।

उड़ान के सकारात्मक परिणाम में 'नो-फ्रिल' हवाई अड्डों के लिये विनियामक ढांचा तथा 'विमान-केंद्रित सुरक्षा' दृष्टिकोण शामिल है जिससे अवसंरचना और प्रचालन संबंधी लागत में कमी आई है और इससे छोटे शहरों के लिये विमान सेवाओं की कनेक्टिविटी बनाये रखने में सहायता मिली है। यद्यपि योजना में मार्गों की निरंतरता को ध्यान में रखा गया है लेकिन ऐसी कुछेक स्थितियां हो सकती हैं जहां प्रचालन से जुड़े मुद्दों या मांग के अभाव के कारण उड़ान से संबंधित रूटों को बंद करना पड़ सकता है। व्यावहारिक रूप से उड़ान को बाज़ार गतिशीलता के जरिए प्रभावी तरीके से उलझनों से मुक्त करना होगा। योजना में अपेक्षित बदलावों के जरिए भविष्य की चुनौतियों और बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करना होगा। उड़ान सचमुच में आम आदमी को उड़ान भरने की दिशा में एक परिवर्तनकारी परिणाम प्रस्तुत करने की दिशा में अग्रसर हो रही है। ❑

न्यू इंडिया के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

किफायती हवाई यात्रा का वादा

उड़े देश का आम नागरिक (UDAN)

स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में 102 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, उड़ान (UDAN) के तहत इसमें 34 एयरपोर्ट्स और जोड़े गए हैं

उड़ान (UDAN) के तहत क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने हेतु अप्रयुक्त और कम इस्तेमाल हुए एयरपोर्टों के लिए ₹2,500/घंटे की दर से सब्सिडाइज किराया

1 जनवरी, 2019 तक

भारतमाला परियोजनाः राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र की सबसे बड़ी क्रांति

डी दास

सड़कें किसी भी देश के लिए जीवनरेखा की तरह हैं और रफ्तार को और तेज करने, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए इस जीवनरेखा को बेहतर और मजबूत होने की जरूरत है। हालांकि, भारत में सड़क का नेटवर्क 1951 के 3.99 लाख किलोमीटर से बढ़कर 2016 में 56.03 किलोमीटर तक पहुंच गया, लेकिन इन सड़कों का बड़ा हिस्सा दो लेन वाला है, जबकि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का 70 फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा दो लेन या इससे कम चौड़ा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए नीतिगत स्तर पर पहली बार प्रमुख रूप से पहल 1998 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के दो हिस्से थे, जिसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत 5,846 किलोमीटर के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ना था, जबकि श्रीनगर से कन्याकुमारी और सिलचर से पोरबंदर तक 7,142 किलोमीटर तक का नेटवर्क तैयार करने का मामला था।

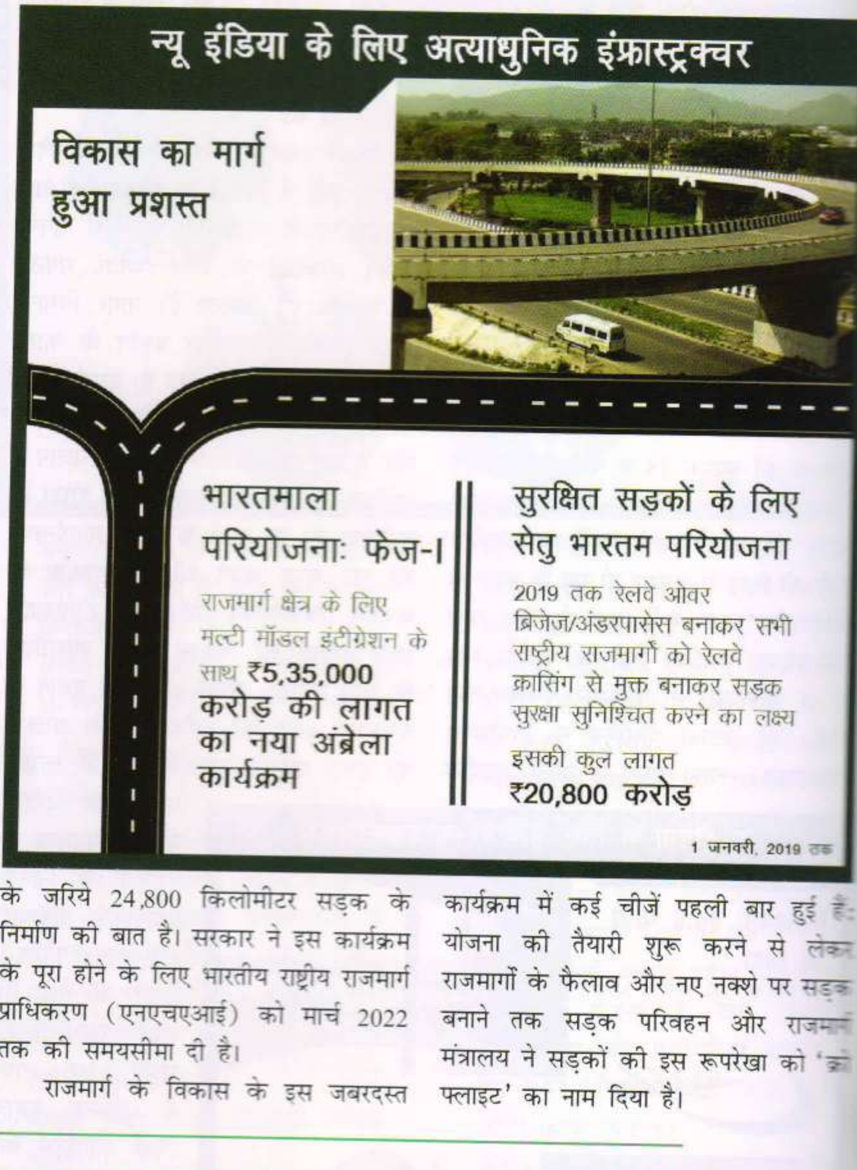

राष्ट्रीय राजमार्गों को उन्नत बनाने का दूसरा बड़ा क्रांतिकारी फैसला अक्टूबर 2017 में हुआ, जब केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी। इसमें 3.85 लाख करोड़ के अनुमानित खर्च के जरिये 24,800 किलोमीटर सड़क के निर्माण की बात है। सरकार ने इस कार्यक्रम के पूरा होने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को मार्च 2022 तक की समयसीमा दी है।

राजमार्ग के विकास के इस जबरदस्त कार्यक्रम में कई चीजें पहली बार हुई हैं: योजना की तैयारी शुरू करने से लेकर राजमार्गों के फैलाव और नए नक्शे पर सड़क बनाने तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों की इस रूपरेखा को 'ग्रीन फ्लाइट' का नाम दिया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को उन्नत बनाने का दूसरा बड़ा क्रांतिकारी फैसला अक्टूबर 2017 में हुआ, जब केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के पहले चरण को मंजूरी दी। इसमें 3.85 लाख करोड़ के अनुमानित खर्च के जरिये 24,800 किलोमीटर सड़क के निर्माण की बात है। सरकार ने इस कार्यक्रम के पूरा होने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को मार्च 2022 तक की समयसीमा दी है

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ईमेल: dashreporter@gmail.com

देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में भारी बदलाव के फैसले के पीछे मुख्य वजह यह थी कि 1998 में पेश किए गए एनएचडीपी में एक निश्चित स्तर का ठहराव आ गया था। लिहाजा, सड़क विकास को फिर से पारिभाषित करना और राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए विस्तार की योजना में बारीक नजरिया अपनाना जरूरी था।

प्रक्रिया

सरकार ने 'शुरुआती ठिकाना-मंजिल' की पहचान करने के बाद उच्च-घनत्व वाले गलियारों के बीच वैज्ञानिक रूप से सामानों की आवाजाही का विस्तार से अध्ययन किया।

चूंकि इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद माल ढुलाई के ट्रैफिक को सुधारना था, लिहाजा नया आर्थिक गलियारा विकसित करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई। अर्थव्यवस्था पर आवाजाही की सुविधा बेहतर होने के चौतरफा फायदे हैं। 'शुरुआती ठिकाना-मंजिल' से जुड़े अध्ययन ने भी एनएचडीपी के तहत चल रही मौजूदा परियोजनाओं के साथ आर्थिक गलियारे के एकीकरण पर विचार किया।

तीव्र गति से व्यापक परिवर्तन

इस अध्ययन ने इस बात को लेकर दिलचस्प तथ्य पेश किए कि किस तरह से कुछ गलियारों का अलग तरह का फैलाव आधारभूत संरचना संबंधी असंगति है। उदाहरण के तौर पर मुंबई-कोलकाता गलियारा (जो ओडिशा के रास्ते गुजरता है और इसका रास्ता काफी अहम है) दो लेन वाली सड़क ही है और इसमें काफी बदलाव भी हैं। अगर इस पूरे रास्ते को उन्नत बनाते हुए सभी जगहों पर चार लेन नहीं किया जाता है तो ट्रैफिक की आवाजाही निर्बाध नहीं होगी। इससे सीधा साबित हुआ कि पूरे देश में गलियारों पर विषमता को दूर करने की क्यों और कब जरूरत है।

यह मानते हुए कि नए गलियारे और फीडर रूट के विकास के अलावा एनएचडीपी के तहत पहले से तैयार सड़कों में भी पूरी तरह से सुधार की जरूरत है, शुरुआती कार्यक्रमों में बायपास, रिंग रोड, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क आदि बनाकर रास्तों के संकुचन को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इसके अलावा, भारत के निर्यात-आयात व्यापार के लिए सीमावर्ती और तटीय इलाकों में आधारभूत संरचना विकास की जरूरत को पूरा करने के लिए राजमार्ग विकास कार्यक्रम में रणनीतिक महत्व के आधार पर सीमा पर बेहतर सड़क के लिए व्यवस्था की गई है। खास तौर पर नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित व्यापार के ठिकानों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। तटीय सड़कों के विकास और बंदरगाह संपर्क वाली सड़क में बढ़ोतरी को सागरमाला कार्यक्रम से जोड़ा गया है।

घटक

आर्थिक गलियारा

माल ढुलाई की आवाजाही को बेहतर बनाने के मकसद से किए गए शुरुआती ठिकाना-मंजिल अध्ययन ने 44 नए आर्थिक गलियारे की पहचान की। इनमें से कुछ इस तरह हैं- मुंबई-आगरा, मुंबई-कोलकाता, चेन्नई-मदुरै, बिलासपुर-दिल्ली, पुणे-विजयवाड़ा,

इंदौर-जयपुर और अमृतसर-जामनगर। आने वाले वर्षों में आर्थिक गलियारों द्वारा 25 फीसदी माल ढुलाई किए जाने की उम्मीद है।

योजना के मुताबिक, राष्ट्रीय गलियारों (स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण व पूरब पश्चिम) के साथ ये गलियारे एशिया के नए राजमार्ग ग्रिड का निर्माण करेंगे। अनुमानों के मुताबिक, राष्ट्रीय और आर्थिक गलियारे अपने अंतर-गलियारों और फीडर रूट के साथ माल ढुलाई संबंधी 80 फीसदी ट्रैफिक ढोने में सक्षम होंगे।

अंतर गलियारा और फीडर रूट

शुरुआती ठिकाना और मंजिल संबंधी अध्ययन ने दो मौजूदा गलियारों और गलियारों के नेटवर्क के फीडर रूट (रास्ता) को जोड़ने वाले छोटे अंतर गलियारे के नेटवर्क की पहचान की है। इन सड़कों से मालों का 20 फीसदी हिस्सा गुजरने का अनुमान है। फीडर रूटों का विकास कर गलियारों के प्रभाव को और बेहतर किया जा सकता है।

राष्ट्रीय गलियारों की क्षमता में बेहतरी

राष्ट्रीय राजमार्गों में फिलहाल स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तरी दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा शामिल है, जहां से भारत के तकरीबन 35 फीसदी माल ढुलाई का काम होता है। इन सभी रास्तों को राष्ट्रीय गलियारा घोषित कर दिया जाएगा। देश के राजमार्ग नेटवर्क की जीवनरेखा होने के कारण इन मार्गों में ट्रैफिक में भारी बढ़ोतरी हुई है। छह राष्ट्रीय गलियारों में औसत ट्रैफिक 30,000 यात्री कार इकाइयों से भी ज्यादा है। भारतमाला कार्यक्रम के तहत इन सभी मार्गों को चौड़ा कर 6-8 लेन किया जाएगा। पिछले कुछ साल में इन राष्ट्रीय गलियारों में कई जगहों पर भयंकर जाम की स्थिति होती है और इससे आवाजाही पर बुरी तरह असर पड़ता है।

लिहाजा, जाम वाली इन जगहों से भीड़भाड़ को कम करने के लिए नया रिंग रोड और बायपास, (ऊंचा (इलिवेटेड) गलियारा बनाया जाएगा। इसके अलावा, माल को लादने और उतारने, बेहतर मॉडल स्थानातंरण के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारों के साथ-साथ महत्वपूर्ण आर्थिक ठिकानों पर मल्टीमॉडल पार्क विकसित किया जाएगा।

न्यू इंडिया के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

अधिक से अधिक सड़कें और राजमार्ग निर्माण से व्यापक बदलाव

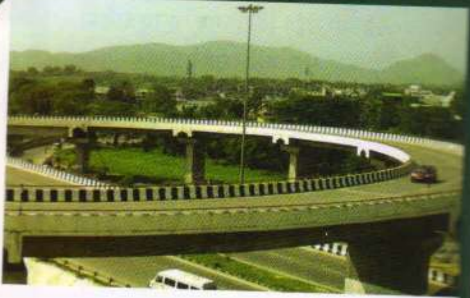

निर्माण और विकास के लिए 2,000 किलोमीटर की तटवर्ती संपर्क सड़कों की पहचान की गई

1 जनवरी, 2019 तक

क्र.	मद	लंबाई (किमी)	लागत (रुपये करोड़ में)
1.	आर्थिक गलियारे का विकास	9,000	1,20,000
2.	अंतर गलियारा और फीडर रूट विकास	6,000	80,000
3.	राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार (स्वर्णिम चतुर्भुज, एनएस-ईडब्ल्यू को 6 लेन किया जाना, संकरे ठिकानों को खत्म करना, लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास आदि)	5,000	1,00,000
4.	सीमा से सटी सड़कें और अंतरराष्ट्रीय संपर्क	2,000	25,000
5.	तटीय सड़कें और बंदरगाह संपर्क	2,000	20,000
6.	ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे	800	40,000
कुल		24,800	3,85,000
कार्यान्वयन के तहत मौजूदा परियोजनाएं		10,000	1,50,000

सीमा पर और अंतरराष्ट्रीय संपर्क वाली सड़कें

अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास तकरीबन 3,300 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और चौड़ीकरण किया जाएगा। रणनीतिक रूप से अहमियत को ध्यान में रखते हुए इन सड़कों के निर्माण का फैसला किया गया है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ निर्यात-आयात में सहूलियत की खातिर [illegible] के प्रमुख राजमार्गों को अंतरराष्ट्रीय [illegible] ठिकानों से जोड़ने के लिए तकरीबन 2,[illegible] किलोमीटर के सड़क की जरूरत है।

तटीय और बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़कें

भारतमाला कार्यक्रम के तहत तटों के आसपास करीब 2,100 किलोमीटर सड़कों की पहचान निर्माण के लिए की गई है। [illegible] सड़कें तटीय क्षेत्र के पर्यटन और औद्योगिक दोनों तरह के विकास को बढ़ावा देंगी। [illegible] सड़के निर्यात-आयात व्यापार के [illegible]

बंदरगाहों से संपर्क भी बेहतर करेंगी। इसमें राज्य सरकार के मालिकाना हक वाले और निजी बंदरगाहों के बीच संपर्क बेहतर करने पर जोर होगा।

ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे का विकास

भारतमाला कार्यक्रम में वैसे राष्ट्रीय और आर्थिक गलियारों के पास एक्सप्रेसवे बनाने की बात है, जहां ट्रैफिक 50,000 यात्री कार ईकाई पार कर चुका है और कई ठिकानों पर जाम लगता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास के लिए ऐसे तकरीबन 1,900 किलोमीटर सड़कों की पहचान की गई है। दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाले इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सक्रियता बढ़ गई है। एक्सप्रेसवे में प्रवेश और निकास के सीमित बिंदु हैं और मुख्य रास्ते पर कोई ट्रैफिक सिग्नल या टोल प्लाजा नहीं है, जिससे ट्रैफिक की तेज और निर्बाध रफ्तार सुनिश्चित हो सकेगी।

यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की मंजूरी और काम शुरू होने में किसी तरह की देरी नहीं हो, सरकार ने इस संबंध में फैसला लेने और परियोजनाओं को मंजूर करने के लिए एनएचएआई बोर्ड को अधिकार दिया है। एनएचएआई बोर्ड एक अंतर-मंत्रालय इकाई है, जिसमें राजमार्ग और वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और राजमार्ग प्राधिकरण के प्रतिनिधि हैं। इस दिशा में अब तक हुई प्रगति संतोषजनक है।

फायदे

भारतमाला परियोजना के एक बार लागू हो जाने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल ढुलाई और मुसाफिरों की आवाजाही में ट्रैफिक के कारण होने वाली दिक्कतें दूर होंगी। भारतमाला के तहत पहचान किया गया नेटवर्क देश में 80 फीसदी अंतर-जिला माल ढुलाई की आवाजाही को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा नेटवर्क देश के 550 जिलों को जोड़ेगा, जिनकी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तकरीबन 90 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा, गलियारों के अगल-बगल मुसाफिरों के लिए सुविधाएं भी होंगी, जिससे उन्हें आवाजाही में आराम होगा।

आर्थिक गलियारों के विकास और संबंधित अंतर गलियारा और फीडर रूट से गाड़ियों की औसत रफ्तार में तकरीबन

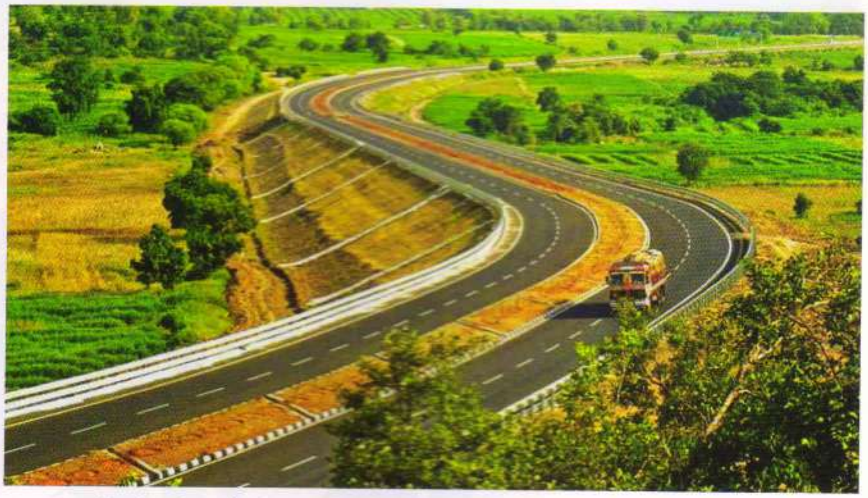

20-25 फीसदी की बढ़ोतरी मुमकिन होगी। टोल प्रणाली के नए स्वरूप के कारण भी राजमार्गों पर औसत गति में तेजी आएगी। ऐसे में माल ढोने वाली गाड़ियों को तीन प्रमुख फायदे होंगे: गाड़ियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सकेगा, गाड़ियां ज्यादा पैसे कमाएंगी और माल ढुलाई की लागत प्रति किलोमीटर कम होगी। सरकार के अनुमान के मुताबिक, एक बार नेटवर्क विकसित हो जाने के बाद यह अर्थव्यवस्था में पूरी आपूर्ति शृंखला की लागत में 5-6 फीसदी की कटौती मुमकिन करेगा।

इसके अलावा, पहले चरण में 24,800 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नत बनाए जाने से निर्माण के चरण के दौरान तकरीबन 10 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा होने की संभावना है। साथ ही, आर्थिक गलियारा नेटवर्क के विकास के कारण तकरीबन 2.2 करोड़ स्थायी रोजगार पैदा होने की संभावना है।

कार्यक्रम के लिए फंडिंग

सरकार ने कुल 6.92 लाख करोड़ के खर्च का अनुमान किया है। इसमें भारतमाला के तहत चल रहे मौजूदा कार्य के पूरा होने से जुड़ी 3.85 लाख करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। इस फंड का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा यानी 2.37 लाख करोड़ ईंधन पर कर से आएगा और 60,000 करोड़ रुपये बजटीय समर्थन के तौर पर मिलेंगे। एनएचएआई ने पहले ही पूरी हो चुकी परियोजनाओं के मुद्रीकरण का काम शुरू कर दिया है और उसका इरादा 34,000 करोड़ रुपये जुटाना है। यह योजना 'टोल ऑपरेट ट्रांसफर (टीओटी)' के नाम से जानी जाती है, जिसका मतलब यह है कि प्राइवेट खिलाड़ियों को कुछ साल के लिए टोल इकट्ठा करने के लिए पूरी सड़क की बोली लगाई जाती है। इस काम को हासिल करने के लिए प्राइवेट खिलाड़ी एनएचएआई को तत्काल भुगतान करते हैं। वे राजमार्गों की संबधित लंबाई के रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होते हैं।

सरकार को उम्मीद है कि वह अपने कुल टोल संग्रह से करीब 46,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। एनएचएआई बाजार से उधारी के रूप में और 2.09 लाख रुपये जुटाएगा और निजी निवेश 1.06 लाख रुपये होने का अनुमान है। ❑

संविधान (103वां) संशोधन अधिनियम, 2019

राष्ट्रपति ने संविधान बिल (124वें संशोधन) 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान अमल में आ गया है। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना में 14 जनवरी से संविधान (103वां) संशोधन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के प्रभावी होने की बात कही गई है। अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है। इसके तहत एक उपखंड जोड़ा गया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए राज्यों को विशेष प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। ❑

भारतीय रेलवे : आमूल चूल परिवर्तन की ओर

दीपक राज़दान

भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में इसमें जबरदस्त बदलाव आए हैं। इसने देश के हर कोने में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। यह कार्य बेहद तेजी से हुआ है और इसके अंतर्गत यात्री परिवहन और माल ढुलाई की सेवाओं को सुरक्षित बनाने और समय की पाबंदी पर जोर दिया गया है।

कुल 63 हजार किलोमीटर लंबे भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क के तहत 22 हजार ट्रेनें चलाई जाती हैं जो रोजाना 15 लाख लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाती-ले जाती हैं। इसके लिए रेल पटरियों, पुलों, सिगनलिंग और दूरसंचार जैसी विभिन्न प्रणालियों को एकदम चुस्त-दुरुस्त रखने की आवश्यकता पड़ती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने रेलवे में निवेश को जोरदार तरीके से बढ़ाया है और उसे प्रोत्साहन दिया है ताकि मौजूदा सुविधाओं को बनाए रखने के साथ-साथ उनकी बढ़ती आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके। पिछले पांच साल में रेलवे का आबंटन बढ़कर 5.30 लाख करोड़ रुपये किया जा चुका है।

भारतीय रेलवे आज बड़ी तेजी से भारत को जोड़ रही है। नयी रेल लाइनों का काम पूरा करने की रफ्तार में 59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2009-14 के दौरान रोजाना औसतन 4.1 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गयी थीं जबकि 2014-18 के दौरान 6.53 किलोमीटर दैनिक की औसत दर से रेल लाइनें बनी हैं। वर्तमान सरकार के शासन के पहले चार वर्षों में रेलवे के वार्षिक पूंजीगत खर्च में जबरदस्त वृद्धि हुई है और यह 2009-2014 के औसत खर्च की तुलना में दुगने से भी अधिक हो गया है।

दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक रेल लाइनों में भारी बदलाव आया है। कन्याकुमारी-नागरकोइल-तिरुअनंतपुरम सेक्शन पर 3,618 करोड़ रुपये लागत से 349 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को दोहरा करने के साथ-साथ इसके विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से जारी है जिससे यातायात के भारी दबाव को कम करने में मदद मिली है।

पूर्वोत्तर में रेल नेटवर्क विस्तार

पूर्वोत्तर के सातों राज्यों-असम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के साथ रेल संपर्क स्थापित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 29 नवंबर, 2016 को गुवाहाटी से मेघालय में

दीपक राज़दान वरिष्ठ पत्रकार हैं और नई दिल्ली से प्रकाशित द स्टेट्समैन में संपादकीय परामर्शदाता हैं। ईमेल: deepakrazdan50@gmail.com

कुल 63 हजार किलोमीटर लंबे भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क के तहत 22 हजार ट्रेनें चलाई जाती हैं जो रोजाना 15 लाख लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाती-ले जाती हैं। इसके लिए रेल पटरियों, पुलों, सिगनलिंग और दूरसंचार जैसी विभिन्न प्रणालियों को एकदम चुस्त-दुरुस्त रखने की आवश्यकता पड़ती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने रेलवे में निवेश को जोरदार तरीके से बढ़ाया है और उसे प्रोत्साहन दिया है ताकि मौजूदा सुविधाओं को बनाए रखने के साथ-साथ उनकी बढ़ती आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके

डिब्रूगढ़ के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 कि.मी. लंबा देश का सबसे लंबा बोगीबील रेल और सड़क पुल चालू हो जाने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक और संपर्क स्थापित हो गया है। 25 दिसंबर, 2018 को प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर तीन लेन वाली सड़क से जुड़ने के साथ ही यह पुल 74 कि.मी. लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क कायम करता है।

मेंदीपाथर के लिए पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस तरह मेघालय भी देश के रेल मानचित्र में जुड़ गया। त्रिपुरा को ब्रॉडगेज रेल लाइन से जोड़ा जा चुका है। 31 जुलाई, 2016 को तत्कालीन रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने अगरतला-नई दिल्ली 'त्रिपुरासुंदरी एक्सप्रेस' को झंडी दिखाकर रवाना किया। अगरतला-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 28 अक्तूबर, 2017 को शुरू हुई। किसी भी राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की यह सबसे लंबी दूरी की सेवा है (2,422 कि.मी.)।

मणिपुर के पहले रेलवे स्टेशन जिरिबाम को ब्रॉडगेज रेल लाइन के जरिए जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री ने 27 मई, 2016 को जिरिबाम के लिए पहली पैसेंजर रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मिजोरम में भैरबी के लिए पैसेंजर रेल सेवा की शुरुआत की। लमडिंग-सिलचर ब्रॉडगेज खंड में दोहरी रेल लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद 20 नवंबर, 2015 से बराक घाटी के साथ ब्रॉडगेज के जरिए सीधा संपर्क कायम हो गया है। पूर्वोत्तर के आठों राज्यों की राजधानियों के साथ ब्रॉडगेज रेल संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी हैं।

देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र ऐतिहासिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। डिब्रूगढ़ के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 कि.मी. लंबा देश का सबसे लंबा बोगीबील रेल और सड़क पुल चालू हो जाने से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक और संपर्क स्थापित हो गया है। 25 दिसंबर, 2018 को प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर तीन लेन वाली सड़क से जुड़ने के साथ ही यह पुल 74 कि.मी. लंबी रेल लाइन के साथ रेल संपर्क कायम करता है।

1997-98 में 1000 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत बोगीबील पुल का काम अप्रैल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रारंभ किया था। लेकिन पूरा होते-होते इसकी लागत बढ़कर करीब 5820 करोड़ रुपये हो गयी।

141 मीटर ऊंचे घाटों पर बना भारत का यह सबसे ऊंचा रेल पुल मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में नोने के पास इरांग नदी पर बनाया जा रहा है। यह नवनिर्मित जिरिबाम-तुपुल-इम्फाल रेल लाइन का हिस्सा है और अपने आप में रेलवे इंजीनियरी का एक चमत्कार है। इसकी ऊंचाई का अनुमान लगाने के लिए इतना बताना काफी होगा कि यह दो कुतुब मीनारों के बराबर ऊंचा है। भैरवी-साइरंग के बीच बिछायी जा रही 51.3 कि.मी. लंबी रेल लाइन पर भी 70 मीटर से अधिक ऊंचे घाटों वाले छह पुल होंगे।

पूर्वोत्तर में पिछले करीब चार साल में रेलवे के क्षेत्र में जो शानदार उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं वे उनमें 970 कि.मी. लंबी छोटी रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना जाना भी शामिल है। इस क्षेत्र की सभी मीटर गेज लाइनों को ब्रॉड गेज में बदला जा चुका है और अब यहां कोई मीटर गेज रेल सेवा नहीं है। 2014-15 से 2017-18 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में हर साल औसतन 353 कि.मी. लंबी नई रेललाइनों का निर्माण, गेज परिवर्तन और दोहरी रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया गया जबकि 2009-2014 के दौरान यहां सालाना सिर्फ 110 कि.मी. लंबी रेल लाइनें बिछायी गयी थीं। इसके अलावा पूर्वोत्तर और इससे जुड़े राज्यों में 47 करोड़ रुपये लागत से 1,397 कि.मी. लंबी नयी रेल लाइनें बिछाने का कार्य नियोजन, स्वीकृति और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों

तीव्र गति से व्यापक परिवर्तन

रेल विकास की गति, परिमाण और सुरक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि

रेल हादसे घट कर हुए 62%

2013-14	118
2017-18	72

ट्रैक नवीनीकरण में 50% की वृद्धि

2013-14	2017-18
2,926 किमी	4,405 किमी

ब्रॉड गेज लाइन बिछाई गई

2009-14	2014-18
7,600 किमी	9,528 किमी

1 जनवरी, 2019 तक

में है ताकि यह क्षेत्र परिवहन संपर्क से जुड़कर एक हो जाए।

क्षमता बढ़ोत्तरी

भारतीय रेलवे के लिए अपनी क्षमता में बढ़ोतरी करना बहुत जरूरी हो गया था और इसके लिए रेलवे ने दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजनाएं-ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना शुरू कीं। 2014 से दोनों परियोजनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पिछले साल अगस्त में पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के फुलेरा-अटारी सेक्शन पर और नवंबर में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर परियोजना के खुर्जा भडान सेक्शन पर मालगाड़ियों का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है।

पश्चिमी गलियारे के विस्तारित रेवाड़ी-मदार सेक्शन और पूर्वी गलियारे के खुर्जा-भाऊपुर सेक्शन पर मालगाड़ियों का परीक्षण के तौर पर संचालन चाले वित्त वर्ष (2018-19) के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडार परियोजना के चरणबद्ध तरीके से 2020 तक पूरा हो जाने की संभावना है। पश्चिमी फ्रेट कॉरीडोर का 190 कि.मी. लंबा अटेली-फुलेरा खंड 15 अगस्त, 2018 को और पूर्वी कॉरीडोर का 194 कि.मी. लंबा तथा खुर्जा-नया भड़ान सेक्शन 23 नवंबर 2018 को शुरू हुए हैं।

3376 रूट कि.मी. की इन दो परियोजनाओं के चालू हो जाने से रेलवे को माल ढुलाई के कारोबार में अपना हिस्सा फिर से प्राप्त करने में मदद मिलेगी बल्कि देश में सामान के परिवहन के लिए कुशल, विश्वसनीय, सुरक्षित और किफायती प्रणाली की गारंटी भी मिलेगी। जब दोनों माल ढुलाई गलियारे काम करने लगेंगे तो इससे माल ढुलाई में बुनियादी बदलाव आएगा। इससे परिवहन की प्रति इकाई लागत में कमी आएगी, संगठन और प्रबंधन का खर्च घटेगा जिससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और ऊर्जा की खपत घट जाएगी।

रेल मार्गों पर भीड़भाड़ और यातायात के क्षमता को पार कर जाने की समस्या से निपटने के लिए रेल लाइनों को दोहरा करने और अतिरिक्त लाइनें बिछाने का कार्य जारी है। पिछले चार वर्षों में रेलवे ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और 2555 कि.मी. लंबी नयी रेल लाइनें बिछायी गयी हैं, 3396 कि.मी. रेल लाइनों का गेज़ बदला गया है और 3577 कि.मी. लाइनों को दोहरा किया गया है। 2017-18 में रेल लाइनों से संबंधित कुल 1862 कि.मी. कार्य हुआ जिसमें से 409 कि.मी. लंबी नयी रेल लइनें बिछाने, 454 कि.मी. रेल लाइनों का गेज़ परिवर्तन और 999 कि.मी. लाइनों को दोहरा करने का कार्य शामिल है।

न्यू इंडिया के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

सस्ते और पर्यावरण अनुकूल ईंधन को बढ़ावा

₹ 12,134.50 Cr allocated to cover 13,675 route kilometres

Railways to save fuel bill up to ₹ 13,510 Cr per annum

To reduce fossil fuel consumption by **2.83 billion litre/annum**

Generate direct employment **of about 20.4 Cr mandays** during construction

1 जनवरी 2019 तक

हाल के बजट में 14,480 कि.मी. रेल लाइनों को दोहरा करने और तीसरी तथा चौथी लाइन बिछाने का कार्य शामिल किया गया है। क्षमता बढ़ोतरी की इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए संस्थागत स्रोतों से संसाधन जुटाए गये हैं। परियोजनाओं के काम में वास्तवित प्रगति, ग्राहक तक पहुंच और मौजूदा मार्गों पर भीड़-भाड़ कम करने की परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जा रही है।

विद्युतीकरण में तेजी

आयातित डीजल, कोयले और ईंधन पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए भारतीय रेलवे ने रेल लाइनों के विद्युतीकरण में तेजी लाने के एक प्रमुख कार्यक्रम की शुरुआत की है। फिलहाल भारतीय रेलवे में करीब दो तिहाई माल ढुलाई और आधे से अधिक यात्री परिवहन विद्युत ट्रैक्शन यानी बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियों के जरिए होता है। रेलवे के ऊर्जा पर होने वाले कुल खर्च का 37 प्रतिशत बिजली से गाड़ियों के संचालन पर होता है। विद्युतीकरण के इस फायदे को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे को इससे 13,510 करोड़ रुपये सालाना की बचत होने की संभावना है जिससे उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने का अनुमान है। इसके अलावा विद्युतीकरण परियोजना के दौरान करोड़ों दिहाड़ियों का प्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा।

1 अप्रैल 2018 तक रेलवे ने 30,212 रूट कि.मी. रेल लाइनों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया था। 29,486 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 33,658 कि.मी. रेल लाइनों के विद्युतीकरण का कार्य जारी है। बाकी बचे रेलमार्गों में से 13,675 रूट कि.मी. के विद्युतीकरण की स्वीकृति सितंबर 2018 में दी गयी जिसके लिए 12,134 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। 2017-18 में 4,087 रूट कि.मी. ब्रॉडगेज लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका था जबकि लक्ष्य केवल 4,000 कि.मी. का ही था। इससे पहले साल (2016-17 के दौरान) 1,646 रूट कि.मी. रेलमार्गों का विद्युतीकरण किया गया था।

विद्युतीकरण से आयातित जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम होगा जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। इससे हाई स्पीड डीजल की खपत में भी करीब 2.83 अरब लीटर वार्षिक की कमी आएगी और उसी अनुपात में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो जाएगा। जाहिर है कि इससे पर्यावरण पर रेलवे का प्रभाव भी कम हो जाएगा। रेलवे का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाने से रेल गाड़ियों का निर्बाध संचालन भी संभव हो गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा।

विद्युतीकरण से रेलवे लाइनों की बढ़ाने में भी मदद मिलेगी क्योंकि इंजनों की रफ्तार और वजन खींचने क्षमता अधिक होती है। सिग्नलिंग सुधार से रेलगाड़ियों के संचालन में और अधिक बढ़ जाएगी।

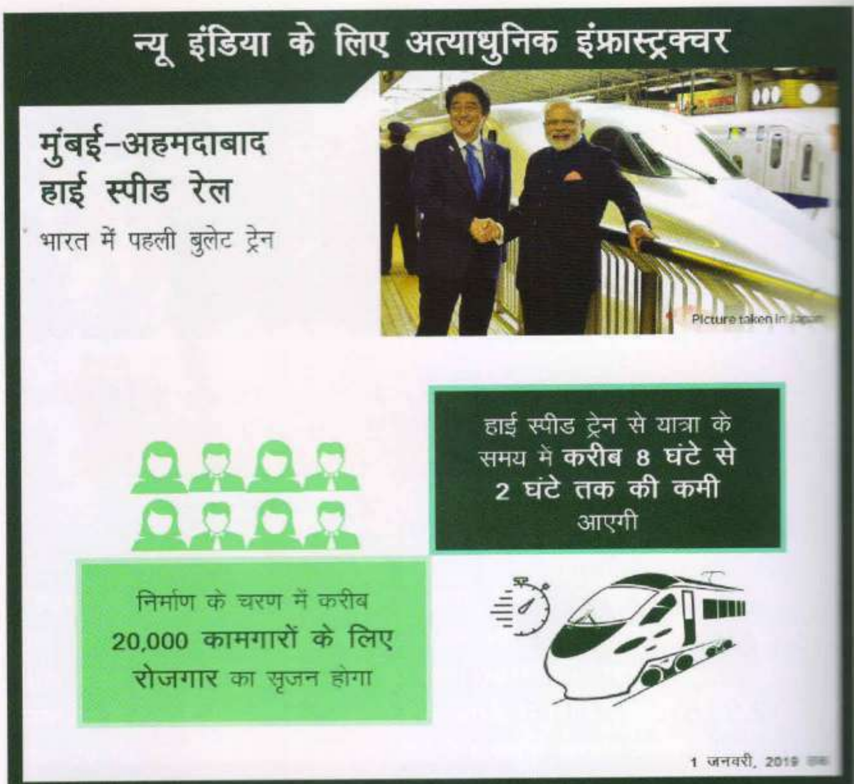

सुरक्षा के साथ-साथ संपर्क सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने 2017-18 राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का गठन किया। यह सुरक्षा परियोजनाओं के एक सुरक्षित निधि है जिसमें पांच वर्षों में एक लाख करोड़ की राशि हो जाएगी। इससे सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बकाया कार्यों का जा सकेगा।

बाकी रेलमार्गों के विद्युतीकरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। जैसे, क्रियान्वयन एजेंसियों का आधार व्यापक किया गया है और 1735 रूट कि.मी. की परियोजनाएं पहले ही इरकॉन लिमिटेड, राइट्स और पी.जी.सी.आई.एल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सौंपी जा चुकी हैं।

सुरक्षा की सुनिश्चितता

सुरक्षा के साथ-साथ संपर्क सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने 2017-18 में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का गठन किया। यह सुरक्षा परियोजनाओं के लिए एक सुरक्षित निधि है जिसमें पांच वर्षों में एक लाख करोड़ की राशि जमा हो जाएगी। इससे सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बकाया कार्यों का निपटाया जा सकेगा। इस तरह के कार्यों में पुरानी रेल पटरियों को बदलाना और उनकी सुरक्षा, पुलों को मजबूत करना, बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों को समाप्त करना, अनुरक्षण सुविधाओं में सुधार, सिग्नल प्रणाली में सुधार, पुराने रेल डिब्बों के स्थान पर आघात से बेअसर रहने वाले एल.एच.बी. डिब्बों का निर्माण तथा आई.सी.एफ. के डिब्बों का रिट्रोफिटमेंट शामिल हैं।

2017-18 के संशोधित बजट अनुमानों में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष समेत सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए 68,725 करोड़ रुपये रखे गये हैं जबकि 2018-19 के बजट अनुमान में इसके लिए 73,065 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में पूंजीगत बजट समर्थन के लिए 5,000 करोड़ रुपये, केन्द्रीय सड़क कोष से रेलवे सुरक्षा निधि में रेलवे के हिस्से के तौर पर 10,000 करोड़ रुपये और रेलवे राजस्व से प्राप्त 5,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। सभी व्यस्त रेलमार्गों पर बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों को बंद करने और एल.एच.बी. किस्म के सुरक्षित रेल डिब्बों का उत्पादन शुरू होने के साथ ही रेल पटरियों के नवीकरण पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है और इसके लिए अब तक सबसे अधिक खर्च रखा गया है।

सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है जिसकी वजह से रेल दुर्घटनाओं में 62 प्रतिशत कमी आयी है। 2013-14 में 118 रेल दुर्घटनाएं हुई थीं जबकि 2017-18 में इनकी संख्या घटकर 73 हो गयी। असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग यानी रेल फाटक के मसले से युद्ध स्तर पर निबटने के लिए पिछले चार साल में इस तरह के 5,479 रेल फाटकों को बंद कर दिया गया। सुरक्षा से संबंधित करीब एक लाख पदों को भरा जा रहा है।

1 अप्रैल 2018 से आई.सी.एफ. (इंटीग्रल कोच फैक्टरी) डिब्बों का निर्माण पूरी तरह बंद करने का फैसला किया गया और उनकी जगह अधिक सुरक्षित किस्म के

लिंके हॉफमैन बुश्च (एलएचबी) डिजायन के डिब्बों का निर्माण प्रारंभ करने की योजना बनायी गयी। ये डिब्बे रेलगाड़ियों की टक्कर होने पर एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते।

रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली का पूरी तरह से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके 2018-19 के निर्माण कार्यक्रम में भारतीय रेलवे की समूची 60,000 रूट कि.मी. ब्रॉड गेज लाइनों को नया बनाने की योजना है।

बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर दुर्घटना की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सभी ब्रॉड गेज रेल लाइनों में इस तरह के फाटकों को या तो बंद करने या उनमें चौकीदार तैनात करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल, 2018 को देश में बिना चौकीदार वाले 7,592 रेल फाटक थे जिनमे से 3479 ब्रॉड गेज पर, 1135 मीटर गेज पर और 1178 नैरोगेज लाइनों पर स्थित थे।

बेहतर सेवाओं की पेशकश

रेलवे को समय की पाबंदी के मामले में 'स्मार्ट' बनाने के लिए स्टेशन मास्टरों से समय दर्ज कराने की बजाय इंटरचेंज प्वाइंट्स पर डेटा लॉगर लगाये गये हैं जो कम्प्यूटर पर आधारित हैं। इससे समय की पाबंदी के मामले में 73-74 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

भारतीय रेलवे अपने हर एक रेल इंजन में जी.पी.एस. प्रणाली स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि मोबाइल फोन से प्रत्येक रेलगाड़ी की स्थिति का सही-सही पता लगाया जा सके। रेलवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (मशीनी बुद्धि) के इस्तेमाल के बारे में भी विचार कर रही है। उसका विश्वास है कि विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का उपयोग करके रखरखाव के कार्यों पर पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं इनसे बेहतर निगरानी रखी जा सकती है और परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। आंकड़ों के उपयोग से यात्री सेवाओं को भी बेहतर बनाया जा सकता है। भारतीय रेलवे ने अपने 6000 स्टेशनों को वाइ-फाई युक्त करने की भी योजना बनायी है।

बेहतर सुविधाओं की शुरुआत

रेलवे अपनी यात्री सेवाओं में सुधार के साथ-साथ स्टेशनों में चलती-फिरती सीढ़ियों (एस्केलेटर्स), लिफ्ट, मुफ्त वाई-फाई जैसी अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराकर उनका कायाकल्प करने की योजना बना रहा है। मार्च 2019 तक 68 स्टेशनों में इस तरह के सुधार करने की योजना है। तेजस, अंत्योदय और हमसफर जैसी रेलगोड़ियां शुरू करने के साथ ही सरकार ने ट्रेनों और रेलडिब्बों में सुधार किये हैं। 160 कि.मी. प्रतिघंटा तक की रफ्तार से चलने वाली सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन 18 का परीक्षण किया जा रहा है। स्वदेशी क्षमता से विकासित इस ट्रेन के निर्माण से 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा मिला है। जापानी मॉडल पर आधारित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य भी शुरू हो चुका है।

यात्रियों की यात्रा को आरामदेह बनाने के लिए पिछले चार साल में 407 नयी ट्रेन सेवाएं शुरू की गयी हैं जिनमें से 1.37 लाख सेवाएं त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए प्रारंभ की गयीं। रेलगाड़ियों में खान-पान पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। 300 और रेलगाड़ियों में बिकने वाले खाने-पीने के सभी सामानों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करना अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे स्टेशनों पर स्थित पाकशालाओं में बनने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता पर नजर रखने तथा इसमें सुधार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का सहारा लिया जा रहा है। भारतीय रेलवे एल.एच.बी. किस्म के रेल डिब्बों को बड़े पैमाने पर अपनाने की योजना बना रहा है क्योंकि वे 130 से 160 कि.मी. प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली रेलगाड़ियों के लिए उपयुक्त पाये गये हैं।

रेलगाड़ियों से माल परिवहन को अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाने के उद्देश्य से 2017-18 में कई कदम उठाये गये जिनमें मालभाड़े को युक्तिसंगत बनाना, नयी वस्तुओं का वर्गीकरण, कंटेनरों के जरिए माल ढुलाई के भाड़े की सूची का विस्तार, नये डिलीवरी मॉडलों जैसे रो-रो (रॉल ऑन-रॉल ऑफ) सेवाएं, महत्वपूर्ण ग्राहकों के साथ दीर्घकालीन शुल्क अनुबंध नीति, दो स्टेशनों के बीच नियत दर, कम ऊंचाई के डबल स्टैक ड्वार्फ कंटेनर, माल तोलने संबंधी ग्राहक अनुकूल वेमेंट नीति, माल डिब्बों की मांग के लिए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण (ई-आरडी) आदि।

निजी कंटेनर रेक्स को ध्यान में रखते हुए खाली कंटेनरों और खाली फ्लैट वैगनों के मालभाड़े पर 25 प्रतिशत की रियायत देने का भी फैसला किया गया है। इससे रेलवे के खाली कंटेनरों की बंदरगाहों में आमद बढ़ेगी और वे माल के साथ वापस लौटेंगे। इससे यातायात में भारतीय रेलवे के कंटेनरों का हिस्सा बढ़ने से उसका मुनाफा भी बढ़ेगा। ❑

15 शहरों में 664 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेल परियोजनाएं

प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2018 में अपने महाराष्ट्र दौरे में आवास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अलावा कुछ मेट्रो परियोजनाओं का भी अनावरण किया। उन्होंने दो अहम मेट्रो कॉरीडोर- ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो और दहिसार-मीरा-भायंदर की आधारशिला रखी। इन दोनों मेट्रो परियोजनाओं के पूरे हो जाने पर इस क्षेत्र के लोगों को सार्वजनिक परिवहन के मामले में बड़ी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पुणे में यहां के तीसरे चरण की मेट्रो परियोजना की आधारशिला रखी।

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि 15 शहरों में 664 किलोमीटर से भी ज्यादा की मेट्रो रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जबकि देश में 515 किलोमीटर से भी ज्यादा की मेट्रो लाइन पर परिचालन हो रहा है।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से जुड़ी सलाहकार कमेटी के सदस्यों के साथ 29 अक्टूबर 2018 को संवाद के दौरान मंत्री ने हाल में सरकार द्वारा शहरी परिवहन के मामले में उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी। मंत्री का कहना था कि मेट्रो रेल के लिए पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने की खातिर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मेट्रो रेल नीति 2017 संबधी अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा, 'यह नीति आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के नजरिये से मेट्रो रेल परियोजनाओं की व्यवहार्यता के मामले में खाई को पाटती है। इसका मकसद मेट्रो रेल प्रणाली के लिए सिलसिलेवार ढंग से योजना और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना है।'

तेजी से विकास के रास्ते पर उत्तर-पूर्व

नमिता तिवारी

उत्तर-पूर्व को स्वर्ग का ऐसा टुकड़ा कहा जा सकता है जिसे बड़े पैमाने पर खोजा नहीं गया है। जहां तक सड़क के संपर्क का सवाल है, तो यह क्षेत्र फिर से सक्रियता के रास्ते पर है और उत्तर-पूर्वको सिलीगुड़ी गलियारे के जरिये देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा गया है। उत्तर पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी गलियारे को 'चिकन नेक क्षेत्र' के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पड़ोस में नेपाल और बांग्लादेश हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के दायरे में 8 राज्य हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। देश की कुल आबादी में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 3.78 फीसदी है और यह इलाका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98 फीसदी है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस उत्तर-पूर्व क्षेत्र की हिस्सेदारी 2.5 फीसदी है।

यह क्षेत्र भौगोलिक ठिकाने, संसाधनों आदि तमाम पहलुओं के लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। देश का उत्तर-पूर्व हिस्सा बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार और नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के तहत करीब 5,437 किलोमीटर की सीमा तय करता है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ उत्तर-पूर्व के संपर्क से इस क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा, ''संपर्क के बेहतर साधन से लैस उत्तर-पूर्व हमारे सपनों के आसियान-भारत संबंधों का पुल होगा।''

आधारभूत संरचना के विकास में तेजी

इस इलाके में आधारभूत संरचना बढ़ाने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यहां 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की सड़क परियोजनाओं पर काम के लिए तकरीबन 1,90,000 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) की तरफ से कुल 1,66,026 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके तहत उत्तर-पूर्व इलाके के 8 राज्यों में 10,982 किलोमीटर सड़क के सिलसिले में निर्माण कार्य को अंजाम दिए जाने की बात है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को लागू करने संबंधी कार्य की सुस्त रफ्तार को तेज करने के मकसद से 18 जुलाई 2014 को एनएचआईडीसीएल की स्थापना की गई थी। यह भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है और इसने विशेष एजेंसी के रूप में राजमार्गों के निर्माण को सहारा दिया है। कुल 17,257 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को संबंधित लोक निर्माण विभागों (पीडब्ल्यूडी) को आवंटित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

न्यू इंडिया के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

पूर्वोत्तर को जोड़कर देश में संपर्क को बढ़ावा

पूर्वोत्तर के पूरे रेल नेटवर्क को ब्रॉड गेज में बदलकर इसे देश के अन्य हिस्से के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया गया

पहली बार मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भारत के रेल मैप पर आए

1 जनवरी, 2019 तक

लेखिका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में सहायक संपादक हैं। ईमेल: namitastewari@gmail.com

प्राधिकरण (एनएचएआई) को 7,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की परियोजनाएं सौंपी गई हैं।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं की गति तेज करने के लिए सरकार ने एक और पहल की है। इसके तहत उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

राजमार्ग परियोजनाओं को रफ्तार

सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग व्यापार में बढ़ोतरी, विशेष तौर पर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में बने उत्पादों का निर्यात आसियान और अन्य पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, भूटान और नेपाल) को करने के लिए इस क्षेत्र को 2022-23 तक विकसित करने की वकालत कर रहा है। इसके लिए आयोग ने राजमार्ग परियोजनाओं को रफ्तार देने की जरूरत पर जोर दिया है।

नीति आयोग का मानना है कि इस इलाके में पर्यटन की कमी और प्रचुर संसाधनों का उपयोग नहीं होने की वजह सड़कों की कमी है। आयोग ने फिलहाल इस इलाके में चल रही परिवहन परियोजनाओं पर करीबी रूप से निगरानी की भी जरूरत बताई है और वैसी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया है, जो अंतर-क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देता हो और इस पूरे इलाके को दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख व्यापारिक अड्डा बनाने में मदद करे।

आयोग का कहना है कि उत्तर-पूर्व में करीब 4,099 किलोमीटर की सड़क को बेहतर बनाने के अलावा कलादान बहु-विध (मल्टी-मोड) परिवहन परियोजना, भारत-म्यांमार-थाइलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, मिजोरम में सीमावर्ती शहर जोखाव्थर और म्यांमार में रीह के बीच 5 किलोमीटर लंबी सड़क को लेकर काम तेज किए जाने की जरूरत है।

हालांकि, इस बात में कोई शक नहीं कि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की तरफ सरकार ने फिर से ध्यान दिया है और मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 30 नवंबर 2018 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 43 परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं।

जहां तक उत्तर-पूर्व इलाके में असम को छोड़कर बाकी हिस्सों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए किसी तरह की लेवी नहीं लगाई जाती। असम में जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजे की राशि का 10 फीसदी शुल्क लगाया जाता है।

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 1,15,435 किलोमीटर लंबाई में अरुणाचल प्रदेश के पास 2,537 किलोमीटर, असम के पास 3,845 किलोमीटर, मणिपुर के पास 1,746 किलोमीटर, मेघालय के पास 1,204 किलोमीटर, मिजोरम के पास 1,422 किलोमीटर, नगालैंड के पास 1,547 किलोमीटर, सिक्किम के पास 463 किलोमीटर और त्रिपुरा के पास 854 किलोमीटर की हिस्सेदारी है।

उत्तर पूर्व में नई सड़क परियोजनाएं

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने दिसंबर 2018 में अरुणाचल प्रदेश में कुल 9,533 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी थी। इस मौके पर उन्होंने कुछ बड़ी राजमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि ये परियोजनाएं विकास, रोजगार सृजन, पर्यटन और युवाओं को रोजगार के लिए गुंजाइश मुहैया कराकर उत्तर-पूर्व की तस्वीर बदल देंगे।

इससे पहले मंत्री ने शिलॉन्ग में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर जोवई-रताचेरा (मेघालय असम सीमा) खंड का बेहतर तरीके से निर्माण कर इसका उद्घाटन किया था। उन्होंने 102 किलोमीटर इस लंबी सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसका निर्माण 683 करोड़ रुपये की लागत से किया गया था।

102 किलोमीटर लंबी यह सड़क मेघालय में उद्योगों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रास्ता राज्य के सीमेंट और कोयला वाले इलाके से गुजरता है और इससे यात्रा में लगने वाला समय 4 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो गया है। इसके जरिये ब्रह्मपुत्र घाटी से आने वाले ट्रक और अन्य भारी वाहन असम के भीतर सिलचर से बराक घाटी में रिकॉर्ड कम समय में आसानी से पहुंच जाएंगे और इस तरह से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम जैसे राज्यों के लिए संपर्क की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी।

इस क्षेत्र के लिए एक और सुविधा ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी-फुलबारी पुल होगा। चूंकि यह 20 किलोमीटर लंबे पुल की परियोजना है और इसका नौपरिवहन संबंधी दायरा 12.625 किलोमीटर है, लिहाजा डीपीआर को अंतिम रूप दिए जाने से पहले क्षेत्र की मिट्टी और जल विज्ञान की विस्तार से जांच-पड़ताल किए जाने की जरूरत है।

इस परियोजना की फंडिंग जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा की गई है और इसके लिए कर्ज संबंधी समझौते पर अक्टूबर 2018 में हस्ताक्षर किए गए। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पुल का निर्माण कार्य शुरू होना है।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले चार साल में परिवहन संबंधी उन्नत अवसंरचना में बढ़ोतरी हुई है और यह नेटवर्क देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में बढ़ रहा था।

भारत-म्यांमार सड़क संपर्क

हाल में भारत और म्यांमार के बीच हुई बैठक में मौजूदा भारत-म्यांमार परिवहन संपर्क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

दोनों पक्षों ने भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) त्रिपक्षीय राजमार्ग के कलेवा-याज्ञी खंड को बेहतर बनाने के लिए परियोजना

की स्थिति और इंफाल-मंडाले बस सेवा को शुरू करने पर चर्चा की।

आईएमटी के कलेवा-याज्ञी खंड को उन्नत बनाने का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। भारत और म्यांमार जमीन सीमा क्रॉसिंग समझौते को चालू करने के बाद बस सेवा शुरू करने को लेकर काफी उत्सुक हैं। इस समझौते के तहत वैध पासपोर्ट और वीजा रखने वाले दोनों देशों के नागरिकों को विशेष मंजूरी के बिना एक-दूसरे मुल्कों में आने-जाने की इजाजत होगी। अब दोनों देशों को इस सेवा के संचालन के लिए बस संचालकों का चुनाव करना है।

भारतमाला परियोजना

उत्तर-पूर्व पर सरकार के विशेष ध्यान को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि भारतमाला परियोजना के तहत उसकी योजना इस क्षेत्र में 28 रिंग रोड बनाने की है। भीड़भाड़ से होने वाली दिक्कत को कम करने के लिए परियोजना में ट्रैफिक के नियमन के लिए कई ठिकाने बनाने की योजना है।

उत्तर-पूर्व राज्यों के जिन प्रमुख शहरों में इस तरह के हस्तक्षेप की योजना बनाई गई है, उनमें गुवाहाटी, इंफाल, सिलचर, शिलॉन्ग, डिब्रूगढ़, डीमापुर और आइज़ॉल शामिल हैं।

सरकार ने अक्टूबर 2017 में अगले पांच साल में 6.92 लाख करोड़ रुपये की लागत से 83,677 किलोमीटर का राजमार्ग बनाने संबंधी बड़ी योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना भी शामिल है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बाद इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना है।

भारतमाला परियोजना सड़कों के लिए एक समग्र कार्यक्रम है, जिसके तहत पहले चरण में 5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत से 34,800 किलोमीटर के राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसमें उत्तर-पूर्व के लिए बड़ी संख्या में परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके तहत आर्थिक गलियारे, अंतरराष्ट्रीय संपर्क परियोजनाएं, असम के लिए फीडर सड़क, मणिपुर के लिए 901, मेघालय के लिए 493, मिजोरम के लिए 1,067, नगालैंड के लिए 406, सिक्किम के लिए 165 और त्रिपुरा के लिए 525 परियोजनाएं भी शामिल हैं।

भारतमाला परियोजना के तहत उत्तर-पूर्व क्षेत्र में तकरीबन 5,301 किलोमीटर लंबी सड़कों में सुधार के लिए मंजूरी दी गई है। इनमें से उत्तर-पूर्व में आर्थिक गलियारे के विकास के लिए 3,246 किलोमीटर लंबी सड़क को मंजूर किया गया है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने मार्च 2019 तक कई राजमार्ग परियोजनाओं को पूरा करने का फैसला किया है और पूरे भारत में फिलहाल चल रही 300 परियोजनाओं की समीक्षा की बात है।

अन्य कार्यक्रमों के अलावा केंद्र सरकार ने उत्तर-पूर्व विशेष आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम (एनईएसआईडीएस) को मंजूरी दी है। यह 100 फीसदी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे मार्च 2020 तक लागू किया जाना है। भौतिक आधारभूत संरचना के लिए कुल 1,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

भारत का सबसे लंबा पुल

प्रधानमंत्री की तरफ से दिसंबर 2018 में भारत के सबसे लंबे रेल और रोड पुल का उद्घाटन किया जाना भी उत्तर-पूर्व में सड़क संपर्क को लेकर प्रतिबद्धता का संकेत था। असम के डिब्रूगढ़ के पास बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह डबल डेकर 4.94 किलोमीटर लंबा पुल अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों की परिवहन और संचार संबंधी बाधाओं को दूर कर देगा। यह पुल डिब्रूगढ़ में शुरू होता है और असम के धेमाजी जिले तक फैला हुआ है।

यह पुल अरुणाचल प्रदेश में मौजूद सीमा के पास आवागमन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए भारत की आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं का हिस्सा है। पुल के कारण डिब्रूगढ़ से ईटानगर के बीच सड़क मार्ग की दूरी को 150 किलोमीटर तक कम जाएगी, जबकि इन दो बिंदुओं के बीच रेल यात्रा की दूरी 705 किलोमीटर तक घट जाएगी।

प्रधानमंत्री ने मई, 2017 में असम में लोहित नदी पर देश के सबसे बड़े पुल (9.15 किलोमीटर लंबा) का उद्घाटन किया था। इस पुल का नाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता और मशहूर गीतकार-गायक भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया, जो सदिया के रहने वाले थे। पुल को 2,056 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और यह बांद्रा-वर्ली समुद्री लिंक से 3.55 किलोमीटर लंबा है। इस पुल की कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है और इसके साथ धोला की तरफ से 7.3 किलोमीटर की संपर्क सड़क है और सदिया की तरफ से इस तरह की सड़क की लंबाई 12.5 किलोमीटर है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया है कि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ उत्तर-पूर्व के संपर्क से इस क्षेत्र को विकास को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा, ''संपर्क के बेहतर साधन से लैस उत्तर-पूर्व हमारे सपनों के आसियान-भारत संबंधों का पुल होगा।''

सरकार चुनौतियों का सामना करते हुए इस क्षेत्र में संपर्क का साधन बेहतर करने के लिए हरमुमकिन प्रयास कर रही है और उत्तर-पूर्व विकास की लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। ❑

सबके लिए आवास : सरकार की प्रमुख प्राथमिकता

रंजीत मेहता

बुनियादी ढांचा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। किसी भी देश की बुनियादी संरचना की गुणवत्ता उसकी आर्थिक मजबूती का सूचक है। विश्वसनीय परिवहन, स्वच्छ जल और कचरे का सुरक्षित निपटान एक सभ्य समाज और उत्पादक अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्व हैं। अनुमानतः 2017 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर दस खरब डॉलर (एक ट्रिलियन अमरीकी डॉलर) खर्च किए जा चुके हैं। औद्योगिक परियोजनाओं में सरकारी निवेश काफी बढ़ा है। एक अरब 30 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में निर्माण क्षेत्र में तेजी आना निश्चित है। अर्थव्यवस्था में निर्माण क्षेत्र का 49 प्रतिशत, भवन और स्थावर संपदा क्षेत्र का 42 प्रतिशत और औद्योगिक परियोजनाओं का हिस्सा 9 प्रतिशत है। रियल एस्टेट और निर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं और विकास के लिए किए जाने वाले निवेश का एक महत्वपूर्ण भाग है। निर्माण क्षेत्र देश के बुनियादी ढांचागत आधार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आर्थिक गतिविधियां सृजित करने वाला प्रमुख कारक है। निर्माण क्षेत्र का अन्य विभिन्न उद्योगों से जैसे सीमेंट, स्टील, रसायन, पेंट, टाइल्स तथा फिक्चर्स और फिटिंग्स उद्योग से मजबूत संपर्क है।

भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है और यह दिनों दिन विकसित होती जा रही है। अनुमान है कि 2050 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सतत आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र का महत्व अच्छी तरह समझा जा सकता है। परिवहन, बिजली और सम्पर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं आर्थिक वृद्धि, जलापूर्ति, स्वच्छता, जल-मल निकासी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सुविधाओं में योगदान करती हैं। ये सामाजिक सुविधाएं नागरिकों के लिए प्राथमिक सेवाएं हैं, जिनका जीवन की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र का प्रदर्शन बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का ही प्रतिबिंब है।

सरकारी नियमों, विनियमों में उदारीकरण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने की सरकार की रणनीति सबके लिए अपार अवसर सृजित करती है। सड़क और राजमार्ग, बंदरगाह और हवाई अड्डे, रेलवे, भवन निर्माण और बिजली सहित लगभग सभी बुनियादी ढांचा क्षेत्र नियोजित निवेश के साथ उत्कृष्ट अवसर सृजित करते हैं। मई 2014 में सत्ता में आने के बाद से मौजूदा सरकार ने इस क्षेत्र की मदद के लिए शीघ्र मंजूरी और विवाद निपटान, वित्त पोषण और कंपनियों के लिए निवेश की समयबद्ध सुरक्षा जैसे कई उपाय किए हैं। सड़क क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सरकार की अनुमति के बाद कई विदेशी कंपनियों ने इस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से पूंजी लगाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ भागीदारी की है। आने वाले वर्षों में भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र लगभग 282 खरब डॉलर से भी अधिक के निवेश अवसर उपलब्ध कराएगा।

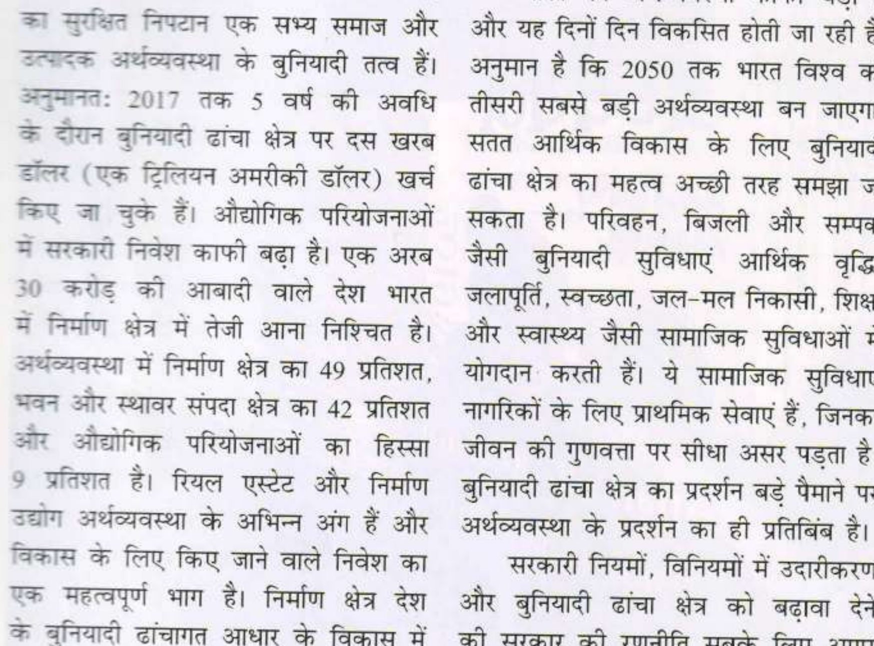

सस्ते (वहन योग्य) मकान उपलब्ध करवाना मौजूदा सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में प्रमुख है। 2022 तक सबके लिए मकान की सरकार की प्रतिबद्धता ने इस क्षेत्र के सभी भागीदारों के समक्ष विभिन्न अवसरों और आवश्यकताओं को सामने रखा है। सबके लिए मकान के सपना को साकार करना नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है

आबादी वृद्धि और आवास

शहरी सभ्यता के विस्तार के साथ ही आवास क्षेत्र लोगों, परिवारों, समूहों और सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है।

रंजीत मेहता नई दिल्ली में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (पीएचडीसीसीआई) में प्रधान निदेशक के पद पर हैं। ईमेलः ranjeetmehta@gmail.com

पूरे विश्व में विशेषकर, उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में तेज गति से शहरीकरण को रोका नहीं जा सकता। जैसा कि पिछले कुछ दशकों में देखा गया है, व्यापक शहरीकरण, बढ़ती आय और जनसंख्या में बदलाव के कारण परिवहन, आवास, भूमि और अन्य शहरी सेवाओं पर आबादी को समायोजित करने का दबाव लगातार बढ़ता गया है। पिछले दशक में जहां, कुल आबादी वृद्धि में कमी आई है, वहीं, शहरी आबादी में वृद्धि देश की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग दोगुनी हो गई है। 2031 तक शहरी जनसंख्या 2011 के 37 करोड़ 70 लाख से बढ़कर 60 करोड़ (कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से भी अधिक) तक पहुंच जाने का अनुमान है। बड़े शहरों की कुल संख्या बढ़ कर 87 हो जाने का अनुमान है (जो 2011 में 50 थे)। 2031 में सकल घरेलू उत्पाद में शहरी आबादी का योगदान बढ़कर 75 प्रतिशत हो जाने की आशा है, जबकि 2009-2010 में यह 62-63 प्रतिशत था (उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति 2011 की रिपोर्ट के अनुसार)। इसे देखते हुए शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है, साथ ही वर्तमान और आने वाले समय में आवास तथा अन्य सुविधाओं की कमी की संभावित समस्या से भी निपटा जाना जरूरी है।

सस्ते (वहन योग्य) मकान उपलब्ध करवाना मौजूदा सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में प्रमुख है। 2022 तक सबके लिए मकान की सरकार की प्रतिबद्धता ने इस क्षेत्र के सभी भागीदारों के समक्ष विभिन्न अवसरों और आवश्यकताओं को सामने रखा है। सबके लिए मकान के सपना को साकार करना नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। भारत सरकार ने शहरी निर्धनों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने के लिए 17 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबके लिए आवास योजना का शुभारंभ किया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-2022 तक सबके लिए मकान

सस्ते मकान उपलब्ध कराने के प्रयास पिछले कई वर्षों से चल रहे हैं। लेकिन 2015 में शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना ने इन प्रयासों को एक नई गति दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी (पीएमएवाई-यू) में पहले की सभी आवासीय योजनाएं शामिल कर ली गई हैं। इसका उद्देश्य 2022 तक सबके लिए मकान का लक्ष्य हासिल कर लेना है। इस योजना के जरिए दो करोड़ मकान उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है।

इस मिशन के चार हिस्से हैं :

(क) यथा स्थान झुग्गी झोपड़ी पुनर्विकास (आईएसएसआर) : इसके तहत जमीन का संसाधन की तरह उपयोग किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को सार्वजनिक या निजी भूमि पर बनी उनकी बस्तियों का विकास कर मकान उपलब्ध कराना है। योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रति मकान एक लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध कराती है।

(ख) सस्ते मकान भागीदारी में (एएचपी) : इसका उद्देश्य सस्ते मकान की योजना में निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए प्राइवेट डिवेलपर को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। निजी परियोजनाओं में जहां कम से कम 35 प्रतिशत मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बनाए जाते हैं, वहां प्रति मकान डेढ़ लाख रुपये की दर से केंद्रीय सहायता दी जाती है।

(ग) ऋण आधारित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) : इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने के लिए ब्याज में सब्सिडी सहित ऋण सुविधा दी जाती है। ब्याज सब्सिडी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं -पीएलआई के माध्यम से खरीददार के खाते में दी जाती है। इससे आवास ऋण और मासिक किस्त की राशि कम होती जाती है।

(घ) नए निर्माण या विस्तार के लिए लाभ योजना (बीएलसी) : इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग को नए निर्माण या मौजूदा मकान के विस्तार के लिए प्रति परिवार डेढ़ लाख रुपये की केंद्रीय सहायता मिलती है।

शहरी आवासीय पहलें

सरकार जलापूर्ति सुविधा, स्वच्छता और चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति के साथ सस्ते पक्के मकान बनाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों सहित शहरी निर्धनों के लिए दो करोड़ मकान 2022 तक बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए केंद्र सरकार से 20 खरब रुपये (31 अरब

न्यू इंडिया के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

बनते घर, पूरे होते सपने

प्रधानमंत्री आवास योजना

"2022 में जब भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हों तब प्रत्येक भारतीय के पास उसका अपना घर हो"

1.48 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण

9 लाख और 12 लाख रुपये तक के होम लोन पर 4% और 3% तक ब्याज अनुदान दिया जा रहा है

1 जनवरी, 2019 तक

अमरीकी डॉलर) की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रत्येक घर में शौचालय, सौभाग्य योजना के तहत बिजली, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन, पेयजल सुविधा और जन धन बैंक खाता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ जोड़ा गया है।

इस योजना का लक्ष्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों में इन संघटक/विकल्पों के साथ शहरी क्षेत्र का उपयोग करना है :

- संसाधन के रूप में जमीन का उपयोग करते हुए प्राइवेट डिवेलपर की भागीदारी से झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का पुनर्वास।
- ऋण आधारित सब्सिडी के जरिए कमजोर वर्ग के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराना।
- निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी में सस्ते मकान उपलब्ध कराना। और
- नए निर्माण या विस्तार की योजना के तहत सब्सिडी।

इसके अलावा भारत सरकार सबके लिए मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बजट में भी कई उपाय कर रही है।

2017-18 के केंद्रीय बजट में सस्ते मकान की योजना को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है :-

- सस्ते मकान को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
- 2019 तक एक करोड़ ग्रामीण आवास बनाए जाएंगे।
- राष्ट्रीय आवास बैंक 20 हजार करोड़ रुपये ऋण देगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 23 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- रियल एस्टेट डिवेलपर्स को अनबिके मकानों पर कर राहत मिलेगी। पूंजीगत लाभ कर चुकाने का दायित्व परियोजना पूरी होने के वर्ष में शुरू होगा।
- सस्ते मकानों के लिए 30 और 60 वर्ग मीटर के बिल्ट-अप एरिया के बदले 30 और 60 वर्ग मीटर का कार्पेट एरिया लागू होगा।
- अचल संपत्ति के लिए पूंजीगत लाभ कर का होल्डिंग पीरियड 3 वर्ष से कम कर 2 वर्ष किया गया है।
- अनबिके मकानों के लिए परियोजना पूरी होने का प्रमाणपत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) मिलने के बाद एक वर्ष के लिए कर देय नहीं होगा।
- इंदिरा आवास योजना का विस्तार 600 जिलों तक किया जाएगा।
- पूंजीगत लाभ का सूचीकरण एक अप्रैल 1981 के स्थान पर एक अप्रैल 2001 किया गया है।

सस्ते मकानों के लिए वित्त व्यवस्था

सस्ते मकानों को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा दिए जाने के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी कम कीमत के मकानों को बढ़ावा दिया गया है। योजना के तहत सरकार ने 9 लाख रुपये से अधिक के ऋण पर केवल 4 प्रतिशत की ब्याज दर और 12 लाख रुपये से अधिक के ऋण पर 3 प्रतिशत की ब्याज दर की घोषणा की है। सरकार ने ऐसी परियोजनाओं को पूरा किए जाने की अवधि बढ़ा कर 3 वर्ष से 5 वर्ष कर दी

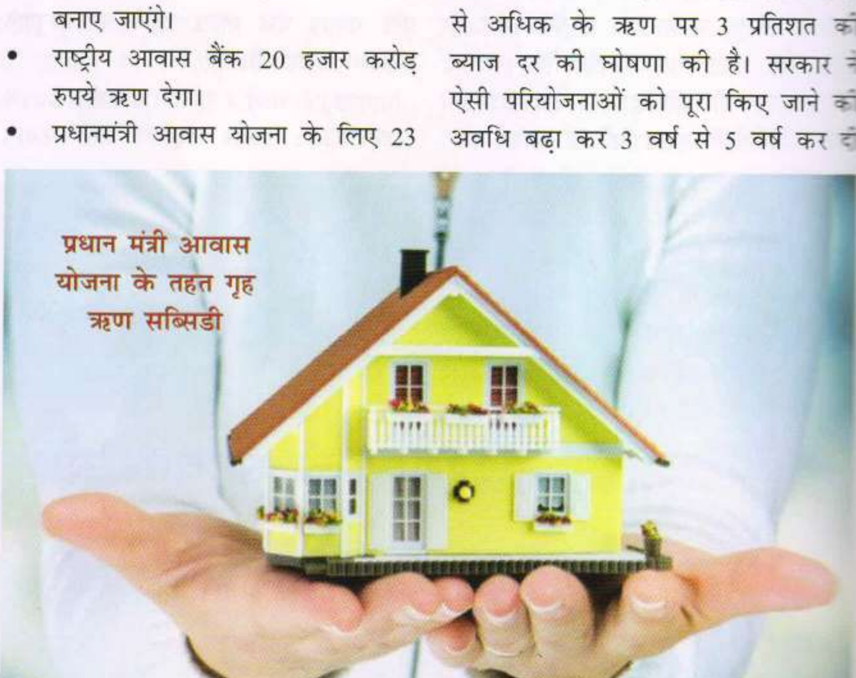

है। इस प्रकार अब और अधिक परियोजनाएं लाभ आधारित आय कर छूट के लिए पात्र होंगी। अब तक सस्ते मकान क्षेत्र में, अधिक मांग के बावजूद निजी डिवेलपर की बहुत कम भागीदारी देखी गई है। अब सस्ते मकानों के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र दर्जे के साथ लाभ आधारित छूट से डिवेलपर को अधिक परियोजनाएं शुरू करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह इस क्षेत्र में निजी डिवेलपर की भागीदारी बढ़ेगी।

कम कीमत के/सस्ते मकानों के लिए मानदंड बिल्ट-अप एरिया 30/60 वर्ग मीटर से बदल कर 30/60 वर्गमीटर कार्पेट एरिया किया गया है। इस प्रकार कम कीमत/सस्ता मकान क्षेत्र बिल्डर्स के साथ-साथ खरीदारों के लिए भी अधिक आकर्षक हो गया है। इस मानदंड में बदलाव से खरीदने वाले को अधिक क्षेत्र वाला मकान मिलेगा और बिल्डर को संपत्ति बेचने के लिए अधिक खरीददार मिलेंगे। 30 वर्ग मीटर की सीमा केवल 4 महानगरों के नगर निगम क्षेत्र में लागू होंगी जबकि महानगरों के आसपास सहित देश के बाकी हिस्सों में 60 वर्ग मीटर की सीमा लागू होगी।

भारत के पास जनसंख्या में बड़ी आबादी युवाओं की होने का महत्वपूर्ण लाभ है। इसे देखते हुए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवास क्षेत्र श्रम आधारित उद्योग है। इसके कारण इससे जुड़े उद्योगों में भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती है और रोजगार के अवसरों में भारी बढ़ोतरी होती है। देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह स्थिति बहुत ही अनुकूल है।

सस्ते मकानों के लिए वित्त व्यवस्था से, सबके लिए आवास का लक्ष्य पूरा करने की सरकार की समय सीमा 2022 तक, 6 लाख करोड़ रुपये के व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबके लिए मकान उपलब्ध कराने के प्रोत्साहन से सस्ते मकान के लिए धन उपलब्ध कराने वाली कंपनियों का एक नया समूह उभर कर सामने आया है, जो व्यावहारिक ऋण आकलन के आधार पर कम आय वर्ग के, शहरी अनौपचारिक उपभोक्ताओं के लिए काम कर रहा है। इन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली ऋण सुविधा प्रति लेनदार 9 लाख 30 हजार रुपये के आधार पर मार्च 2013 के 1000 करोड़ रुपये से बढ़ कर दिसंबर 2017 में 27000 करोड़ रुपये हो गई है। इससे, 2 लाख 30 हजार से अधिक लोगों को सस्ते मकान मिले हैं। निम्न आय वर्ग के लोगों का अपना मकान होने से शहरी क्षेत्रों में किराए के मकान लेने वाले कम हुए हैं। इससे अनौपचारिक और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार 2016-17 में ऋण मंजूरी और वितरण में तथा नई परियोजनाओं की शुरुआत में भारी इजाफा देखा गया है। ऋण आधारित सब्सिडी योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मकानों तक पहुंच बढ़ाने में काफी कारगर साबित हुई है।

कुल मिलाकर 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के इन सभी उपायों से सकल घरेलू उत्पाद में भारी इजाफा होने की आशा है, क्योंकि आवास क्षेत्र की वृद्धि सीधे लगभग 265 अन्य सहायक उद्योगों से सीधे जुड़ी है। □

खेल ढांचागत सुविधाओं में आगे बढ़ता भारत

राजेश राय

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है : भारत में क्रिकेट के अलावा और भी बहुत खेल हैं। ज़िला स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान करने की ज़रूरत है। केवल आधारभूत ढांचा मुहैया कराना काफी नहीं है, खेलों के लिए क्रिकेट जैसा वातावरण बनाना भी ज़रूरी है। खेलों के लिए संस्थागत इंतज़ाम करना जरूरी है। श्री मोदी रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम में लगातार खेलों पर जोर देते आये हैं और खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं।

प्रधान मंत्री ने जो यह बात कही है वह भारत के मौजूदा खेल परिदृश्य में बिलकुल सटीक बैठती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खेलों और ढांचागत सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार आया है और इस दिशा में केंद्र की मौजूदा सरकार के लगातार प्रयास जारी हैं।

महाराष्ट्र के पुणे में बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जनवरी में दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इस दिशा में एक बड़ा कदम है। पिछले साल पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था और इस बार दूसरा आयोजन उससे भी बड़े स्तर पर हुआ है। इन खेलों में तकरीबन 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 5,925 एथलीट, 1,096 सपोर्ट स्टाफ, 893 तकनीकी

लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। ईमेल: rajeshraivarta@gmail.com

मणिपुर में देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और कोच तैयार करने तथा खेल विज्ञान के क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से मणिपुर में देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में की गई। यह विश्वविद्यालय फिलहाल इंफाल के खुमन लंपाक खेल परिसर में अपने अस्थाई परिसर से कार्य कर रहा है।

देश में तथा विदेशों में कई स्थानों पर इसकी शाखाएं खोली जा सकेंगी। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के लिए 325 एकड़ में बनने वाले कैंपस की जमीन राज्य सरकार ने मुफ्त में दी है।

प्रधानमंत्री ने 16 मार्च, 2018 को इसका शिलान्यास किया था और जून 2018 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश-2018 को मंजूरी देने के बाद इसकी स्थापना हुई। यह खेल एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। भारत में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय नामक इसी तरह के तीन राज्य विश्वविद्यालय स्थापित/प्रस्तावित किए जा चुके हैं जबकि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान नामक एक डीम्ड यूनिवर्सिटी पहले से खेलकूद के क्षेत्र में संचालित है।

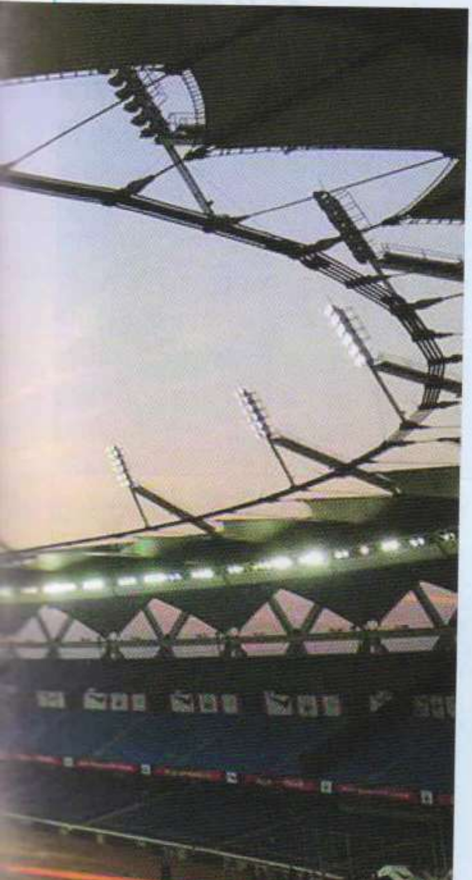

देश की युवा शक्ति को बढ़ावा

खेलों और खेल कौशल को बढ़ावा

मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

खेल शिक्षण व प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय अपनी तरह का पहला संस्थान होगा

गुजरात के गांधीनगर में पैरा एथलीटों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला पहला प्रशिक्षण केंद्र

ऑस्ट्रेलिया में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत ने अपने प्रभावशाली और ऐतिहासिक प्रदर्शन से 66 पदक जीते

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय में सुविधाएं

विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन, खेल औषधि तथा उच्च स्तर के प्रशिक्षण पर फोकस होगा। साथ ही खेलों के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री भी दी जायेगी। यहां अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की भी सुविधा होगी। इसमें एडवेंचर और दिव्यांग खेलों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालय देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के खेल प्रदर्शन में भी सुधार करेगा। इससे रोजगार उत्पादन भी बढ़ेगा।

अभी तक देश में खेलों के प्रशिक्षण के संबंध में सिर्फ दो संस्थान है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर स्थित समकक्ष विश्वविद्यालय लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान सिर्फ शारीरिक प्रशिक्षण में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री देता है जबकि पटियाला स्थित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान सिर्फ एथलीटों और कोचों के प्रशिक्षण का काम करता है।

विश्वविद्यालय के सभी परिसरों में एथलीट, खिलाड़ी, कोच, अंपायर और रेफरी तैयार करने पर फोकस होगा। विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम, अनुसंधान सुविधाएं तथा प्रयोगशालाएं तैयार करने के लिए सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा विश्वविद्यालय और विक्टोरिया विश्वविद्यालय के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

विश्वविद्यालय में होंगे चार स्कूल:

- खेल विज्ञान एवं खेल औषधि
- खेल प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी
- खेल शिक्षा
- अंतर स्पर्धाएं अध्ययन

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के प्रमुख बिंदु

- मणिपुर में स्थापित देश के पहले राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षकों के पद पर प्रतिष्ठित खिलाड़ी ही नियुक्त किए जाएंगे।
- विदेशी प्रशिक्षकों को बुलाकर विश्वविद्यालय में कक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, जिससे छात्रों को उनके अनुभव का लाभ मिल सकेगा।
- विभिन्न राज्यों में वहां की सरकारों से चर्चा करके समुचित सुविधाएं और जमीन मिलने पर आउटलाइन केंद्र खोले जाएंगे। लेकिन डिग्री सिर्फ मणिपुर विश्वविद्यालय से ही दी जायेगी।
- विश्वविद्यालय खेल से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री, मास्टर डिग्री, और अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान, खेल तकनीक, खेल प्रबंधन और खेल प्रशिक्षण जैसे विषयों पर अध्ययन-अध्यापन और शोध आदि किया जाएगा।
- चुने हुए खेलों के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र के तौर पर भी यह विश्वविद्यालय काम करेगा।

खेलो इंडिया-नए भारत की नींव

केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने जनवरी 2019 में दूसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत करते हुए कहा था कि इन खेलों से हम भविष्य के खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं और 2028 के ओलम्पिक तक हम वह ढांचा तैयार कर लेंगे कि 2028 ओलम्पिक में चीन हमारे सामने ठहर नहीं पायेगा।

कर्नल राठौड़ ने कहा, "खेलो इंडिया नए भारत की नींव रख रहा है और इसके जरिये हम भविष्य के लिए हजारों खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। खेलो इंडिया हर साल 1000 एथलीटों को ट्रेनिंग देगा और उन्हें प्रायोजित करेगा। हम पूरे देश में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि खेल सिर्फ मनोरंजन न रहे बल्कि युवा खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए खेले ताकि देश भी मजबूत बने और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरे।"

देश की युवा शक्ति को बढ़ावा

खेलों और खेल कौशल को बढ़ावा

खेलो इंडिया

- युवाओं के बीच खेल और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक जन आंदोलन
- प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 8 साल के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
- जनवरी, 2018 में पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का शुभारंभ, जिसमें 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 3,507 खिलाड़ियों ने भाग लिया
- 2017–18 से 2019–20 तक पुनर्गठित खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए 1,756 करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय निर्धारित

नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल लांच

उपलब्धियों को साझा करने हेतु प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक पारदर्शी मंच

*10 अगस्त, 2018 तक

अधिकारी, 36 दल प्रमुख, 1010 स्वंयसेवक और 1,500 अधिकारी शामिल थे। यह संख्या पिछले साल के पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स से लगभग दोगुनी है। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन दिल्ली के विभिन्न स्टेडियमों में हुआ था जिसमें 3000 के लगभग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।

इन खेलों के लिए बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नया रूप दिया गया और यह कॉम्प्लेक्स अब किसी भी अच्छे स्तर के खेल आयोजन की मेजबानी करने में सक्षम है। कुछ साल पहले झारखंड के रांची में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए वहां स्पोर्ट्स स्थलों को नया रूप दिया गया था। पुणे ने खेलो इंडिया से पहले टाटा ओपन महाराष्ट्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया था जिसमें दुनिया के नामी टेनिस खिलाड़ी खेलने उतरे थे। इन खेलों की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि युवा खिलाड़ियों को ओलम्पिक की तर्ज पर खेलने और अपना कौशल दिखाने का एक बड़ा मंच मिल रहा है और उनके प्रदर्शन पर बाकायदा गौर किया जा रहा है। इन खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले 10 साल के अभिनव शॉ की उपलब्धि को सभी ने सराहा और उनका प्रदर्शन मीडिया की सुर्खियां बना।

केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ खुद एक खिलाड़ी रहे हैं और 2004 एथेंस ओलम्पिक के रजत पदक विजेता निशानेबाज हैं। खेल मंत्री जानते हैं कि खिलाड़ियों की जरूरतें क्या हो सकती हैं और खेल मंत्री के रूप अपना पदभार संभालते ही उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों को अब फाइलों में नहीं उलझना पड़ेगा। वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश के युवा खिलाड़ी को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलें और उनकी सभी स्टेडियम तक पहुंच हो।

भारत ने जब 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था तब राजधानी के तमाम स्टेडियमों का नवीकरण किया गया था और पिछले नौ वर्षों में इन स्टेडियमों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसा पहले कभी बड़ा आयोजन नहीं हुआ था। हालांकि भारत ने अपनी मेजबानी में 2017 में हुए अंडर 17 फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के छह आयोजन स्थलों कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम, नयी दिल्ली के

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम, गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम और गोवा के मडगांव के फातोरदा स्टेडियम में उल्लेखनीय सुधार किये थे ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतर सकें।

भारतीय संविधान के तहत खेल मुख्यत: राज्य का विषय हैं और खेल आधारभूत ढांचे का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों के पास है और वे उसका प्रबंधन देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) खेल मंत्रालय की तरफ से स्टेडियमों का निर्माण करता है और उनका प्रबंधन देखता है। ये स्टेडियम केंद्र सरकार के तहत आते हैं। केंद्र सरकार अपनी खेलो इंडिया पहल के जरिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों कुछ आधारभूत परियोजनाओं और खेल सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करती है। राज्य सरकारें और अन्य स्थानीय प्रशासन साई के साथ समझौता ज्ञापन कर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने 2018 के अपने बजट में खेलो इंडिया के लिए 575 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

खेल मंत्रालय ने 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (टॉप्स) के तहत 2020 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के लिए उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। खेल मंत्रालय ने टॉप्स को सितंबर 2014 में शुरू किया था और इसका लक्ष्य ओलंपिक के संभावित पदक विजेताओं को तैयारी के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। खेल मंत्री का साफ़ निर्देश है कि टॉप्स में खिलाड़ियों के लिए कोष की कमी नहीं होनी चाहिए।

बुनियादी ढांचा बनाने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। साई ने भारत में ट्रेनिंग सेंटर और हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने के लिए कई अंशधारकों के साथ समझौता किया है। खेल ढांचों के विकास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को प्रयोग में लाया जा रहा है। इससे मौजूदा ढांचों का नवीकरण हो रहा है और उन्हें आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है।

गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों ने अपनी खेल नीति में पीपीपी मॉडल को अपनाया है जबकि अधिकतर राज्य अभी पीपीपी मॉडल से कोसों दूर हैं। पीपीपी का एक सफल उदाहरण नया रायपुर में नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी स्पोर्ट्स सिटी है जिसमें टेनिस, तैराकी सेंटर और एक इंडोर स्टेडियम है। मध्य प्रदेश ने भी स्पोर्ट्स सिटी के विकास का काम शुरू किया है। राजस्थान ने 2015 में पीपीपी को अपनी नीति में शामिल किया था जिसमें सरकारी जमीन पर खेल ढांचा बनाया जाएगा जो सरकार के स्वामित्व में होगा लेकिन इसका संचालन और प्रबंधन निजी क्षेत्र देखेगा। निजी क्षेत्र को इसके लिए फीस लेने की अनुमति होगी।

गुजरात की 2016 की खेल नीति में निजी क्षेत्र की वृहद् भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। कर्नाटक सरकार ने 2018 की अपनी खेल नीति में पीपीपी ढांचे को शामिल किया है। हरियाणा ने 2015 की अपनी खेल नीति में माना है कि पीपीपी मॉडल का अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

पटियाला और ग्वालियर में खेल संस्थान हैं, पुणे और हैदराबाद में पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, अमरावती को विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी के रूप में तैयार करने की योजना है। देश में खेलों में योगदान देने वालों के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड है जिसमें कॉर्पोरेट अपना योगदान दे सकते हैं। इस फंड की स्थापना खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड में 10 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। यह आईआईएफसीएल द्वारा दिए गए योगदान की तीसरी किस्त है, जिससे उसका कुल योगदान 30 करोड़ रुपये हो गया है। इस योगदान का उपयोग बैडमिंटन, तीरंदाजी और पैरा स्पोर्ट्स जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए तथा इनके खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण, अन्य सेवाएं और इससे जुड़े अकादमियों की स्थापना या उनकी सहायता के लिए किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने नारा दिया है- खेलोगे तभी खिलोगे। रियो ओलम्पिक के बाद ही प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया था कि अगले तीन ओलम्पिक के लिए योजना अभी से तैयार करनी शुरू कर देनी चाहिए। यही कारण है कि सरकार युवाओं को खेलों के लिए तैयार करने पर जोर दे रही है और साथ ही वह ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुनना चाहती है जिन्हें साल भर छात्रवृति दी जाए ताकि उन्हें और उनके परिवार को उनके भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी पड़े।

खेल मंत्रालय ने 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (टॉप्स) के तहत 2020 ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के लिए उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। खेल मंत्रालय ने टॉप्स को सितंबर 2014 में शुरू किया था और इसका लक्ष्य ओलंपिक के संभावित पदक विजेताओं को तैयारी के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना है। खेल मंत्री का साफ़ निर्देश है कि टॉप्स में खिलाड़ियों के लिए कोष की कमी नहीं होनी चाहिए।

आज पुराने समय के खिलाड़ियों से पूछा जाए तो वह एक बात बड़ी साफगोई से कहते हैं कि आज देश में खिलाड़ियों को जो खेल सुविधाएं मिल रही हैं वे उनके जमाने में नहीं थीं। राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद कहते हैं: ''भारतीय खिलाड़ियों को अब मूलभूत सुविधाओं के लिए चिंता नहीं करनी पड़ रही है, जिसके लिए उन्हें अपने खेल के दिनों में जूझना पड़ता था।'' ❑

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का सृजन

संजीव कुमार

किसी भी देश की स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को समझने के लिए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन और व्यवस्था के संदर्भ में निवेश संबंधी प्राथमिकताओं का परिचायक है। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं समुचित रूप से उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा प्राथमिक शर्त है। भारत में स्वास्थ्य स्थितियों में प्रणालीबद्ध ढंग से सुधार हुआ है। औसत जीवन की अवधि 1947 के 32 वर्ष से बढ़ कर मौजूदा समय में 66.8 वर्ष यानी लगभग दोगुना हो गया है। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) कम होकर प्रति 1000 जन्म पर 50 रह गया है।

एक अनुमान है कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले व्यय का केवल 22 प्रतिशत सरकारी कोष से मिलता है। शेष 78 प्रतिशत के अधिकांश भाग का व्यय निजी स्रोत से होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कुल सब्सिडी में आबादी के सबसे धनी 20 प्रतिशत का भाग लगभग 31 प्रतिशत है। यह आबादी के सबसे निर्धन 20 प्रतिशत के भाग का लगभग तिगुना है।

स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और ढांचा

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र राजस्व और रोजगार दोनों दृष्टि से देश के सबसे बड़े क्षेत्रों में एक है। स्वास्थ्य देखभाल में अस्पताल, चिकित्सा संयंत्र, चिकित्सकीय परीक्षण, आउट सोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा उपकरण आते हैं। भारत का स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र बढ़ते सरकारी और निजी व्यय तथा अपनी मजबूत सेवाओं के कारण काफी तेज गति से बढ़ रहा है। भारतीय चिकित्सा देखभाल प्रणाली को दो प्रमुख भागों - सार्वजनिक और निजी में

भारत बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं के लिए कृतसंकल्प है। आशा है कि इन तमाम कारगर पहल के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र आने वाले वर्षों में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में होगा और किए गए संकल्पों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा

लेखक वरिष्ठ संचार, शोध और मीडिया प्रोफेशनल हैं और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ईमेल: sanjeevbcc@yahoo.co.in

बांटा जा सकता है। सरकारी यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में प्रमुख शहरों में स्थित चिकित्सा संस्थान तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आती हैं। निजी क्षेत्र अधिकांश द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ श्रेणी के स्वास्थ्य संस्थान उपलब्ध कराते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से महानगरों, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के शहरों पर ध्यान दिया जाता है। भारत की प्रतिस्पर्धी लाभ की स्थिति इसके प्रशिक्षित और कुशल चिकित्सा पेशेवरों में निहित है। एशियाई और पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में चिकित्सा लागत भी काफी कम है। भारत में सर्जरी की लागत अमरीका या पश्चिमी यूरोप की तुलना में 10वां हिस्सा है।

भारत में चिकित्सा शिक्षा बुनियादी ढांचे में पिछले 20 वर्ष के दौरान तेज वृद्धि हुई है। अभी देश में 476 चिकित्सा महाविद्यालय, डेंटल सर्जरी के स्नातक पाठ्यक्रम -बीडीएस के लिए 313 कॉलेज और इसके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम-एमडीएस के लिए 249 कॉलेज हैं। 2017-18 के दौरान 476 मेडिकल कॉलेजों में 52646 तथा बीडीएस पाठ्यक्रम में 27060 और एमडीएस पाठ्यक्रम में 6233 एडमिशन हुए।

31 अक्टूबर 2017 तक नर्स और मिडवाइफ प्रशिक्षण के लिए 3215 संस्थान हैं, जिनमें 1,29,926 लोग प्रवेश ले सकते हैं। फार्मेसी के डिप्लोमा कोर्स के लिए 777 कॉलेज हैं, जिनमें 46795 आवेदकों को प्रवेश देने की क्षमता है। देश में 23582 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें 7,10,761 बिस्तर उपलब्ध हैं। 2,79,588 बिस्तरों के साथ 19810 अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि 4,31,173 बिस्तरों के साथ 3772 अस्पताल शहरी क्षेत्रों में हैं। भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। 31 मार्च तक उनकी चिकित्सा जरूरतों की पूर्ति के लिए 1,56,231 उपकेंद्र, 25650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5624 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत थे।

स्वास्थ्य देखभाल के लिए सर्वव्यापी पहुंच

स्वास्थ्य देखभाल के लिए सर्वव्यापी पहुंच वैश्विक संस्थानों के साथ साथ राष्ट्रीय

सरकारों का भी लक्ष्य रहा है। भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सबके लिए और सभी उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य का सर्वोच्च संभव स्तर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने की नीति अपनाने तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिए बिना किसी वित्तीय अड़चन के सर्वव्यापी पहुंच बनाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोग उन्मूलन के वैश्विक प्रयास के लिए प्रतिबद्धता, उपचार और स्वास्थ्य देखभाल उपायों को मजबूत करने तथा स्वास्थ्य संबंधी नई समस्याओं के समाधान के प्रयासों की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य संबंधी कई सूचकों में भारत की उपलब्धियों ने उसे सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की ओर प्रगति के लिए प्रेरित किया है।

स्वस्थ भारत का निर्माण

आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा पहल

पीएम जन आरोग्य योजना 23 सितंबर, 2018 को शुभारंभ

लगभग 50 करोड़ लोगों को प्रति परिवार

₹5 लाख

तक का व्यापक स्वास्थ्य कवरेज

1.5 लाख

हेल्थ और वेलनेस सेंटर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे

अब तक **41.45 लाख से अधिक** लाभार्थी ई-कार्ड जारी किए गए और **6.95 लाख से अधिक** व्यक्तियों को फ्री इलाज कराया

(31 दिसंबर 2017 तक)

1 जनवरी, 2019 तक

विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल नीति

2018-19 के केंद्रीय बजट में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल नीति आयुष्मान भारत मिशन की घोषणा की गई। यह 10 करोड़ निर्धन और वंचित ग्रामीण परिवारों तक स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा पहुंचाने की नवीनतम पहल है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के तंत्र में भी सुधार के ठोस प्रयास किए गए हैं। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कई योजनाओं, कार्यक्रम और पहल की शुरुआत की गई है।

प्रमुख सरकारी पहलें

भारत सरकार ने भारतीय स्वास्थ्य देखभाल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख उपाय किए हैं। 23 सितंबर, 2018 को सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य प्रति वर्ष 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये (7124.54 डॉलर) का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। अगस्त 2018 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन-आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की। इसमें सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार का योगदान 40:60 के अनुपात में है। पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90:10 का है और केंद्र शासित प्रदेशों में 60:40 का है। केंद्र बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शत-प्रतिशत योगदान करेगा।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का लक्ष्य सुलभ और विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल सेवा की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना तथा देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

पीएमएसएसवाई के दो भाग हैं-

(1) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना।

(2) सरकारी मेडिकल अस्पतालों को उन्नत बनाना।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत देश में एम्स की तरह के 6 संस्थान स्थापित किए गए हैं। बिहार (पटना), छत्तीसगढ़ (रायपुर), मध्य प्रदेश (भोपाल), ओडिशा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर) और उत्तरांचल (ऋषिकेश) में एक-एक संस्थान हैं। प्रत्येक नए संस्थान के लिए स्वीकृत लागत पहले चरण में 820 करोड़ रुपये थी। 620 करोड़ रुपये निर्माण लागत के लिए तथा 200 करोड़ रुपये चिकित्सा उपकरणों की खरीद और ऑपरेशन थिएटर के लिए थी। इस योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों को उन्नत बनाने का भी लक्ष्य है। आरंभ में इस कार्य के लिए अनमानित लागत संशोधित कर 150 करोड़ रुपये (शुरुआती अनुमान 120 करोड़ रुपये से बढ़ाकर) प्रति संस्थान की गई, जिसमें 125 करोड़ रुपये का योगदान केंद्र सरकार का है।

आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)

वर्तमान समय में विश्व के सर्वाधिक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), आयुष्मान भारत देश को अपने स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे में बदलाव का एक अवसर उपलब्ध कराती है। सितंबर 2018 में शुरू की गई पीएमजेएवाई का उद्देश्य देश के सबसे निर्धन 10 करोड़ परिवारों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यह योजना जरूरत मंदों को वे सभी व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है, जिन्हें पिछले कई दशकों में उपलब्ध नहीं कराया जा सका था। हालांकि लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग में कई चुनौतियां हैं : जिनसे निपटने पर यह योजना सबसे ज़्यादा प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल पहल होगी।

समुचित ढंग से लागू किए जाने पर पीएमजेएवाई में देश की स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा प्रणाली में राजकोष पर भारी बोझ डाले बिना व्यापक सुधारों की क्षमता है। केवल सरकारी वित्त पोषण पर अस्पतालों की निर्भरता की अनुपयोगी पुरानी प्रणाली की जगह स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में साझा सिद्धांतों और कम लागत की स्वास्थ्य बीमा योजना के आधार पर निजी और सरकारी संयुक्त प्रयास सही दिशा में उठाया गया कदम है।

कायाकल्प

2 अक्तूबर 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं आबादी के एक बड़े हिस्से की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करने की सामाजिक सुरक्षा का बड़ा तंत्र है। अस्पतालों में साफ सफाई संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी है तथा ये रोगियों और आने वालों को एक सकारात्मक अनुभव देती हैं साथ ही स्वच्छ वातावरण के प्रति अपना दायित्व निभाने को भी प्रोत्साहित करती हैं। स्वास्थ्य देखभाल का पहला सिद्धांत है - स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसलिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी साफ स्वच्छ होनी चाहिए ताकि संक्रमण नियंत्रण सुनिश्चित हो

स्वस्थ भारत का निर्माण

गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित

- 1084 आवश्यक दवाइयां मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत लाई गई, इससे मरीजों को ₹15,000 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों पर सस्ती दवाईयां उपलब्ध। 4635 से अधिक स्टोर से जनसामान्य को 50%–90% की बचत
- AMRIT फार्मेसियों में कैंसर और हृदय संबंधित बीमारियों के लिए दवाईयां बाजार से 60% से 90% कम कीमतों पर मिलती हैं

हृदय संबंधी स्टेंट की कीमत में 85% तक की कमी

घुटने के इम्प्लांटस की कीमत में 69% तक की गिरावट

1 जनवरी, 2019 तक

सके। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए स्वच्छता संबंधी दिशा निर्देश अलग से जारी किए गए हैं। इस प्रयास को और सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण का उच्च स्तर बनाए रखने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को पुरस्कार देने की राष्ट्रीय पहल की है। कायाकल्प नाम से यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने का प्रयास है। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले केंद्रों को पुरस्कृत किया जाता है और कायाकल्प के तहत आगे के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

मौजूदा समय तक कायाकल्प पहल देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों को उत्कृष्ट स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने में सफल रहा है। यह इन स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले लोगों में भरोसा कायम करने का भी माध्यम बन रहा है।

मिशन इन्द्रधनुष

भारत सरकार ने देश में टीके से वंचित रह गए बच्चों के लिए मिशन इन्द्र धनुष की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अब तक टीके से वंचित रह गए या आंशिक रूप से टीका लगवा चुके बच्चों को इसके दायरे में लाना है।

स्वास्थ्य देखभाल में निजी क्षेत्र

उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक फैसले में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को निर्धन रोगियों को निजी अस्पतालों में रेफर करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को निर्धनों के हित में निर्णय बताया गया, जिसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण रोगियों को चिकित्सा देखभाल के क्षेत्र में धनी शहरी रोगियों के समकक्ष लाना है। अब तक केवल शहरी धनी लोग ही ऐसे निजी संस्थानों का फायदा उठाते रहे हैं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि निजी संस्थानों को गरीब रोगियों को निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करानी होगी। इस संबंध में योजना तैयार की जा रही है, जिसमें निजी चिकित्सा उद्योग को निर्धनों के भी उपचार का दायित्व दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय में याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने कुछ निजी अस्पतालों को 10 प्रतिशत दाखिल हो चुके रोगियों और 25 प्रतिशत बाह्य रोगियों का नि:शुल्क उपचार सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया था। ये निर्देश इस आधार पर दिया गया था कि अस्पतालों को निर्माण के लिए भूमि इस हलफनामे पर दी गई थी, जिसके अनुसार वे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नि:शुल्क उपचार के लिए बाध्य हैं। उच्चतम न्यायलय ने दिल्ली सरकार और निजी स्वास्थ्य संस्थानों को साथ मिल कर गरीबों की चिकित्सा सेवा के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। यह निर्देश सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल तक पहुंच के मुद्दे को राज्य सरकारों और निजी चिकित्सा उद्योगों के समन्वय से हल किया जा सकता है।

बाजार का आकार

स्वास्थ्य देखभाल बाजार 2022 तक तिगुना बढ़कर 80 खरब 60 अरब (133.44 अरब डॉलर) का हो सकता है।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार की व्यापक गुंजाइश है। सकल घरेलू उत्पाद में स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाला व्यय का प्रतिशत तेजी से बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 17-18 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी व्यय बढ़कर 1.4 प्रतिशत हो गया है जबकि वित्त वर्ष 13-14 में यह 1.2 प्रतिशत था। सरकार 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को बढ़ा कर सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत पर लाने की योजना बना रही है।

निवेश

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अस्पतालों और निदान केंद्रों में अप्रैल, 2000 से जून, 2018 तक लगभग 5.25 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ।

उपलब्धियां

इस क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :

2017 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन को मंजूरी दी। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है, जिसका उद्देश्य जीवनशैली में बदलाव लाकर कुपोषण का चक्र तोड़ना है।

23 सितंबर 2018 को विश्व की सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य देखभाल योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई।

15 नवंबर, 2017 तक 44 लाख 50 हजार रोगी सुलभ औषधि और सस्ते प्रतिरोपण उपचार -अमृत योजना के तहत लाभान्वित हुए।

15 दिसंबर 2017 को सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाना है।

स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा और सेवा क्षेत्र में सुधार

भारत का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग तेज गति से वृद्धि वाले क्षेत्रों में है। 2020 तक इसके 280 अरब डॉलर का हो जाने की संभावना है। निदान सुविधाओं में भारी पूंजी निवेश के साथ देश उत्तम उपचार और निदान सेवा के प्रमुख केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। इस प्रगति के साथ अधिक आबादी तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना सुगम हो गया है। इसके अलावा देश में चिकित्सा सेवा के उपभोक्ता अपनी स्वास्थ्य देखभाल के प्रति पहले से अधिक जागरूक हो गए हैं।

भारत सरकार ने भारतीय स्वास्थ्य देखभाल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रमुख उपाय किए हैं। 23 सितंबर, 2018 को सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य प्रति वर्ष 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये (7124.54 डॉलर) का स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है।

भारतीय स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र काफी विविध और व्यापक है तथा सेवाप्रदाता और चिकित्सा प्रौद्योगिकी सहित प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की गुंजाइश है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ इस क्षेत्र के व्यवसाय आधुनिकतम तकनीक और रुझानों को तलाशने में लगे हैं, जिससे उनके व्यवसाय पर अनुकूल प्रभाव पड़ सके। भारत में अस्पताल उद्योग के 16-17 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से वित्त वर्ष 2022 तक 80 खरब 60 अरब रुपये (132.84 अरब डॉलर) का हो जाने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2017 में यह केवल 40 खरब (61.79 अरब डॉलर) का था।

भारत के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ भारतीय कंपनियों के एब्रिविएटिड न्यू ड्रग एप्लीकेशन (एएनडीए) हासिल करने की बढ़ती दर पर भी निर्भर करता है। भारत चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के साथ साथ चिकित्सा पर्यटन के लिए भी व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है। स्पष्ट कहा जाए तो देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे में निवेश के व्यापक अवसर हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को ये तीन शर्तें सुनिश्चित करनी चाहिए: विस्तार, समानता और उत्कृष्टता यानी एक्सपैंड-इक्विटी-एक्सिलेंस। पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच के लिए तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। तृतीयक सुविधाएं आबादी के विभिन्न वर्गों तक समान रूप से पहुंचनी चाहिए। नए स्वास्थ्य केंद्रों को तीन स्तर असंतुलन दूर करने होंगे - क्षेत्रीय स्तर पर, विशेषज्ञता के स्तर पर और डॉक्टर-नर्स और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अनुपात के स्तर पर।

भारत बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं के लिए कृतसंकल्प है। आशा है कि इन तमाम कारगर पहल के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र आने वाले वर्षों में उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में होगा और किए गए संकल्पों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। ❑

स्वस्थ भारत का निर्माण

अधिक सुविधाएं, अधिक डॉक्टर

20 नए एम्स–जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं

2017–18 में झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए **3 नए एम्स की घोषणा की गई**

73 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया जा रहा है

परिचालित एम्स में **1675 अस्पताल बिस्तर जोड़े गए**

कुल 92 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है, जिससे 15,354 एमबीबीएस सीटें बढ़ीं

पिछले चार वर्षों में कुल 12,646 पीजी सीटों में वृद्धि हुई है

1 जनवरी, 2019 तक

संदर्भ

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (एनएचपी) 13 संस्करण, केंद्रीय स्वास्थ्य इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 2018
3. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 2018
4. http://pmssy-mohfw.nic.in/
5. गर्ग, शिवानी, भारत में स्वास्थ्य देखभाल नीति-चुनौतियां और उपचार 2018
6. काया कल्प, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का पुनर्रुद्धार, एनएचएसआरसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, 2018

ग्रामीण विकास के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा

नितिन प्रधान

इस बात के पर्याप्त उपाय किये गये हैं जिससे एक स्वस्थ, स्वच्छ और आर्थिक दृष्टि से मजबूत ग्रामीण भारत का विकास हो सके। इसके लिए आवश्यक तमाम बुनियादी ढांचे के विकास का पूरा ध्यान दिया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर बजटीय आवंटन में तेज वृद्धि की है। बीते वित्त वर्ष में 12.85 लाख करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास का बजट रखा गया था जिसे मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में बढ़ाकर 14.34 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। यह इस बात का परिचायक है कि सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत को वास्तव में मजबूत आर्थिक भारत की रीढ़ के रूप में तैयार करने का है

सब जानते हैं कि भारत गांवों में बसता है। इसलिए अगर भारत को विश्व के मानचित्र में सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था के देश के तौर पर स्थापित होना है तो गांवों और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की रफ्तार को तेज करना और उससे सतत बनाये रखना बेहद आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण भारत का बुनियादी ढांचा इतना मजबूत हो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी निरंतर बढ़ती रहे। जिस देश की दो तिहाई से ज्यादा आबादी गांवों में बसती हो और पूरे देश का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी जिन गांवों पर हो उनके लिए यह बेहद आवश्यक है कि वहां मूलभूत आवश्यकताएं पर्याप्त हों। खेती के लिए आवश्यक ढांचा, कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था, गांवों में बिजली की उपलब्धता, रहने के लिए आवास आदि ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेज विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

अर्थव्यवस्था के आंकड़ें बताते हैं कि बीते चार साल में देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। खेती की विकास दर का इस दौरान चार फीसद से ऊपर पहुंचना यह दर्शाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है। क्योंकि अगर खेती के विकास की यह रफ्तार बनी रही तो देश की अर्थव्यवस्था को सालाना आठ फीसद से ऊपर ले जाना मुश्किल काम नहीं होगा। चूंकि कृषि विकास दर आमतौर पर मानसून पर निर्भर करती है इसलिए साल दर साल इसमें उतार-चढ़ाव बना रहता है।

गांवों का विकास मूलतः तीन बातों पर टिका है। पहला सिंचाई की उचित व्यवस्था, ताकि खेती को मानसून पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल, जिससे किसानों को बिना समय नष्ट किए अपनी पैदावार मंडियों और बाजारों तक पहुंचाने की सहूलियत हो और वे अपनी

लेखक दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। ईमेल: pradhnitin@gmail.com

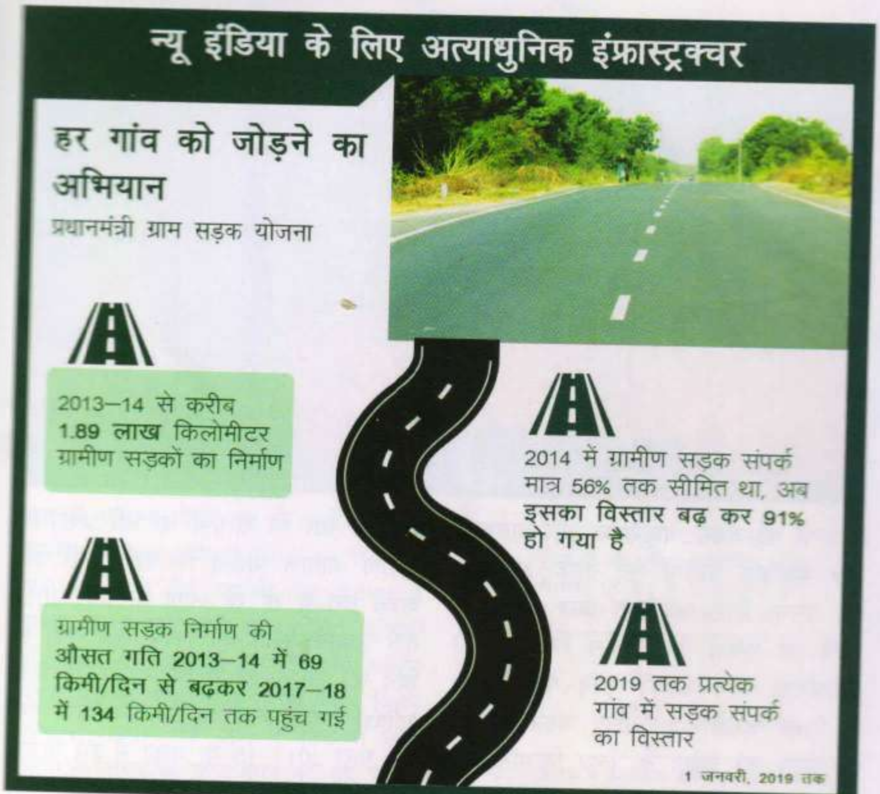

फसल का उचित दाम प्राप्त कर सकें। तीसरा गांवों में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता ताकि ग्रामीण भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास में संतुलन बना रह सके।

सिंचाई के लिए पर्याप्त ढांचा होगा तो किसानों को खेती के लिए हर साल मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ग्रामीण सड़कों का जुड़ाव मुख्य सड़कों के साथ होगा तो किसान मंडी तक पहुंच सकेगा और फसल खराब होने से पहले उसे बाजार में पहुंचा कर उचित दाम प्राप्त कर सकेगा।

ग्रामीण सड़कों का जाल

प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्राम मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होंगे, राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली योजनाओं को लेकर चल रही है। ग्रामीण भारत के विकास को ध्यान में रखकर ही सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के आम बजट में ऐसे कई प्रावधान कर दिये थे जिनका योगदान न केवल गांवों में उपरोक्त तीनों मूलभूत सुविधाओं के विकास में है बल्कि ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे का स्तर भी ऊपर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण भारत को जोड़ने वाली सड़कों के विकास की। सरकार इस काम के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से एक केंद्र पोषित योजना चलाती है। यह योजना पिछली सरकारों के समय से चल रही है। लेकिन मौजूदा सरकार के कार्यकाल में एक बड़ा फर्क यह आया कि सरकार ने इसकी रफ्तार को बढ़ाया है। पहले सरकार इस लक्ष्य को मार्च 2022 तक पूरा करना चाहती थी। लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि इसे मार्च 2019 तक ही प्राप्त कर लिया जाएगा। सरकार का इरादा देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने का है। साल 2014 तक इस योजना के तहत सड़क बनाने की गति 69 किलोमीटर प्रतिदिन थी जिसे अब बढ़ाकर 134 किलोमीटर प्रति दिन तक ले आया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि देश में ग्रामीण सड़कों की लंबाई आज की तारीख में 187808 किलोमीटर हो गई है जो साल 2014 में 86764 किलोमीटर थी। फलस्वरूप 91 फीसद गांवों तक ग्रामीण सड़क की पहुंच हो गई है।

ग्राम सड़क योजना के इस लक्ष्य की प्राप्ति सुगम हो इसके लिए वित्त मंत्री ने इसके लिए 19000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हालांकि इस योजना के तहत बनने वाली सड़कों पर आने वाले खर्च का एक हिस्सा राज्य वहन करते हैं। लेकिन सरकार ने इस योजना के लिए बजटीय राशि में वृद्धि कर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती। अगर केंद्र द्वारा दी जाने वाली बजटीय राशि में राज्यों के अंशदान को भी जोड़ दिया जाए तो साल 2017-18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए कुल 27000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी गई। ग्रामीण विकास में सड़कों के निर्माण के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 44 जिलों में अगले चार वर्ष तक 5411 किलोमीटर सड़कों का निर्माण भी इसी योजना के तहत किया जाएगा। साथ ही इन जिलों में 126 पुलों का निर्माण भी होगा। इन कार्यों पर 11700 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। सरकार की स्पष्ट अवधारणा है कि इन क्षेत्रों में विकास का मूल जरिया ये सड़कें ही बनेंगी।

विद्युतीकरण

ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है गांवों का विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण इस सरकार के लिए प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर चलायी जा रही दीनदयाल उपाध्याय योजना के बजट आवंटन को सरकार ने 44 फीसदी बढ़ाया। आवंटन राशि में हुई इस वृद्धि के स्पष्ट नतीजे दिखायी दिए हैं। मौजूदा सरकार ने लक्ष्य से पहले शेष बचे 18374 गांवों तक बिजली पहुंचा कर देश के 100 फीसद गांवों में विद्युतीकरण की उपलब्धि को प्राप्त कर लिया। इस योजना के तहत 120804 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। जाहिर है गांवों में बिजली पहुंचने का सीधा असर गांव के पूर्ण विकास पर पड़ेगा और सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता किसान की आय को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी।

सिंचाई

ग्रामीण क्षेत्र का विकास पूरी तरह किसानों की कृषि आय पर निर्भर करता है। सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलें। गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास में सिंचाई की व्यवस्था इसमें सबसे अहम है। बिना सिंचाई के साधनों के किसानों की आय में बढ़ोतरी का विचार नहीं किया जा सकता। यह सही है कि किसानों को डेयरी, पशुपालन और बागबानी जैसे सहायक उद्योगों की तरफ आकर्षित कर उनके लिए अतिरिक्त आय के उपाय किये जा सकते हैं। लेकिन किसानों की वास्तविक आय उनकी कृषि पैदावार पर ही निर्भर करती है। इसलिए जरूरी है कि इस आय को बढ़ाने के लिए किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जाएं। इसके महत्व को समझते हुए ही वित्त मंत्री ने सिंचाई के बजटीय आवंटन को बढ़ाकर 40000 करोड़ रुपये किया गया है। इसी तरह वाटरशेड कृषि सिंचाई योजना के लिए भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2310 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गए।

ग्रामीण आवास

इसी तरह ग्रामीण भारत की एक बुनियादी जरूरत आवास है। इसके तहत केंद्र के स्तर पर चलायी जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों के लिए 2019 तक मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2016-17 में इस योजना के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। साल 2017-18 के बजट में इस योजना के बजटीय आवंटन को 53 फीसद बढ़ाकर 23000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। नतीजा यह हुआ है कि सरकार आज की तारीख में 1.35 करोड़ ग्रामीण आवास का निर्माण करने में सफल हो सकी है।

इस बात के पर्याप्त उपाय किये गये हैं जिससे एक स्वस्थ, स्वच्छ और आर्थिक दृष्टि से मजबूत ग्रामीण भारत का विकास हो सके। इसके लिए आवश्यक तमाम बुनियादी ढांचे के विकास का पूरा ध्यान दिया गया है। वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर बजटीय आवंटन में तेज वृद्धि की है। बीते वित्त वर्ष में 12.85 लाख करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास का बजट रखा गया था जिसे मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में बढ़ाकर 14. 34 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। यह इस बात का परिचायक है कि सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत को वास्तव में मजबूत आर्थिक भारत की रीढ़ के रूप में तैयार करने का है। ❑

स्वच्छ भारत मिशन : खुले में शौच से मुक्त भारत के लक्ष्य प्राप्ति की ओर

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 5.4 लाख से अधिक गांव और 585 जिले खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किए गए हैं। अब तक 27 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। ग्रामीण भारत में 9 करोड़ से ऊपर शौचालय बनाए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता कवरेज आज 98 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जबकि यह 2014 में 38.70 प्रतिशत था। इस प्रगति का सत्यापन स्वतंत्र रूप से व्यापक तीसरे पक्ष के राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2017-18 में किया गया है। विश्व बैंक समर्थित यह सर्वेक्षण 6 हजार से अधिक गांवों के 90,000 परिवारों में किया गया। इसमें ग्रामीण शौचालय उपयोग 93.4 प्रतिशत पाया गया। स्वच्छ भारत मिशन अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है।

स्वच्छता क्रांति शुरू करना सरकार की कार्यसूची में प्रमुखता से शामिल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान (एसबीएम) 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था, जिसका मकसद भारत में स्वच्छता के दायरे को व्यापक करना और इसकी उपलब्धता को बढ़ावा देना था।

आदर्श स्वच्छ ठिकाने (एसआईपी)

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से एमडब्ल्यूएस ने देशभर के 100 ठिकानों पर बहुपक्षीय अभियान चलाया है, जिसका फोकस स्वच्छता पर है। ये ठिकाने अपनी विरासत, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण 'प्रतिष्ठित' हैं। अब तक पहले तीन चरणों में 30 प्रतिष्ठित ठिकानों की पहचान की गई है।

महिलाओं के नेतृत्व में विकास

नमामि गंगे

नमामि गंगे कार्यक्रम जल संसाधन मंत्रालय की पहल है। अंतर-मंत्रालय पहल के तहत गंगा नदी के तट पर गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा रहा है एवं ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के तहत पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 52 जिलों में मौजूद 4,470 गांवों को राज्य सरकारों की सक्रिय मदद से खुले में शौच से मुक्त किया गया है।

पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय ने करनाल, हरियाणा में 30 अप्रैल 2018 को 'गोबर्द्धन' योजना शुरू की। इस योजना का मकसद गांवों को स्वच्छ रखना और गाय के गोबर और अन्य जैविक संसाधनों को बायोगैस और जैविक खाद में बदलकर किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

स्वजल

स्वच्छता और पेय जल मंत्रालय ने नीति आयोग द्वारा चिन्हित किए गए 117 संभावनाशील जिलों के लिए समुदाय मांग आधारित, विकेंद्रित, एक गांव वाली, प्रमुख रूप से सौर ऊर्जा से संचालित मिनी पीडब्ल्यूएस कार्यक्रम शुरू किया है। माननीय उपराष्ट्रपति ने 27 सितंबर 2018 को झारखंड में इस योजना की आधारशिला रखी और 19 नवंबर 2018 की पहली योजना का उद्घाटन विश्व शौचालय दिवस के मौके पर झारखंड के हजारीबाग में किया गया। ❑

(स्रोत : प्रेस सूचना ब्यूरो, एसबीएम वेबसाइट)

नोट : स्वच्छता कवरेज एमआईएस पर रिपोर्ट की गई घरों की सूचना पर आधारित है।

स्रोत : एसबीएम वेबसाइट

शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार की नई पहलें

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई नई पहलें कीं।

- सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं।
- शिक्षा क्षेत्र को सुगम, गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, सभी के लिए समानतापूर्ण और किफायती बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए हैं और साथ ही शोध एवं नवाचार को बढ़ावा दिया गया है।
- नई पहल 'लर्निंग आउटकम्स' (या सीखने के परिणाम) हर साल हर विषय और कक्षा में विद्यार्थी द्वारा हासिल की गई क्षमताओं का एक बेंचमार्क है। इससे विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों में विश्वसनीयता आएगी, साथ ही अभिभावक विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकेंगे।

सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध

शिक्षा के माध्यम से समग्र समाज का सशक्तिकरण

- मेधावी छात्रों के दैनिक भत्ते की राशि 150 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दी गई और छात्रावास में रहने वाले मेधावी छात्रों के लिए दैनिक भत्ते की राशि 350 रुपये से बढ़ाकर 525 रुपये कर दी गई
- एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की फ्री–कोचिंग के लिए वार्षिक आय की पात्रता 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई
- स्थानीय छात्रों के लिए भत्ता 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया
- बाहर से आने वाले छात्रों के लिए भत्ते की रकम 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई

*23 अगस्त, 2018 तक

सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध

शिक्षा से सशक्तिकरण

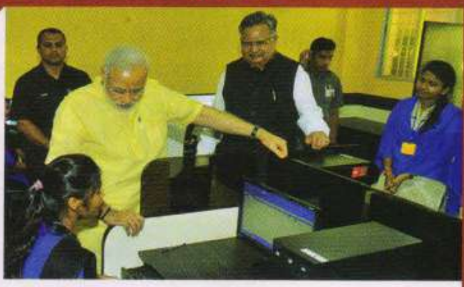

- 2.29 करोड़ एससी छात्रों ने 2014–18 के दौरान 10, 388 करोड़ रुपये की पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठाया
- ओबीसी वर्ग के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय की पात्रता 44,500 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये वार्षिक की गई
- एससी वर्ग के छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति की वार्षिक आय की पात्रता 2 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये वार्षिक की गई

*23 अगस्त, 2018 तक

- मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान 103 नए केंद्रीय विद्यालय और 62 नए नवोदय विद्यालय खोले गए हैं।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण के तहत कक्षा 3, 5 और 8 के 22 लाख विद्यार्थी और कक्षा 10 के 15 लाख विद्यार्थियों का इस सर्वेक्षण में मूल्यांकन किया गया जिसमें हर जिले और राज्य का शिक्षा से संबंधित विवरण मुख्यमंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों के साथ साझा कर दिया गया है।
- नो–डिटेंशन (अवरोध रहित) नीति के अंतर्गत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2017 को संसद में पहले ही पेश किया जा चुका है और प्रस्तावित संशोधन के तहत राज्यों को कक्षा 5 और 8 में विद्यार्थियों की परीक्षा करानी होगी। यदि एक विद्यार्थी दूसरे प्रयास में भी असफल रहता है तो वह पढ़ाई जारी रख सकता/सकती है। इससे

विद्यार्थी की पढ़ाई जारी रहेगी और उसके प्रदर्शन में सुधार होगा।

- सरकार पाठ्यक्रम को दुरुस्त करने का काम भी कर रही है और उसे पाठ्यक्रम में कमी लाने के लिए 37 हजार सुझाव मिल चुके हैं। मूल्यवान शिक्षा, अनुभव से युक्त पढ़ाई, जीवन कौशल शिक्षा, रचनात्मक कौशल और शारीरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत।
- समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक साल बजट में 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाएगी।
- प्रत्येक दिन 11.4 विद्यालयों में 9.5 करोड़ बच्चों को ताजा खाना परोसा जाता है, जिस पर प्रति वर्ष 17,000 करोड़ रुपये की लागत आती है। केंद्र सरकार खाने, परिवहन लागत, खाने को पौष्टिक बनाने के लिए ज्यादा धनराशि के आवंटन के माध्यम से कार्यक्रम को मजबूत बना रही है।
- उच्च शिक्षा के मोर्चे पर मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान 141 विश्वविद्यालय, 14 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 7 आईआईटी और 1 एनआईटी खोले गये हैं। 'शिक्षा में बुनियादी ढांचा और प्रणालियों को 2022 तक पुनर्जीवित करने' की पहल के तहत इसका क्रियान्वयन किया गया है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता की ओर ध्यान देते हुए आईआईएम विधेयक पारित कर दिया गया है, वहीं 60 से ज्यादा विश्वविद्यालयों को ग्रेड आधारित स्वायत्तता दी गई है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के अंतर्गत बजट को तीन गुना बढ़ा दिया गया है। शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से की गई एक अन्य पहल ज्ञान-शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल की जा रही है।
- उत्कृष्टता और रैंकिंग से संबंधित एनआईआरएफ-राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क लगातार तीसरे साल सफलतापूर्वक पूर्ण हुए। यह संस्थानों के बीच गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा की भावना से युक्त एक बेंचमार्क बन गया है। इसमें 4,500 से ज्यादा संस्थानों ने हिस्सा लिया है।
- डिजिटल पहल के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ संकायों के द्वारा 1,032 कोर्स के साथ स्वयं पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस परस्पर संवादात्मक शिक्षा कार्यक्रम का लाभ 20 लाख से ज्यादा उपयोगकर्ता उठा रहे हैं।
- राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के अंतर्गत 1.7 करोड़ डिजिटल पुस्तकें और पत्रिकाओं का ऑनलाइन पुस्तकालय उपलब्ध कराया गया है।
- नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के अंतर्गत प्रमाण पत्रों और डिग्रियों के इलेक्ट्रॉनिक भंडारण की सुविधा शुरू की गई है।
- सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाई- फाई की सुविधा शुरू की गई है। लगभग 400 विश्वविद्यालय परिसर और 10,000 महाविद्यालय वाई-फाई की सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं।
- इम्प्रिंट-1 और 2 के साथ शोध और नवाचार की पहलों का शुभारंभ हुआ। इस पहल के अंतर्गत सामाजिक महत्व के मुद्दों पर शोध परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण की शुरुआत की गई है। 323 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ❑

(स्रोत : प्रेस सूचना ब्यूरो, जू.'18-प्रे.वि.)

राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019

युवा कार्य एवं खेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने 12 जनवरी 2019 को दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का शुभारंभ किया और इसके साथ ही राष्ट्रीय युवा दिवस 2019 के जलसे की शुरुआत हो गई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसंबर 2017 को अपने 'मन की बात' संबोधन में देश के हर जिले में युवा लोगों की युवा संसदों को आयोजित करने के विचार को साझा किया था। ये इसलिए ताकि 2022 से पहले हमारे संकल्पों को साकार करने के रास्ते ढूंढ़ने और योजना बनाने और नए भारत के बारे में मंथन करने के लिए युवाओं को मौका मुहैया करवाया जा सके। उन्होंने 12 जनवरी 2018 को 22वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान युवाओं को दिए अपने संबोधन में, युवाओं की आवाज को पहचानने के अपने विचार को दोहराया।

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय का ये प्रण है कि वो इस युवा महोत्सव को देश के हर जिले में लेकर जाएगा और इसे 'राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव' के तौर पर मनाएगा। जिला युवा संसदों को आयोजित करने और इस महोत्सव को युवाओं के दरवाजे तक ले जाने से देश में बड़ी संख्या में युवाओं को हिस्सा लेने का अवसर मुहैया करवाया जा सकेगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 को "नए भारत की आवाज़ बनो'' और "उपाय ढूंढो और नीति में योगदान करो'' की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। जिला युवा संसदों में हिस्सा लेने के लिए 18 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं को आमंत्रित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस आयु वर्ग के युवाओं की आवाज को सुना जा सके जिन्हें मतदान करने का अधिकार तो है लेकिन चुनाव लड़ने का नहीं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव युवाओं को प्रोत्साहित करेगी कि वे जनता के मुद्दों से जुड़ें, आम आदमी के नजरिए को समझें, इस पर अपनी राय बनाएं और एक स्पष्ट ढंग से उसे अभिव्यक्त करें। ऐसा अनुमान है कि सभी स्तरों पर युवा संसदों के माध्यम से 50 हजार युवा हिस्सा लेंगे और इनकी आवाजों, विचारों और सुझावों से ये रिवायत मजबूत होगी और ज्यादा जीवंत होगी। ❑

(स्रोत : प्रेस सूचना ब्यूरो)

2500 ईयर्स ऑफ बुद्धिज़्म

संपादन : पी. वी. बापट
पृष्ठ : 424, नौवां संस्करण : 2018
प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

यह किताब बौद्ध धर्म की उन मान्यताओं, दर्शन और कला से संबंधित पहलुओं के बारे में विस्तार से बताती है, जो पिछले 2500 साल में विकसित हुई हैं। इस किताब की प्रस्तावना दुनिया भर में मशहूर दार्शनिक डॉ. राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई है। इस किताब में 16 अध्याय हैं और तकरीबन 100 लेख भारत, चीन, जापान, श्रीलंका और नेपाल के बौद्ध धर्म से जुड़े विद्वानों ने लिखे हैं।

बौद्ध दर्शन जीवन जीने का तरीका है। यह मन, वचन और कर्म में शुद्धता की बात करता है। यह किताब न सिर्फ भारत में बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी देती है, बल्कि पूरब के अन्य देशों में इस धर्म को लेकर सूचनाएं मुहैया कराती है। इस किताब में बौद्ध दर्शन के अलग-अलग मतों और विचारों का भी जिक्र किया गया है। शिक्षा पर बौद्ध धर्म के विचार और प्राचीन काल में चीनी तीर्थ यात्रियों ने बौद्ध धर्म को लेकर जो विवरण पेश किया है, उसके बारे में भी किताब में बताया गया है। भारत और विदेश में मौजूद बौद्ध कलाओं पर आधारित अध्यायों को भी इस किताब में शामिल किया गया है, ताकि बौद्ध दर्शन से जुड़ी जानकारियों के बारे में समग्र नजरिया दिया जा सके। इन अध्यायों को बौद्ध धर्म के विद्वानों ने लिखा है, जिनमें बौद्ध जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं पर सूचना और विश्लेषण मुहैया कराया गया है। किताब में वर्णित ऐतिहासिक पहलुओं के तहत चार बौद्ध परिषद और सम्राट अशोक और उनके बाद के शासनकाल में बौद्ध धर्म के फैलाव के बारे में जानकारी दी गई है। साथ पूरे दक्षिण, दक्षिण पूर्व और मध्य एशिया में फैले बुद्ध के विचारों के बारे में ब्यौरा दिया गया है।

यह किताब बौद्ध धर्म की अलग-अलग धाराओं और मतों के बारे में गहन विश्लेषण पेश करती है। इसमें महावस्तु से लेकर पिटक तक तमाम बौद्ध साहित्य की झलक पेश की गई है। इसके अलावा, भारत और अन्य देशों के प्रमुख बौद्ध विद्वानों को लेकर भी दिलचस्प अध्याय हैं।

चीनी यात्रियों और उनकी यात्राओं के लिए प्रेरणादायक यात्रा, बौद्ध कला और इससे जुड़ी अन्य चीजों के बारे में जानकारी इस किताब को काफी दिलचस्प बनाती है। बौद्ध धर्म में बाद में हुए बदलाव और समकालीन अध्ययनों को भी इस किताब के दायरे में समेटा गया है। संक्षेप में कहें तो यह खंड बौद्ध दर्शन के सभी विद्वानों और छात्रों के लिए 'जरूर पढ़ा जाने वाला' शोध ग्रंथ है।

बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने पर पहली बार 1956 में प्रकाशित इस किताब का मौजूदा संस्करण हाल में पेश किया गया है। दरअसल, इस किताब को हाल में 'भारत-एक परिचय कार्यक्रम' के तहत विदेश मंत्रालय ने भारतीय मिशन और पुस्तकालयों के लिए चुना है, जिसके बाद इसका ताजा संस्करण पेश किया गया।

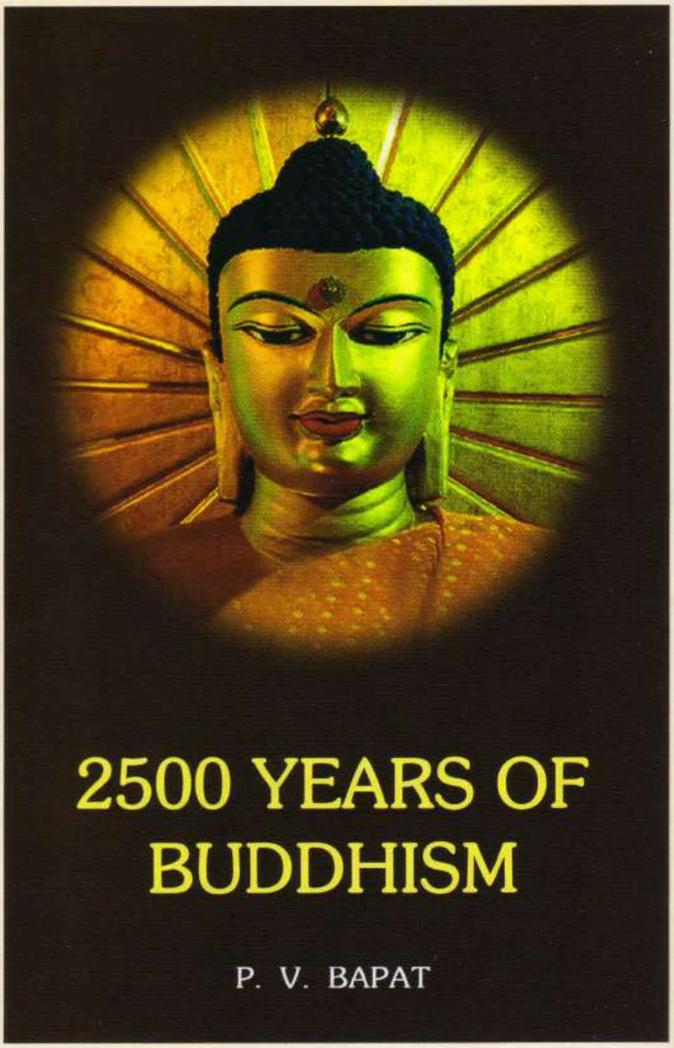

इस किताब में बुद्ध का दर्शन जीवंत हो जाता है और पाठकों को उनके ज्ञान से आलोकित होने का अवसर मिलता है।

यह किताब पुस्तक दीर्घा, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में उपलब्ध है। किताब की अपनी प्रति ऑर्डर करने के लिए इस पते पर मेल करें- businesswng@gmail.com. ❑

विश्व पुस्तक मेले, 2019 में प्रकाशन विभाग

नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5 से 13 जनवरी, 2019 के बीच आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मीडिया एकक प्रकाशन विभाग ने भी हिस्सेदारी की। विश्व पुस्तक मेले के पहले दिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे ने प्रकाशन विभाग की तरफ से प्रकाशित 7 पुस्तकों का लोकार्पण किया। सचिव ने बताया कि प्रकाशन विभाग न सिर्फ देशभर में अच्छे लेखकों को मौका देता है, बल्कि विदेश में भी भारतीय साहित्य के प्रसार में मदद करता है।

सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे ने 5 जनवरी 2019 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रकाशन विभाग की किताबों का लोकार्पण किया।

इस अवसर पर जिन पुस्तकों का लोकार्पण किया गया, वे हैं- 2500 ईयर्स ऑफ बुद्धिज्म, बापू के आशीर्वाद, पोर्ट्रेट्स ऑफ स्ट्रेंथ, हिंदी स्वेदश में और विदेश में, रंग बिरंगी कहानियां, बादल की सैर तथा आओ पर्यावरण को बचाएं और धरा को स्वर्ग बनाएं।

इस मौके पर राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय की पूर्व निदेशक वर्षा दास, सस्ता साहित्य मंडल की सचिव डॉ रीता रानी पालीवाल, प्रकाशन विभाग की महानिदेशक डॉ साधना राउत और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

प्रकाशन विभाग ने विश्व पुस्तक मेले में 10 जनवरी, 2019 को 'बाल साहित्य और इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स में उलझे बाल पाठक' विषय पर परिचर्चा का भी आयोजन किया। इस परिचर्चा में किताबों के महत्व और बच्चों पर उनके प्रभाव पर चर्चा हुई, जो आज के दौर में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यस्त रहते हैं। इस अवसर पर भी 10 किताबों का लोकार्पण किया गया। ये पुस्तकें हैं- सरल पंचतंत्र भाग-1; चिल्ड्रेन्स विवेकानंद; चिल्ड्रेन्स महाभारत इन इंग्लिश; शेखावटी की लोक संस्कृति; हमारे समय में उपनिषद; मां का जन्मदिन; बापू की वाणी; वेद गाथा और हिंदी में बाल महाभारत। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के सदस्य सचिव डॉ सच्चिदानंद जोशी मुख्य अतिथि थे।

पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। विभाग की चुनिंदा किताबों पर विशेष छूट की योजना को लोगों द्वारा काफी सराहा गया। लोगों ने इस अवसर का उपयोग कला और संस्कृति, आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला, बच्चों के साहित्य, इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम आदि पर किताबें खरीदने में किया। इस दौरान किताब खरीदने के लिए डिजिटल भुगतान की सुविधा भी मुहैया कराई गई और लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से इसका फायदा उठाया। ❑